दशम माला, खण्ड 29, अंक 17

शनिवार, 19 मार्च 1994
28 फाल्गुन, 1915 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

नवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. 52
Date 6-10-95

(खंड 29 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय सूची

दशम माला, खंड 29, नवां सत्र, 1994/1915 (शक)

अंक 17, शनिवार, 19 मार्च, 1994/28 फाल्गुन, 1915 (शक)

विषय	पृष्ठ
मंत्री द्वारा वक्तव्य	1
पूर्व ओलम्पियन और अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री जगजीत सिंह की करूणाजनक स्थिति श्री मुकुल वासनिक	1
सभा पटल पर रखे गए पत्र	10
राज्य सभा से संदेश	10
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर पोलावरम बहु-उद्देश्यीय सिंचाई परियोजना को केन्द्रीय योजनाओं में सम्मिलित करने की आवश्यकता श्री रामकृष्ण कोंताला	11
(दो) मध्य प्रदेश में सिहोरा तहसील के सिहोरा कस्बे के निकट हरगढ़ में एक उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता श्री श्रवण कुमार पटेल	11

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

(तीन) पूर्वी भारत के आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे उद्योगों में आदिवासी युवकों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण देने हेतु वहां तकनीकी संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता 12

कुमारी फ्रिडा तोपनी

(चार) सामान्य श्रेणी के टिकट धारकों को दिन के समय रेलगाड़ियों में द्वितीय श्रेणी के आरक्षित डिब्बों में यात्रा करने की अनुमति देने की आवश्यकता 12

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)

(पांच) भुवनेश्वर उड़ीसा में भारतीय जीवन बीमा निगम का एक मंडलीय कार्यालय खोलने कीआवश्यकता 13

श्री शिवाजी पटनायक

(छ:) रबड़ उत्पादकों के हितों की रक्षा हेतु रबड़ के बेहतर उपयोग के तरीके निकालने की आवश्यकता 13

श्री पी.सी. थामस

(सात) कानपुर, उत्तर प्रदेश को वायु सेवा द्वारा देश के अन्य महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ने की आवश्यकता 13

श्री जगत वीर सिंह द्रोण

सामान्य बजट 1994-95 सामान्य चर्चा जारी

श्री निर्मल कांति चटर्जी 14

प्रो. रीता वर्मा 25

श्रीमती गीता मुखर्जी 30

श्री चिरंजी लाल शर्मा 35

श्री राजेश कुमार 39

श्री उदयसिंह राव गायकवाड़	43
श्री गिरधारी लाल भार्गव	45
प्रो. पी.जे. कुरियन	47
श्री तेज नारायण सिंह	53
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर	56
श्री सत्यनारायण जटिया	60
श्री सूर्य नारायण यादव	67
श्री चित्त बसु	69
श्री दत्ता मेघे	73
श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा	76
श्री मनोरंजन भक्त	78
श्री मुमताज अंसारी	82

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

नियम 331 छ (क) का निलम्बन	24

लोक सभा

शनिवार, 19 मार्च 1994/28 फाल्गुन, 1915 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मध्यावकाश से पूर्व आज अन्तिम दिन है। ....
(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक बहुत ही योग्य संसदविद् के रूप में आप और कुछ नहीं सिर्फ बजट पर ही चर्चा करने जा रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : आप जीरों आवर 10-15 मिनट चलाइए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, फिर श्री अन्ना जोशी जी से प्रारंभ करते हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, कुछ दिन पहले श्री असलम शेर खां द्वारा एक भूतपूर्व ओलिम्पिक खिलाड़ी से सम्बन्धित मुद्दा उठाया गया था। मैं उस पर केवल एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, सभा उस बारे में जानना चाहती है।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

11.02 म०पू०

पूर्व ओलम्पियन और अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री जगजीत सिंह की करूणाजनक स्थिति

16.3.94 को श्री असलम शेर खान ने श्री जगजीत सिंह, भूतपूर्व ओलम्पिक खिलाड़ी और अर्जुन पुरस्कार विजेता की दयनीय दशा के बारे में मामला उठाया था जैसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था।

मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि श्री जगजीत सिंह गांव संसारपुर, जिला जलन्धर (पंजाब) में निवास

कर रहे है और वे भारतीय दल के सदस्य थे जिन्होंने तोक्यो में आयोजित 1964 ओलम्पिक में स्वर्ण पदक तथा मेक्सिको सिटी में आयोजित 1968 ओलम्पिक में कांस्य पदक जीता था। वे उस भारतीय हाकी टीम के सदस्य भी थे जिसने 1966 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। उनकी खेल उपलब्धियों की मान्यता में भारत सरकार ने उन्हे वर्ष 1967 में अर्जुन पुरस्कार से अंलकृत किया था।

यह पता लगा है कि श्री जगजीत सिंह एन.आई.एस. प्रशिक्षक के रूप में अर्हता प्राप्त है तथा उन्होंने पहले पंजाब पुलिस और सीमा सुरक्षा बल में सेवा की है। 1974 में उन्होंने सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला में ग्रेड-II प्रशिक्षक के रूप में कार्यभार संभाला था परंतु 1976 में उन्होंने इस सेवा को छोड़ दिया था। उसके पश्चात् उन्होंने प्रादेशिक सेना में कार्यभार संभाल लिया था परन्तु यह नौकरी भी उन्होंने छोड़ दी। श्री जगजीत सिंह इस समय बेरोजगार हैं।

मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि हाल ही में युवा कार्यक्रम और खेल विभाग ने "उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिय पैंशन हेतु खेल निधि" की योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना का उद्देश्य ओलम्पिक खेलों और एशियाई खेलों जैसी अभिज्ञात अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनके उल्लेखनीय प्रदर्शन की मान्यता में खिलाड़ियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।

वे खिलाड़ी जिन्होंने ओलम्पिक खेलों में स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक अथवा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते हैं पैंशन पाने के लिए पात्र हैं। जबकि ओलम्पिक खेलों में पदक विजेता 2000/- रूपये प्रति मास और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता 1500/- रूपये प्रति मास की दर से आजीवन पेंशन प्राप्त करेंगे। श्री जगजीत सिंह भी इस योजना में आते हैं और वे 2000/- रूपये प्रति मास की दर से पेंशन प्राप्त करेंगे। मैंने अपने अधिकारियों को सभी औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया है ताकि श्री जगजीत सिंह को शीघ्रताशीघ्र पैंशन स्वीकृत की जा सके। जब तक ऐसी औपचारिकताएं पूरी नहीं होती हैं, मैंने आदेश दिए हैं कि खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि में से उन्हें 2000/- रूपये की मासिक पैंशन दी जाए। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह कब से प्रभावी होता है?

श्री मुकुल वासनिक : यह बीते दिनों से नहीं बल्कि अब से ही लागू होता है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपने जो कार्य किया है सभा उसकी सराहना करती है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने बताया कि दो हजार रूपये महीने की पेंशन देना तय किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किस तारीख से पेन्शन देना शुरू कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय : उसको डायल्युट मत कीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने जो कार्य किया है, मंत्रालय तथा सरकार ने जो कार्य किया है, सभा उसकी सराहना करती है।

(व्यवधान)

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : महोदय, शून्य काल के दौरान में जनहित का निम्न मुद्दा उठाना चाहूंगा।

हाल ही में पाकिस्तान के एक व्यक्ति श्री सादिल हुसैन ने **"तवारिख-के-मुजाहिद"** नामक एक पुस्तक लिखी और प्रकाशित करायी है जिसमें उन्होंने सिख सम्प्रदाय के धार्मिक नेताओं को चोर और लुटेरा कहा है। यह अत्यधिक अपमानजनक और शर्मनाक मामला है। चूंकि हमारी राष्ट्रीय अखंडता, प्रभुसत्ता और संस्कृति की रक्षा हेतु किये गए संघर्ष में सिख गुरूओं की वीरता, त्याग तथा राष्ट्रभक्ति से हम अवगत है।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस कार्यवाही की भर्त्सना करते हुए एक वक्तव्य जारी किया जाए तथा भारत में इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया जाए।

मैं यह भी कहता हूं कि पाकिस्तान ने अपने सभी प्रान्तों तथा अन्य जगहों में इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया है। अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि उन्हें भी इस मामले में कार्यवाही करनी चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : महोदय, मैंने पहले भी इस मुद्दे को सभा में उठाया था। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सरकार को इस मुद्दे की जांच करने दीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, 29 जनवरी को एक समाचार प्रकाशित हुआ था। सरकार तथा राजनीतिक दलों के नेताओं, जिनके नामों का उल्लेख किया गया था, ने इसका खंडन नहीं किया है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक डायरी प्राप्त की है जिसमें यह देखा गया है कि आई०एस०आई० जो हमारे देश में सक्रिय है, द्वारा हमारे कुछ राजनैतिक नेताओं को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मुझे इसका लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आशा करता हूं यह आत्मदंड नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, वे विभिन्न दलों से सम्बन्धित है। यह बहुत ही गंभीर मामला है। लगभग 20 राजनीतिज्ञों पर धनराशि लेने का आरोप लगाया गया था। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैंने सूचना दी है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कुछ ऐसे मामलें होते हैं जिन्हें सरसरी तौर पर नहीं उठाया जाना चाहिए कुछ ऐसे मामले हैं जिनके सम्बंध में आपको कुछ जानकारी है और यदि आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप ऐसे मामले उठा सकते हैं। अन्यथा हम ऐसा कार्य क्यों करें?

श्री बसुदेव आचार्य : मुझे जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप जिम्मेदारी लेते है?

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : उनमें से किसी ने भी इसका खंडन नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : इसका खंडन किसे करना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसका खंडन करेंगे ?

श्री बसुदेव आचार्य : सरकार को इसका खंडन करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि मैं ऐसा कहता हूं तो आपकी बात बिलकुल ठीक है। बिना किसी गंभीरता के कोई भी मुद्दा नहीं उठाया जाना चाहिए। परंतु यह एक परेशानी वाली बात है क्योंकि विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के आरोप लगाये गये हैं जो कि समग्र रूप से राजनीतिज्ञों के नाम को, उनकी भाईचारे की भावना को बदनाम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, जब आप यह बात कहते है तो मैं आपके साथ हूं। इस पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। यदि आप सोचते हैं कि इसमें कोई तथ्य है तो मैं आपको यह मुद्दा उठाने की अनुमति दूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : व्यक्तिगत रूप से मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि यह रिपोर्ट सही नहीं है। परंतु किसी को यह उम्मीद होगी कि इस देश के राजनीतिक जीवन में ये अत्यंत सम्माननीय नाम हैं। उन्हें इस पर आपत्ति करनी चाहिए तथा इसका विरोध करना चाहिए। अत: इस मामले में सरकार द्वारा छान-बीन किया जाना उचित होगा यद्यपि कि ऐसा समझा जाता है कि उनमें से कुछ व्यक्ति इस मामलें में शामिल हैं। हम यही बात कह रहे हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (दिवगढ़) : अध्यक्ष महोदय, अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले को उठाने हेतु मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर तथा कोणार्क में सूर्य मंदिर संपूर्ण देश के अत्यंत महत्वपूर्ण स्मारक है।

अध्यक्ष महोदय : ये सांस्कृतिक सम्पत्ति भी है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : सिर्फ दिल्ली से ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत तथा विदेशों से भी हजारों तीर्थयात्री तथा पर्यटक इन मंदिरों में आते हैं। 1000 वर्ष पुराने ये मंदिर अब असुरक्षित अवस्था में है और कभी-कभी इनकी छतों से पत्थर गिरते हैं। हाल ही में पुरी के मौसिमा मंदिर में इस प्रकार की ही एक दुर्घटना हो गयी थी। इससे दो तीर्थयात्रियों को चोट लगने वाली थी। वे बाल-बाल बच गए। इसी कारण पुरातत्व विभाग द्वारा शीघ्र ही पुरी में जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क में सूर्य मंदिर तथा मौसिमा मंदिर के परिसर की भी तथा इन मंदिरों की इमारत की सुरक्षा सम्बंधी जांच की जानी चाहिए। सभी सुधारात्मक उपाय, मरम्मत कार्य आदि अविलम्ब शुरू किए जाने चाहिए।

पुरातत्व विभाग द्वारा पुरी मंदिर में कुछ कार्य आरंभ किया गया है। परंतु यह कार्य बहुत ही धीरे-धीरे चल रहा है। इसमें तेजी लाई जानी चाहिए। आपके माध्यम से मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि इस इस मामले पर ध्यान दे तथा जहां तक इन स्मारकों का सम्बन्ध है प्राथमिकता के आधार पर कोई कार्यवाही की जाए।

श्री बी. एन. रेड्डी (मिरयालगुडा) : महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से दो सिचाई परियोजनाओं का जवाब प्राप्त करना चाहता हूं। मैने एक सूचना दी है। यहां अकाल की स्थिति लम्बे समय से बनी हुई है।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं यह बात आपके ध्यान में ला सकता हूं कि हम सिंचाई मंत्रालय पर चर्चा करने जा रहे है ?

श्री बी.एन.रेड्डी : दो सिंचाई परियोजनायें - आन्ध्रप्रदेश के गोदावरी से जुड़ी श्री राम सागर का दूसरा चरण तथा कृष्णा नदी से जुड़ी श्री सैलेम लेफट बैंक कनाल गत 20 वर्षों से केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ी है। अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि शीघ्र ही इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी जाए तथा राज्य सरकारों को इनसे सम्बन्धित कार्य प्रारम्भ करने का परामर्श दिया जाए ताकि इन्हें आठवी पंचवर्षीय योजना में ही पूरा किया जाए।

मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कम से कम अब मंत्री जी को बुलाया जाए।

[हिन्दी]

श्री भावना चिखलिया (जूनागढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहती हू। अभी हाल ही में हमारे भाजपा के नेता और सदन में विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में मानवधिकार के कमसल पर पाकिस्तान को जिस तरह करारी हार का सामना करना पड़ा है....

अध्यक्ष महोदय : आपने गुजरात और राजस्थान पर बोलना है।

श्रीमती भावना चिखलिया : उसके बावजूद हिन्दुस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने के इरादे से पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था ने गुजरात और राजस्थान को सीमावर्ती क्षेत्रों में विस्फोटक पदार्थो एवम् नशीले पदार्थो का संग्रह कर लिया है। उपयुक्त समय मिलने पर वे लोग इन नशीले पदार्थो को सारे भारत में फैलाने का षडयंत्र रच रहे हैं, मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि सीमा पार की चौकियां का अंतर घटकर उनकी संख्या बढ़ायी जाये, यही निवेदन है।

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

[हिन्दी]

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर) : अध्यक्ष महोदय, जवाहर रोजगार योजना की विशेष योजना के तहत देश के ऐसे जिलों को केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 5 करोड़ रूपये देने का प्रावधान है जहां पर काफी संख्या में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले असंगठित मजदूर है, वही लोगों को - जवाहर रोजगार योजना- की अतिरिक्त सहायता द्वारा काम दिया जायेगा। पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। सड़क, बांध, नहर आदि बनाये जायेंगे और बेरोजगारों को काम दिया जायेगा। उत्तर बिहार के समस्तीपुर एवं मधुबनी जिले केन्द्रीय सरकार की उपरोक्त योजना के मानदंड में स्पष्ट तौर पर आते हैं परंतु न जाने क्यों इन जिलों को केन्द्र सरकार की जवाहर रोजगार योजना की इस विशेष योजना के लाभ से वंचित रखा गया हैं जिससे वहां के लोगों में घोर अंसतोष व्याप्त है।

अत: केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि उत्तर बिहार के समस्तीपुर एवं मधुबनी जिलों को जवाहर रोजगार योजना की उपरोक्त योजना में अविलम्ब शामिल किया जाये तथा उक्त योजना से वहां की जनता को लाभ पहुंचाया जाये ताकि वहां की गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनता, असंगठित मजदूरों, बेरोजगारों एवं बाढ़ की निरंतर तबाही से पीड़ित गरीब जनता को राहत मिल सके।

[अनुवाद]

श्री थाइल जॉन अंजलोज (अलेप्पी) : महोदय, केरल में नारियल उत्पादक हाल ही के महीनों में उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि और नारियल के मूल्यों में निरंतर गिरावट के कारण कृषि लागत में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप संकट का सामना कर रहे हैं।

अप्रैल, 1993 से गरी के मूल्य में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी है और नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह प्रति क्विंटल 2350 रूपये तक पहुंच गई है। राज्य सरकार ने भारत सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य 3500 रूपये घोषित करने का अनुरोध किया था। गत एक वर्ष से संसद सदस्य नारियल उत्पादकों के उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने के लिए केन्द्रीय एजेन्सी से हस्तक्षेप की लगातार मांग कर रहे हैं। परंतु अभी तक सरकार ने कोई रूचि नहीं दिखाई है और किसानों को उचित मूल्य से वंचित रखा गया है।

नारियल केरल की अर्थव्यवस्था का आधार है और लाखों परिवार नारियल की खेती पर निर्भर रहते हैं। चूंकि इसके मूल्य में तेजी से गिरावट आयी है, अत: लाखों लोगों को गरीबी के कगार पर ढकेल दिया गया है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह नारियल उत्पादकों के उत्पादों के समुचित मूल्य की शीघ्र घोषणा करे। **(व्यवधान)**

श्री पी.सी. थामस (मुवन्तुपुजा) : सरकार नारियल के मूल्य की घोषणा करने के लिए सहमत हो गई है और समर्थन मूल्य कम से कम दो महीने पूर्व घोषित किया जाना चाहिए था। नारियल का उत्पादन केवल केरल में ही नहीं होता अपितु अन्य आठ राज्यों में भी होता है। सरकार द्वारा अनेक आश्वासन दिये गये हैं परंतु सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है। महोदय, यह एक अत्यधिक गंभीर मामला है। क्योंकि लाखों लोग इससे जुड़े हुए है।

अध्यक्ष महोदय : इसे दोहराना आवश्यक क्यों हैं?

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, केरल के मुख्य मंत्री, श्री करूणाकरण आज यहां आये हुए हैं, वे केवल नारियल उत्पादकों की समस्या का समाधान करने के लिए ही प्रधान मंत्री जी से मिलेंगे। वे इस संबंध में श्री बलराम जाखड़ से भी मिलेंगे। हम माननीय मंत्री से अनुरोध करते हैं कि वे नारियल उत्पादकों के हितों का ध्यान रखें और उनके लिए समुचित मूल्य की घोषणा करें । **(व्यवधान)**

श्री पी.सी. थामस : महोय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मंत्री महोदय को इस संबंध में एक वक्तव्य देने का निदेश दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे ऐसा करने के लिए नहीं कह रहा हूं। यदि वे कोई वक्तव्य देना चाहते है तो वे स्वयं दे सकते हैं। कृपया यह समझने की कोशिश करें कि इन मामलों को इस प्रकार नहीं लिया जाता है। यहां अन्य सदस्य भी हैं जो बोलना चाहते हैं। आप इसी मामले को दोहराने के लिए कितना समय लेंगे? कृपया बैठ जाएं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बिहार में चल रहे झारखंड आंदोलन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार का मालूम है कि पिछले दो साल से आर्थिक नाकेबंदी और बंद के कारण अरबों रूपये का नुकसान सरकार का हो चुका है और आम नागरिक सुविधाओं से वंचित होता रहा है तथा इसके चलते सैकड़ो लोगों की जानें भी जा चुकी है फिर भी केन्द्र सरकार इस समस्या के समाधान का प्रयास नहीं कर रही हैं पिछले एक महीने से लगातार बंद और आर्थिक नाकेबंदी के कारण झारखंड क्षेत्र के लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

इसलिये हम सरकार से मांग करते है और चाहते है कि वह तुरंत इसकी घोषणा करे, सभी दलों के प्रतिनिधियों को बुलाकर तुरंत कोई सर्वमान्य निर्णय करे क्योंकि यह आंदोलन हर तरफ जोर पकड़ता जा रहा है। कही आगे चलकर यह कश्मीर और पंजाब का रूप धारण न कर लें। आप जानते है कि आज इस

आंदोलन के कारण वहां रेल रोकी जा रही है, पावर स्टेशन उड़ाये जा रहे है जिसके कारण राष्ट्र का अरबों रूपये का नुकसान हो रहा है। मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करे और एक निश्चित समय फिक्स करके उस अवधि में झारखंड समस्या का समाधान करे, यही मेरी सरकार से मांग है।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : महोदया, मैं आशा करता हूं कि आप अपनी बात इस प्रकार कहेंगी जिससे सभा में सनसनी नहीं फैलेगी।

कुमारी ममता बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, यह सदन मानव अधिकारों और लोकतंत्र का रक्षक है। आप इस बात की प्रशंसा करेंगे कि हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारी सरकार हमारे पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए कुछ धनराशि स्वीकृत करने के मामले में काफी उदार है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करती हूं कि वह हमारे पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए और अधिक धनराशि स्वीकृत करें ताकि वे अंधाधुंध गोलीबारी का सहारा लिए बिना देश के प्रत्येक भाग में कानून और व्यवस्था का ध्यान रख सकें। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि प्रत्येक जगह पुलिस गोलीबारी में वृद्धि हो रही है। मैं विशेष रूप से अपने राज्य का उल्लेख करना नहीं चाहती क्योंकि यदि मैं ऐसा करती हूं तो दूसरे पक्ष के सदस्य अधिक जोर शोर से प्रतिक्रिया करते हैं। परंतु यह हम सभी के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। मेरी जानकारी के अनुसार मेरे राज्य पश्चिम बंगाल में 1,260 बार पुलिस गोलीबारी हुई जिसके कारण अनेक लोगों की जानें गई। यहां तक कि कल भी दो ग्रामीण मारे गये थे। यही स्थिति बिहार में भी है परसो ही बिहार में पुलिस गोलीबारी में कुछ लोग मारे गये थे। बहुमूल्य मानव जीवन को इस प्रकार के निष्ठुर तरीके से समाप्त किये जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मैं माननीय गृह मंत्री से अपील करती हूं कि वे इस मामले पर गंभीरता से ध्यान दें। मैं सुझाव देती हूं कि हमारी पुलिस को असली गोलियों के बजाय रबड़ की गोलियों और पानी के फव्वारों का प्रयोग करना चाहिए। मेरी इस सरकार से यही अपील है कि उसे 'बुलैट' सरकार के समान व्यवहार नहीं करना चाहिए। उन्हें 'बैलेट' की सरकार के रूप में कार्य करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा ! संपूर्ण सदन माननीय सदस्य के विचारों का समर्थन करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अनुरोध करता हूं कि राज्य सरकारों को रबर की गोलियां और पानी के फव्वारे प्रदान कराये जाने चाहिए।

कुमारी ममता बनर्जी : पश्चिम बंगाल राज्य ने उसे प्रदान की गई धनराशि का भी उपयोग नहीं किया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जब भी हम उसकी बात का समर्थन करते हैं, वे उत्तेजित हो जाती हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक कार्य 'ममता' से किया जाना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : केवल शब्दों में ही नहीं अपितु कार्य में भी।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक अति लोक महत्त्व के विषय

की ओर सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। जी.पी.ओ. लखनऊ के पार्क में गांधी जी की मूर्ति के पास जूते और चप्पल रखकर उनका जिस तरह से अपमान किया गया है, यह मेरे पास उसकी फोटो है जिस पर फोटोग्राफ का नाम भी लिखा हुआ है। मैं समझता हूं कि आजादी के 46 वर्षों के बाद भी जिस तरह से लगातार पूज्य महात्मा और राष्ट्रपिता का अनादर, अपमान और असम्मान एक संगठन के जनरल सैक्रेटरी के द्वारा किया गया है, वह बहुत अफसोसजनक और शर्मनाक है। कल पूरे सदन में यह सवाल उठा था। इससे पहले भी जिस तरह से कुछ साम्प्रदायिक शक्तियों ने गांधी जी को असमय हमसे छीन लिया था, आजादी के 46 वर्षो बाद भी, गांधी जी का नाम सबसे ज्यादा जपने वाले लोग, जिस तरह जूते और चप्पलों के बीच में 'गांधी जी अमर रहे' का नारा लगा रहे है, वह गांधी जी का ही अपमान नहीं, पूरे राष्ट्र का अपमान है, अनादर है। मैं कहना चाहता हूं कि इस घटना के कारण आज सभी गांधीवादी लोगों में असंतोष है, संपूर्ण राष्ट्र के लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश व्याप्त है, मैं इस घटना की तीव्र शब्दों में भर्त्सना करना चाहता हूं और गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि इसकी जांच कराये और सदन में एक वक्तव्य देकर स्पष्ट करे और ऐसा घृणित कार्य कराने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय। वे कांग्रेस पार्टी के लोग है।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष जी, मैं माननीय यादव जी के विचारों से सहमत हूं। उत्तर प्रदेश में आजकल एक नई प्रकार की बीमारी फैली है और राष्ट्रीय मानदंडों के खिलाफ अनर्गल प्रचार करके, अनर्गल बोलकर जिस तरह बार-बार कुछ लोग अपना नाम अखबारों में प्रकाशित करा रहे हैं, इससे हमारे समाज के अंदर भेदभाव बढ़ रहा है और फूट पड़ रही है। मगर इसके लिए जो लोग दोषी है वे ही इस बारे में ज्यादा बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार इन सब बातों को आंख और कान बन्द कर के देख और सुन रही है। वहां की सरकार को चलाने का दोष जनता दल और कांग्रेस पार्टी पर है क्यों कि इन्हीं के समर्थन से वह सरकार चल रही है। यदि ये चाहे तो उस सरकार को कल गिरा दे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि गांधी जी की अवमानना करने के लिए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राज्य के सीतामढ़ी से आता हूं। अभी-अभी माननीय मंजय लाल जी ने जिस बात की चर्चा की उसको मैं आपके माध्यम से सदन में उठाना चाहता हूं। पिछले वर्ष सीतामढ़ी में भयंकर बाढ़ आई थी। बाढ़ का सर्वेक्षण करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी भी गए थे और हवाई सर्वेक्षण के बाद पटना हवाई अड्डे पर प्रधान मंत्री जी ने बिहार की मदद करने का आश्वासन दिया था, लेकिन वह आश्वासन "ढाक के तीन पात " के समान सिद्ध हुआ और जो राशि उन्होंने 2 करोड़ 88 लाख की देने की घोषणा की ....

अध्यक्ष महोदय : आप बजट पर बोलते समय इस विषय को उठाएं। अब आप बैठ जाइए।

श्री नवल किशोर राय : अध्यक्ष महोदय, वह राशि बिहार सरकार के हिस्से में से काटी गई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस राशि को राज्य के हिस्से में से न काटा जाए और वहां पर विकास कार्य चलाए जाएं ताकि लोगों को काम मिल सके।

[अनुवाद]

श्री पाइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, यह वास्तविकता है कि मणिपुर में बिना किसी उत्तेजना के सुरक्षा बलों द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी के कारण एक व्यक्ति मारा गया है और छ: व्यक्ति घायल हुए हैं। इससे मणिपुर राज्य में आतंक पैदा हो गया है। चूंकि मणिपुर राष्ट्रपति शासन के अधीन है, इसलिए, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस ओर ध्यान दे ताकि सुरक्षा बलों द्वारा इस अंधाधुंध गोलीबारी को रोका जा सके।

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक गम्भीर समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देश की प्राथमिक पाठशालाओं के शिक्षकों ने 14 मार्च से 18 मार्च तक दिल्ली में करीब 70 हजार की संख्या में अपनी सामूहिक गिरफ्तारी दी थी। उनकी मांग है कि प्राथमिक शिक्षा को जो पंचायतीराज एक्ट में जोड़ दिया गया है उससे उसको अलग किया जाए। यह एक गंभीर विषय है। उनके अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने भविष्य में आंदोलन करने की घोषणाएं की है। यदि इस प्रकार आंदोलन होगा तो देश में जो शिक्षा का प्राथमिक स्तर है उसमें रूकावट आएगी। देश के शिक्षक बहुत गरीबी की हालत में अपना जीवन-यापन कर रहे है और जिस प्रकार से इसे राजनीति से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है वह शिक्षा के लिए गंभीर चिन्तन का विषय है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस पर गम्भीरता से चिन्तन करे और प्राथमिक शिक्षा को पंचायतराज कानून से अलग रखे और शिक्षक संघ से बात करे और प्राथमिक शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करें ताकि भविष्य में शिक्षा का प्रसार हो सके और इसकी गति बढ़ सके।

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर सरकार की ओर से कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त की जानी चाहिए। वहां पर लाठीचार्ज हुआ है सैकड़ो लोग घायल हुए हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

श्री सूरज मंडल (गौड्डा) : अध्यक्ष महोदय, आदिवासियों पर पुलिस का जुल्म इतनी हद तक बढ़ गया है कि हमारे इलाके में जो विस्थापितों के नेता श्री संतलाल मरांडी हैं जिनकी 80 एकड़ जमीन एक कोयला परियोजना में अर्जित कर ली गई है, उनको पुलिस ने उनके घर में जाकर पीटा तथा उनकी पत्नी की पिटाई की और घर का सारा सामान नष्ट कर दिया तथा उनको जेल में बन्द कर दिया। 1989 में मुकदमा दर्ज हुआ था लेकिन 1993 तक भी उसमें कुछ नहीं किया गया। 1994 में पुलिस द्वारा दमन कराने की कार्यवाही हो रही है। इतना ही नही, संथाल-परगना में तीन महीने से पुलिस का अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि एक कुमारी के साथ पुलिस ने फतेहपुर थाने में बलात्कार किया। इसी तरह से एक दूसरे थाने में पुलिस के दरोगा ने एक लड़की के साथ बलात्कार किया। राज्य सरकार के इशारे पर पुलिस का अत्याचार झारखंड इलाके में बढ़ गया है। 10 जनवरी को ट्रेड यूनियन के लीडर श्याम सुन्दर सिंह की भी हत्या कर दी गई। हत्यारे आज भी पुलिस के सामने घूम रहे है लेकिन कोई कार्यवाही नही की जा रही है।

मैं केन्द्र सरकार से कहना चाहता हूं, उस इलाके में आदिवासी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को बिहार की पुलिस तंग कर रही है। झारखंड राज्य की मांग को लेकर राज्य सरकार के साथ हमारी अनबन है इसलिए हमें गलत मुकदमों में फसाया जा रहा है। यह फिफ्थ शैडयूल में आता है, केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आधा घंटा समाप्त हो गया है। अब हम अगली मद पर विचार करेंगे।

11.31 म.पू.

सभा पटल पर रखें गए पत्र

स्वास्थ्य के लिए नागरिक चार्टर के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 1461 के 3 मार्च, 1994 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री : श्री पवन सिंह (घाटोवार) : मैं स्वास्थ्य के लिए नागरिक चार्टर के बारे में श्री अकुंशराव राव साहब टोपे के अतारांकित प्रश्न संख्या 1461 के 3 मार्च 1994 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या 5644/94)

11.32 म. पू.

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है:

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोकसभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 17 मार्च, 1994 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 15 मार्च 1994 को पारित किये गये विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) संशोधन विधेयक 1994 से बिना किसी संशोधन के सहमत है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 17 मार्च 1994 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 15 मार्च, 1994 को पारित किये गये कॉफी (संशोधन) विधेयक, 1994 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य- संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1994 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 17 मार्च, 1994 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(चार) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य- संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे विनियोग विधेयक, 1994 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 17 मार्च, 1994 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(पांच) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 17 मार्च 1994 को हुई

अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 16 मार्च, 1994 को पारित किये गये खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक 1944 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

11.34 म. पू.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) आन्ध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर पोलावरम बहु-उद्देश्यीय सिंचाई परियोजना को केन्द्रीय योजनाओं में शामिल करने की आवश्यकता

श्री रामकृष्ण कोंताला (अनकापल्ली) : मैं सरकार का ध्यान आन्ध्र प्रदेश में पश्चिम गोदावरी जिले के पोलावरम गांव में गोदावरी नदी पर पोलावरम बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना की ओर दिलाना चाहता हूं। राष्ट्रीय जल नीति में जल संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। विविध उद्देश्यों के लिए जल की बढ़ती हुई मांग जैसे पीने के लिए, सिंचाई, जल विधुत, नौ संचालन औद्योगिक तथा अन्य उद्देश्यों के लिए इस परियोजना द्वारा पूर्ति की जायेगी इस परियोजना से 2.91 लाख हेक्टेयर उच्च भूमि क्षेत्र की सिंचाई करने का विचार है। जिसमें पूर्व, पश्चिम गोदावरी, कृष्णा और विशाखापट्टनम जिलें आते है, इसके अलावा 720 मेगावाट तक विद्युत उत्पादन हो पायेगा। इस परियोजना को आधुनिक बनाने की लागत 3030 करोड़ रूपये की है। पिछले 20 वर्षों से यह परियोजना राज्य तथा केन्द्रीय जल आयोगों के पास लम्बित पड़ी हुई है। इस परियोजना से लगभग 40 लाख लोगों को सीधे फायदा होगा। इससे तेलगू गंगा, रायलसीमा क्षेत्र को भी फायदा होता है। इस परियोजना से कुछ सीमा तक समूचे आन्ध्र प्रदेश राज्य को तथा हैदराबाद की जल समस्याएं भी सुलझ जायेगी। चूंकि जल संसाधन विकास कार्य अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए उत्प्रेरक है इसे अवश्य ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में लेने का अनुरोध करता हूं क्योंकि राज्य सरकार इस परियोजना को संसाधनों के अभाव को ध्यान में रखते हुए इसे अपने हाथ में लेने की स्थिति में नहीं हैं वैकल्पिक रूप में, इस परियोजना को विश्व बैंक या एशियन विकास बैंक जैसी सहायता देने वाली विदेशी एजेन्सियों को सौंपा जा सकता है चूंकि यह एक बहु-उद्देश्यीय सिंचाई नौसंचालन तथा विद्युत परियोजना है। इसे औद्योगिक दर्जा दिया जा सकता है, ताकि इस परियोजना को बहुराष्ट्रीको द्वारा पूंजी निवेश के योग्य बनाया जा सके। मैं आपसे इस मामले को शीघ्र आगे बढ़ाने और इस बहु-उद्देश्यीय सिंचाई परियोजना को आगामी आठवीं योजना में शामिल करने के लिए सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं।

(दो) मध्यप्रदेश में सिहोरा तहसील में सिहोरा कस्बे के निकट हरगढ़ में एक उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता

श्री श्रवण कुमार पटेल (जबलपुर) : जबलपुर जिले की तहसीलों में सिहोरा तहसील निःसंदेह सबसे पिछड़ी हुई तहसील है।

इसके सामरिक महत्व तथा इसके पिछड़ेपन पर विचार करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने सिहोरा कस्बे के निकट सहोरा तहसील हरगढ़ में विस्फोटक फैक्टरी स्थापित करने का निर्णय लिया था। इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार ने हरगढ़ में बहुत बड़ी भूमि का टुकड़ा लिया है और इसके बुनियादी ढांचे पर बहुत अधिक धनराशि निवेश भी की गई है।

तथापि, सरकार ने अचानक ही इस विस्फोटक फैक्टरी को हरगढ़ से अन्यत्र कहीं स्थापित करने का निर्णय लिया है।

हरगढ़ में ली गई भूमि अभी भी केन्द्रीय सरकार की है। मैंने प्रधानमंत्री को और 1992 में तत्कालीन उद्योग मंत्री को भी इस स्थिति के बारे में अवगत कराया था।

इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि चूंकि हरगढ़ में इसके बुनियादी ढांचे पर इतना अधिक धन लगाया गया है, इसलिए यहां एक उपयुक्त उद्योग स्थापित किया जाए जिससे कि जबलपुर जिले के सिहोरा तहसील की गरीब, जरूरत मंद तथा आदिवासी जनता को रोजगार मिल सके और इसके अलावा भूमि का भी इस्तेमाल हो सके।

(तीन) पूर्वी भारत के आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे उद्योगों में आदिवासी युवकों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण देने हेतु एक तकनीकी संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता

कुमारी फ्रिडा तोपनो (सुन्दरगढ़) : माननीय अध्यक्ष, मैं इस महान् सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान रोजगार के अवसर उपलब्ध न होने, व्यापक औद्योगिकीकरण के कारण भारत के पूर्वी हिस्से में स्थानीय आदिवासी लोगों की संस्कृति की पहचान न होने की और दिलाना चाहता हूं। आदिवासी लोगों की जन्म भूमि पूर्वी भारत में खनिज संसाधन प्रचूर मात्रा में है। हाल ही कें पिछले वर्षो में, इस क्षेत्र में संयुक्त सरकारी क्षेत्र के उपक्रम स्थापित किये गये है। वे आदिवासी लोगों की भूमि पर स्थापित किये गये है, उन आदिवासी लोगों को उनकी भूमि से वंचित करके, हजारों आदिवासियों को उनकी भूमि से विस्थापित किया गया है उन आदिवासी लोगों ने भूमि पर अथक परिश्रम करके उस भूमि को कृषि योग्य बनाया था। सरकार ने वास्तविक आवश्यकता पर ध्यान दिये बिना हजारों एकड़ भूमि अधिग्रहति कर ली है। अब, सैकड़ों एकड़ भूमि का गैर-कानूनी लोगों द्वारा या तो दुरुपयोग किया जा रहा है या उस पर कब्जा किया जा रहा है।

इसलिए, मै सरकार से इस संबंध में राष्ट्रीय नीति बनाने का अनुरोध करता हूं। उद्योग स्थापित करते समय सरकार का एक उद्देश्य स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना था लेकिन सरकार ने उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उचित कदम नहीं उठाये थे। मैं सरकार से इस क्षेत्र में तकनीकी संस्थान स्थापित करने का अनुरोध करता हूं जिससे कि इन उद्योगों में आदिवासी युवकों को नियुक्ति के लिए तैयार किया जाये।

(चार) सामान्य श्रेणी के टिकट धारकों को दिन के समय रेलगाड़ियों में द्वितीय श्रेणी के आरक्षित डिब्बों में यात्रा करने की अनुमति देने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, देखे की आम जनता की रेलगाड़ी में यात्रा बड़ी कठिन हो गई है। जिन यात्रियों को दो या तीन घंटे रेल से यात्रा करनी हो, उनको अपने परिवार और बच्चों के साथ खड़े होकर जाना पड़ता है। आम डिब्बे भरे आते है। इनकी संख्या भी कम होती है। गाड़ी जहां से चलती है वहीं से डिब्बे भर जाते हैं। 2 टायर तथा 3 टायर में बैठने पर भारी जुर्माना देना पड़ता है। यात्री फिर बसों में चलते है। इससे रेल विभाग को हानि अधिक हो रही है। यह पूरे देश की समस्या है। आम डिब्बा बढ़ाने पर भी वही समस्या रहेगी। शुरू से डिब्बे भरे आयेंगे और आम यात्री उनमें नहीं बैठ पायेगें।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि आम जनता के हित के लिये दिन मे यात्रा करने वाले यात्रियों को पहले की तरह द्वितीय श्रेणी आरक्षण में बैठने के आदेश दिये जाने चाहिये।

(पांच) भुवनेश्वर उड़ीसा में भारतीय जीवन बीमा निगम का एक मंडलीय कार्यालय खोलने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री शिवाजी पटनायक (भुवनेश्वर) : उड़ीसा की राजधानी, भुवनेश्वर में भारतीय जीवन बीमा निगम का एक भी मंडलीय कार्यालय नहीं है। राज्य और केन्द्र सरकार के और सरकारी क्षेत्र तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के अधिकांश कर्मचारी भुवनेश्वर में रहते हैं। इससे पहले इस शहर को और इसके आस-पास के जिलों को कटक के मंडलीय कार्यालय में शामिल किया गया था। लेकिन तब से कटक कार्यालय में कार्यभार बहुत अधिक बढ़ गया है। यहां तक कि बरहामपुर और संबलपुर, जिन्हें पहले कटक कार्यालय में शामिल किया गया था, में मंडलीय कार्यालय खोलने के बाद भी, लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नये व्यापार का विकास कटक कार्यालय की क्षमताओं से बाहर है। इन सबके अलावा, समाज के कमजोर वर्गों, जिनमें बीड़ी श्रमिक भट्टे में काम करने वाले श्रमिक, बढ़ई, महिला दर्जी, शारीरिक रूप से विकलांग हस्तशिल्प कारीगर, खादी बुनकर शामिल है, के लिए सामूहिक बीमा और समाज सेवा योजनायें भुवनेश्वर से ही भली भांति चलाई जा सकती है। जीवन बीमा निगम वित्त लि० भुवनेश्वर में पहले से ही एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला हुआ है और वर्ष 1992-93 के दौरान, इसके संचालन ने कीर्तिमान विकास किया है जोकि यहां अच्छे कारोबार का सूचक है।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि वह भुवनेश्वर में शीघ्र एक मंडलीय कार्यालय खोलें।

(छ:) रबड़ उत्पादों के हितों की रक्षा हेतु रबड के बेहतर उपयोग के तरीके निकालने की आवश्यकता

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : भारत में रबड़ का उत्पादन इसकी खपत से अधिक है। अगले वर्ष के अंत में कम से कम 1 लाख टन रबड़ वास्तव में आवश्यकता से अधिक होगा। इसलिए, यह आवश्यक है कि रबड़ के नये उपयोग का पता लगाया जाये। विशेष रूप से लघु क्षेत्र के उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। रबड़ का एक और अच्छा उपयोग रबड़ की सड़कें बनाकर किया जा सकता है। पूरे राष्ट्र में, सड़कों को लंबे समय तक अच्छी स्थिति में रखने के लिए, रबड़ के उपयोग द्वारा हमारी सड़कों को पहले से बेहतर, टिकाऊ, दुर्घटना मुक्त और आधुनिक बनाया जा सकता है। रबड़ बोर्ड प्रौद्योगिकीय सहायता दे सकता है। केन्द्रीय और राज्य लोक निर्माण विभागों को इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। भारत में सभी सड़कों को रबड़युक्त बनाने के लिए, हमारे देश में रबड़ का पर्याप्त उत्पादन होता है। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, किसान और हमारी सड़कों को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचेगा। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करे।

(सात) कानपुर उत्तर प्रदेश को वायु सेना द्वारा देश के अन्य महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जगत बीर सिंह द्रोण (कानपुर) : मान्यवर अध्यक्ष जी, कानपुर उत्तर भारत का एक प्रमुख औद्योगिक एवं व्यावसायिक केन्द्र है, जहां से चमड़ा तथा चमड़े से बनी अनेक वस्तुऐं विदेशों को बड़ी मात्रा में निर्यात की जाती है। उद्योग तथा व्यापार के संबंध में यहां बड़ी संख्या में देश से एवं विदेश से लोगों का लगातार आना-जाना होता है, परन्तु तीस लाख से ऊपर जनसंख्या वाले इस महानगर से वायु मार्ग द्वारा सम्पर्क सम्भव नहीं है जिसके कारण यहां की उन्नति एवं विकास अवरूद्ध हो गया है तथा यहां की औद्योगिक तथा व्यावसायिक उन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

कुछ समय पूर्व तक दिल्ली से कानपुर तथा कुछ उड़ानें कानपुर होकर देश के अन्य प्रमुख नगरों तक

थी, परन्तु कतिपय कारणों से इन्हें पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। अभी हाल ही में कानपुर को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने हेतु सर्वेक्षण कराया गया था जिसमें कानपुर को इसके उपयुक्त पाया गया था, परन्तु फिर एक बार लखनऊ को यह स्थान प्रदान किये जाने पर जोर दिया जा रहा है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कानपुर नगर की तीस लाख जनसंख्या तथा यहां के उद्योग एवं व्यापार को प्रोत्साहन देने हेतु कानपुर महानगर को नियमित उड़ानें प्रारम्भ की जाये। इस नगर को देश के अन्य प्रमुख नगरों से वायु मार्ग द्वारा जोड़ा जा जाये तथा कानपुर हवाई अड्डे का विकास एवं विस्तार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाए, जिससे उत्तर प्रदेश के इस सबसे प्रमुख नगर का गौरव पुन: स्थापित किया जा सके।

[अनुवाद]

श्री के. राममूर्ति टिंडिवनाम (टिंडिवनाम) : महोदय, मेरा नाम नहीं लिया गया है। एक सदस्य अनुपस्थित थे और उनकी अनुपस्थिति में मेरा स्थान सबसे पहले आता है।

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि नियम 377 के अधीन सीमित निवेदन करने की अनुमति होती है और वह संख्या पूरी हो चुकी है।

श्री के. राममूर्ति टिंडिवनाम : महोदय, एक सदस्य अनुपस्थिति है और उनके बाद मेरा स्थान सबसे पहले आता है।

अध्यक्ष महोदय : वह खास संख्या पूरी हो चुकी है - उन सदस्यों की संख्या जिन्हें 377 के अधीन अनुमति दी गई है।

श्री के. राममूर्ति टिंडिवनाम : मुझे खेद है, वह संख्या पूरी नहीं हुई है। एक सदस्य अनुपस्थित है और उनके बाद मेरा नाम सबसे पहले आता है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने दो और नाम भी बुलाए हैं। मैंने दूसरी सूची से दो अन्य नाम भी आंमत्रित किए है। आपको पूरी जानकारी नहीं है और आप बहस करते जा रहे हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

अब मैं श्री निर्मल कान्ति चटर्जी को आज की चर्चा आरंभ करने के लिए आमंत्रित करता हूं।

11.44 म०पू०

सामान्य बजट, 1994-95 - सामान्य चर्चा - जारी

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मैं नहीं जानता कि क्या आपने डा० सिंह को यह सूचना दी थी कि मैं पहला वक्ता होऊंगा।

आपने मुझे सबसे पहले बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह जल्दी नहीं है बल्कि दोपहर के 12 बज रहे है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं कुछ टिप्पणियां करना चाहूंगा, दुर्भाग्य से डा० सिंह उपस्थित नहीं है। मेरी स्वाभाविक इच्छा है कि राज्य मंत्री ये बातें उन्हें बता देंगे।

पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बजट - मेरे भाषण में कुछ सार होगा, लेकिन अधिकांशत:

नयी बातें होगी, जैसाकि मैंने आपको आवश्वासन दिया है, महोदय - अनावश्यक रूप से बनावटी है। यह अनावश्यक रूप से बनावटी क्यों है? क्योंकि मैं यह मानने लगा हूं कि श्री मनमोहन सिंह को गहरी समझ है लेकिन समस्या यह है कि वे कांग्रेसियों के बीच आ गये हैं। यह बजट संदेहास्पद आंकड़ों से भरा हुआ है। मैं बताऊंगा कि मेरे समय में संसद में उन दिनों इस प्रकार के तथ्यात्मक रूप से संदेहास्पद आंकड़े कभी प्रस्तुत नहीं किए गये। मैं यह बताने का प्रयत्न करूंगा कि बजट में संपूर्ण दृष्टिकोण आश्चर्यजनक रूप से अनुत्तरदायी है। यह जनता के पक्ष में नहीं है और यह विकास संबंधी नीति के मार्ग में बाधक है सिवाय जल देवता अथवा बहुराष्ट्रों पर निर्भर रहने के।

मैं सच्चाई रखना चाहता हूं। मेरा संदेह, कुछ अजीब आंकड़ों से उत्पन्न हुआ। मैं 'बजट-एक नजर' को देख रहा हूं। हम कभी-कभार ही राजस्व प्राप्तियों के बीच इस प्रकार का संबंध देखते हैं जैसाकि बजट अनुमान और संशोधित अनुमानों में है। मैं केवल आंकड़े दूंगा।

निगमित कर के लिए 10,500 करोड़ रू० का बजट अनुमान था। संशोधित अनुमान भी 10,500 करोड़ रू० के थे। आयकर के लिए बजट अनुमान 9,500 करोड़ रू० थे और संशोधित अनुमान 9,500 करोड़ रू० के थे। यह सिर्फ राजस्व के मामले में ही नहीं है। मैं बाद में दिखाऊंगा कि यह कुछ खर्च के आंकड़ों के संदर्भ में भी सही है। इससे मुझमें शंका उत्पन्न हुई और अनुपूरक मांगों में, यदि इसकी और ध्यान रहे। एक अनुपूरक मांग की गई है। जिसमें 10,000 करोड़ रूपये का अतिरिक्त खर्च है, इन सभी पर मतदान होना है और 40 हजार रूपये इस पर लगाया जाएगा। मैंने आंकड़ों में एकरूपता लाने की कोशिश की। मैंने एक प्रश्न किया। क्या ये आंकड़े संशोधित प्राक्कलन का ही हिस्सा है। उत्तर था, कि 10,000 करोड़ रूपये में से 1,000 करोड़ रूपये संशोधित प्राक्कलन के बाहर है। लगभग 40,000 रूपये के संबंध में उन्होंने चुप्पी साध ली है। उन्होंने कोई भी उत्तर नहीं दिया। मुझे सरकारी पक्षों के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहिए, जो इस बात से सहमत थे कि उन्होंने उत्तर टाला है। मैंने पता करने की कोशिश की कि यदि 49,000 करोड़ संबंधी इस आंकडे की बजट में कहीं चर्चा हुई है। मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इस तरह के आंकड़े इसमें नहीं थे।

इन सभी आंकड़ों से मेरे मन में संदेह पैदा हुआ। सामान्यतया, हम पहले वर्ष के संशोधित प्राक्कलनों और आने वाले वर्ष के लिए बजटीय प्रस्ताव के आधार पर ही चर्चा आरंभ करते हैं। इससे मुझे एक वर्ष पीछे जाने का मौका मिला। मैं आपको ये आंकड़े दूंगा और देखूंगा कि इन तीनों बजटों के दौरान इन आंकड़ों में क्या समानता है।

वर्ष 1993-94 के लिए बजट में बजट प्राक्कलनों और संशोधित प्राक्कलनों के विषय में एक निश्चित प्राक्कलन पहले जैसा ही दिया गया है, उन्होंने इन वर्षों की किताबों में सही आंकड़े प्रस्तुत किए है। कृपया समानता की प्रकृति को देखिए। बजट प्राक्कलनों के प्रत्येक आंकडों को भी देखिए। वर्ष 1992-93 के बजट प्राक्कलन में राजस्व उगाही के आंकड़े 78,279 करोड़ है और वास्तविक आंकड़े 74,128 करोड़ थे। वर्ष 1992-93 के लिए संशोधित प्राक्कलन 58,179 करोड़ थे और वास्तविक राशि 54,044 करोड़ थे। मैं ऐसे कितने ही आंकड़े दे सकता हूं। राजस्व उगाही संबंधी प्रत्येक आंकड़े संशोधित बजटीय प्राक्कलनों से कम है, और खर्च में से प्रत्येक एक वस्तु संशोधित प्राक्कलनों से ज्यादा है। इन दोनों को हम जोड़ दें। पूरक बजट में यह उल्लिखित है कि 1,000 करोड़ रूपये की राशि पर संशोधित प्राक्कलन से बाहर मतदान हुआ है और कोई भी अवगत नहीं है कि सूद भुगतान की 40,000 करोड़ रूपये की राशि को शामिल गया है या नहीं। वर्ष 1993-94 के बजट में 37,000 करोड़ रूपये सूद के रूप में चुकाई गई है। इसलिए, जैसा कि आंकड़ों से पता चलता है कि ये जो स्थिति है वह बहुत ही भयावह है। महोदय, मैंने श्री प्रणव मुखर्जी

के बजट श्री राजीव गांधी के बजट को और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के बजट को पढ़ा है। इस तरह के आंकड़े में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है।

महोदय, इस संदर्भ में एक या दो बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। हम सभी राजस्व की हानि से अवगत है, यह दूसरी भयावह बात है। मुझे नहीं मालूम कि किस तरह के विशेषण का यहां इस्तेमाल हो रहा है। आंकड़े यहां दिए गए है। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आंकड़ों का उदारीकरण किया गया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उनका निजीकरण किया गया है।

यदि हम मान लें कि 1300 करोड़ रूपये के निगमित कर को त्याग दिया गया है और यदि हम यह मान लें कि जैसा कि बजट के प्रस्ताव में दिया गया है कि आयकर के रूप में 1000 करोड़ का त्याग किया गया है तो वर्ष 1994-95 के आंकड़े के मुताबिक आपको मालूम है कि किसी विकास की जरूरत है। वर्ष 1994-95 के निगमित कर के लिए प्रस्तुत आंकड़े से यह जानने के लिए वर्ष 1994-95 में कितना आयकर की प्राप्ति हुई है, निगमित करके मामले में 39 प्रतिशत से कम विकास दर का अनुमान किया जाना चाहिए और संशोधित आंकलनों के मुताबिक 30 प्रतिशत से कम विकास दर नहीं माना जाना चाहिए। यह संशोधित आंकलन बजट आंकलन के ही बराबर है।

महोदय, कृपया मुझे एक अन्य मुद्दे को और जोड़ने दीजिए और तब मैं अन्य चीजों का उल्लेख करूंगा।

यह मान लिया गया है कि 55,000 करोड़ के वित्तीय घाटे के स्तर पर, मेरा पहला प्रस्ताव यह होगा कि जब इन आंकड़ों को जोड़ा जाता है, तो पिछले वर्ष के लिए, यह 1 लाख बनता है, लेकिन आने वाले वर्ष के लिए उन्होंने 55,000 करोड़ के वित्तीय घाटे का अनुमान किया है।

दावा यह है कि यह सकल घरेलू उत्पाद था। यह केवल 6 प्रतिशत ही है। सकल घरेलू उत्पाद के जो वर्तमान आंकड़े आपने प्राप्त किए है वह वर्ष 1992-93 के लिए है। यह 6,27,000 करोड़ है। यह हम मूल्यों के मामले में विकास दर मान लें, तो यह 6,27,000 करोड़ रूपये की राशि पर आठ प्रतिशत की मुद्रास्फीति का दर होगा और वर्ष 1993-94 में सकल घरेलू उत्पाद में 12 प्रतिशत की अभिवृति होगी। वे 7,00,000 करोड़ रूपये तक इसे ले जायेंगे। सकल घरेलू उत्पाद को छह प्रतिशत के स्तर पर घाटे सीमित रखने के लिए, तो आपको सकल घरेलू उत्पाद को 9,00,000 रूपये तक रखना होगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना विकास दर की कल्पना की गई है। अर्थव्यवस्था में विकास दर को 25 से 30 प्रतिशत के बराबर होना चाहिए। इसे निश्चित रूप से प्राप्त किया जा सकता है। मैं इसे अस्वीकार नहीं कर सकता **(व्यवधान)** मैं नहीं सोचता कि इसे प्राप्त कर लेना असंभव होगा क्योंकि आपने यह धारणा व्यक्त की है, कि आप 6 प्रतिशत का विकास दर मान सकते हैं। जो कि अधिकतम है और जिसे आप प्राप्त भी कर ले सकते हैं लेकिन शेष बीस प्रतिशत मुद्रास्फीति के दर से आता है। यदि चालू मूल्यों की दर से यदि हम 7,00,000 करोड़ से 9,17,000 करोड़ तक बढ़ जाते है और यदि आप छह प्रतिशत का सही विकास दर मान लेते हैं तो आपको मुद्रास्फीति की दर 24 प्रतिशत मानना होगा। मैं समझता हूं कि, आप गलतियां कर रहे है, आप दिवास्वप्न देख रहे हैं और आप देशों के लोगों को धोखा दे रहे हैं। यही स्थिति है। मैं रोजगार के विषय में चर्चा नहीं करूंगा। उन्होंने रोजगार के आंकड़ों के लिए श्रेय लिया। मैं उस तक बाद में आऊंगा जब मैं लोगों की स्थिति पर चर्चा करूंगा।

यह वास्तविक स्थिति है जो भयानक रूप से संदेहास्पद है, जिसके आधार पर आप अपने लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए महल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस छिछला क्यों मानता हूं। मेरे लिए यह बहुत

ही साधारण मसला है। वित्त मंत्री जी द्वारा सफलता का दावा, विदेशी मुद्रा भंडार की समृद्धि पर आधारित है जो 13 विलियन डालरों तक पहुंच गया है। दूसरा विशाल खाद्य भंडार है। अन्य दावों के अतिरिक्त, इन दो दावों पर वह आगे जाना चाहते हैं। मैं क्यों इसे छिछला मानता हूं।

अब मैं डा० मनमोहन सिंह के संबंध में बोलता हूं। आरंभ में खाद्य भंडारों की बात करते हुए, मैं कहना चाहूंगा कि पिछले तीन वर्षों में खाद्य भंडार में कमी आती रही है। यही गलीचे के नीचे जाने का मतलब है और आन्तरिक स्थिति का रूपायक है। हम वर्ष 1984-85 में चोटी पर पहुंच गए है।

12.00 मध्यान्ह

प्रति व्यक्ति आय में कमी होती रही है, जब खाद्य भंडार बन जाता है तो क्या प्रश्न नहीं उभरते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिव्यक्ति आय में कमी होने की स्थिति में, लोग अब पहले इतना भी खरीदने या उपभोग करने में सक्षम नहीं है। कृषि का उत्पादन अच्छा है लेकिन उतना अच्छा नहीं था कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो। भंडार से लोगों की विपदा और गरीबी का पता चलता है। यह सतह से अंदर तक यही हाल है। हमे इस 13 विलियन डालरों के विषय में सोचना चाहिए 13 विलियन डालर का भंडार अच्छा है। लेकिन इसके नीचे हमें यह पता करनी चाहिए कि इस 13 विलियन डालरों की प्रकृति आखिर है क्या? हम जानते हैं कि ये 13 विलियन डालर कहां-कहां से आए हैं। एक उत्पादक गतिविधि में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है। एक होगा पोर्टफोलियों स्थानांतरण या पोर्टफोलियों निवेश टी.ओ.एम.सी.ओ की खरीदारी की जा रही है। कोका कोला कुछ खरीद रहा है। इतना ही नहीं, कई ऐसे भी लोग हैं। लेकिन मैं इस पर सदन का समय नहीं खर्च करूंगा। इसलिए, यह एक तरह की चीज है। तीसरा कर्ज का इन-फ्लाईट (वृद्धि) है जिसे एन.आर.ई. कर्ज है।

श्री मुरली देवरा (मुम्बई-दक्षिण) : जैसा कि चीन है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : जैसा कि चीन में हैं, वह भी समझते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्योंकि वह बम्बई क्लब के हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : और, महोदय, यह प्रवाह पोर्टफोलियों प्रबंधन से नहीं है बल्कि स्टॉक मार्केट में बोली लगाने के कारण है। इसे वित्तीय संस्थागत निवेश कहा जाता है। 1.3 विलियिन डालर स्टॉक मार्केट में पहुंच गया है और अन्य प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने दूसरे संदर्भ में, चर्चा किया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी औद्योगिक मंदी है और धन का अधिक्या है जो लाभ की तलाश में विश्व भर में खोज में है कि इसका निवेश कहां किया जाये।

वे इस देश में उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देना नहीं चाहते। यह एक साधारण अर्थशास्त्र है कि यदि उत्पादन इकाईयों को और भी उर्जा प्रौद्योगिकियों से मजबूत किया जाता है तो वे अपनी उत्पादन सुविधाओं से ही प्रतियोगिता कर सकेंगे जो कि इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। यह पुराना सिद्धांत है और हमे इसे समझने के लिए मार्क्सवादी विचारधारा की आवश्यकता नहीं है। अर्थशास्त्रियों के पितामह, जॉन मेनट किंग्स सुझाव देते हैं कि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का एक और तरीका यह है कि उन मार्गों का पता करें जिनमें बगैर उत्पादन किए भी आप निवेश कर सकते हैं। उन्होंने दो मतों का सुझाव दिया। एक तो बहुत ही सरल है कि कोई उत्पादन नहीं होना चाहिए। अत: खड्डा खोदिए और उसे पुन: भर दीजिए। तब कोई उत्पादन नहीं हैं। आप दोनों मार्गों पर खर्च करते हैं और आय बगैर किसी उत्पादन के ही होता है।

श्री ए. चार्ल्स : वहां किस तरह का उत्पादन होता है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : आय उत्पादन होता है। मि० चार्ल्स, यदि आप खड्डा खोदने में लगे है, तो आपको आय प्राप्त होगी, क्योंकि आप को वेतन प्राप्त होगा जो न्यूनतम पारिश्रामिक से ज्यादा होगा।

यदि आप इस पुन: भरने में शामिल हैं, तो आपकी आय दोगुना हो जाएगा। यह विशेष विशेषज्ञ का मत है कि आपको उत्पादन के लिए उपभोक्ता की जरूरत नहीं होती है। यह जॉन मेनोटकिंस की प्रतिभा थी, जो खोज करती थी, जिसके आधार पर उन वर्षों के दौरान कई अर्थशास्त्रियों को कुछ लाभ हुआ। अत: हमें 13 विलियन डालर के विदेशी मुद्रा भंडार में इस संचयन को समझना होगा, लेकिन फालतू नीतियों के सदंर्भ में नहीं। मैं संकेत देना चाहता था कि डा० सिंह की ख्याति के लोगों को चाहिए था कि वे अर्थव्यवस्था को नई दृष्टि प्रदान करें। उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में इस वृद्धि का कुल स्रोत बताने से इंकार किया। अब मैं और किसी विषय के संबंध में बोलता हूं।

महोदय, कई अन्य माननीय सदस्यों जैसे डा० सिंह द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि उत्पाद शुल्कों आदि को लगाने के संदर्भ में कई गलतियां गणना में हुई है। उनका कहना है कि वह अंकगणित में कमजोर है और वह इस बात से सहमत है कि उन्हें आंकड़ों में कोई विशेष रूचि नहीं है। यह एक गलत तरीके का उत्पाद शुल्क होगा और यह एक गलत तरीके की छूट होगी। वह इससे भी सहमत है। यह मुद्रा गलतियों का प्रश्न नहीं है। गलतियों का जो एक व्यवस्थित स्वरूप है उससे कुछ और ही बात का पता चलता है। पहले, लघु उद्योग को क्षति होगी। यह व्यवस्थित है।

जब आप किसी विशेष उत्पाद शुल्क को यथा मूल्य परिवर्तित करते हैं की बात करते हैं तो स्पष्ट है कि कोशिश यह की गई है कि लघु उद्योग को काफी नुकसान हुआ है। यहां मेरे पास ज्ञापनों के बंडल है, जो आपको भेजा गया है। अत: मैं इस पर आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। **(व्यवधान)** दरअसल, जैसाकि हम सभी जानते है कि इस धरती पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता, जो सौ प्रतिशत बुरा हों, न ही मुरली है।

महोदय, मैं इसे गरीब विरोधी और भारत-विरोधी क्यों कहता हूं। इस दिशा में सोचों कर लगाने की दिशा पर सोचे। जैसा कि हम जानते हैं, सदन जानता है, हम हमेशा यह जोर देते रहे हैं कि कुल करबचन में से, प्रत्यक्ष करों से एक निम्न प्रतिशत ही लिया जाए और प्रत्यक्ष करों में से एक उच्च प्रतिशत लिया जाए। यह एक नया मार्ग है कि उन्होंने इसकी खोज की है। यह मार्ग सीमा शुल्क है को कम करता है और कुछ किस्म के उत्पादों के लिए उत्पाद शुल्क को कम करें और कुछ अन्य किस्म के उत्पादों के लिए उत्पाद शुल्क में वृद्धि की जाए। जैसा कि हम सभी जानते है कुल सीमा शुल्क में 2,000 करोड़ रूपये की कमी की गई है। उत्पाद शुल्क के मामले में स्थिति संतोषजनक है। यह थोड़ा है, लेकिन इसमें यह सच्चाई छिपी हुई है। कि उन उत्पादों के उत्पाद शुल्क में कमी की गई है जो संसदों द्वारा भी पसंद किए जाते थे, और देश का धनाढ्य वर्ग तो इस तथाकाक्षित 'श्वेत उत्पाद' का ज्यादा पसंद करता ही था। छाते, चप्पल आदि के उत्पाद शुल्क को वैज्ञानिक लगने के नाम पर और शुल्क ढांचे को विशेष से लेकर यथामूल्यानुसार, इस तरह की स्थिति उभरी है।

यह गलती का प्रश्न नहीं है। यह निवेश का मामला है जो कि देश के बाहर के कुछ अन्य लोग चाहते हैं कि इस पर अमल किया जाए। यह निवेश है क्या? कृपया कल्पना कीजिए जैसा कि मैं पहले कह रहा था, बाहर भारी मंदी का दौर चल रहा है। उन्हें अपने उत्पादों को बेचने के लिए बाजार चाहिए। उन उत्पादों के लिए दरवाजा खोलने के सिवा और बेहतर विकल्प क्या है। यह तो देश की सीमा शुल्क को कम करने का एक नाम मात्र है। यह हमने गैट के नाम पर किया है और हमें वहां अब और हस्ताक्षर करने के लिए जाने की जरूरत नहीं है वे जो कुछ भी चाहते थे। वो सब हमने कर दिया है और हमने ऐसा बगैर हस्ताक्षर के ही कर दिया है। हमने उनके उत्पादों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए है। हमने उनकी पूंजी के लिए दरवाजे खोल दिए हैं और जो उत्पादन नहीं है और यही तो हम उत्पादों के नाम स्पष्ट कर रहे हैं, पूंजी के प्रवाह के नाम पर कर रहे हैं।

महोदय, मैं चलते चलते चर्चा करना चाहता हूं जैसा कि हम जानते हैं कि वास्तविक उत्पादन उनकी चिंता का विषय नहीं है। उनकी चिंता का विषय अमेरिका है। दरअसल, अमेरिका के राष्ट्रीय आय का ढांचा आज ऐसा है कि सकल घरेलू उत्पाद का 75 प्रतिशत उनकी सेवाओं से आता है। यही वह मुद्रा है जिस पर वह ज्यादा जोर दे रहे हैं। यह सिर्फ गैट नहीं है, सेवा के क्षेत्रों में गैट भी है। सेवा वाले क्षेत्रों को खोलना होगा। हम यह जानते हैं। इतना ही नहीं, हम इसे निर्यात के संदर्भ में भी जाते हैं, अमरीकी अर्थव्यवस्था में, कृषि का पहले बहुत बड़ा अनुपात था। यह एक 64 प्रतिशत से 24 प्रतिशत तक आ गिरा है। सेवा वाला क्षेत्र और निर्यात क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। यही कारण है कि वे दबाव डालते है और यूरोपीय देशों से प्रतिरोध के बावजूद उन्होंने भारत में सफलता प्राप्त की है, क्योंकि हमने अपना निजी क्षेत्र के बैंकों को विदेशी पूंजी के लिए खोल दिया है, जैसा कि हमने बैंकिंग (विनियमन) अधिनियम पर चर्चा के दौरान पाया।

हम अपने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दे रहे है, जो कि इस देश के व्यक्ति विशेष तक ही सीमित नहीं है। और संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के बावजूद कि चार विदेशी बैंकों की लाईसेंस तक जब्त कर ली जाए, वे अपना परिचालन बढ़ा रहे है। यह एक ऐसा परिणाम है जो हमारी सीमा शुल्क और नई आर्थिक नीतियां हमारे देश में उत्पन्न कर रही हैं हम जानते हैं, महोदय, कि इसे नरीमन प्वांइट माननीय मित्र द्वारा भी पसंद नहीं किया जा रहा हैं।

प्रख्यात वक्ता श्री मुरली देवरा के अतिरिक्त अन्य दूसरे प्रख्यात वक्ता है नानी पालखीवाला है। उन्होंने भी कलकत्ता में बोलते हुए इस बात की आपत्ति की थी कि विदेशी निवेशकों का 24 प्रतिशत इक्विटी का अधिकार दिया जा रहा है। बड़बड़ाना भी सुनाई दिया था। अत: आप अगर इस तरह से निष्कर्ष निकाले तो यह पता चल सकेगा कि यह तरीका कितना गैर-जिम्मेदाराना है और कितना देश-विरोधी है और इसके पीछे विदेशी शक्तियां है। मैं नहीं कहता कि यह सिर्फ विश्व बैंक है क्योंकि वे भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कठपुतियां है।

मैं सिक्के के एक पहलू पर ही वापस आऊंगा। बजट में और आर्थिक सर्वेक्षण में, यह धारणा व्यक्त की गई कि इस वर्ष सकल घरेलू उत्पाद में विकास दर 4 प्रतिशत होगा। विकास दर की यह उम्मीद कृषि के 3.8 प्रतिशत विकास दर पर आधारित है। इस देश में अर्थव्यवस्था से या आंकड़े से जुड़ा कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है कि यदि कृषि में विकास दर 3.8 प्रतिशत है, जिसकी बहुत ही कम उम्मीद है, यदि निवेश की लागत भी शामिल कर ली जाए तो आय बहुत ही कम होगा। सभी पर्यवक्षेकों ने यह उल्लेख किया है। मैं आपकी दृष्टि में कोई खामी का उल्लेख नहीं करता कि राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू उत्पाद के मामले में कृषि में विकास दर से 4 प्रतिशत के सकल घरेलू उत्पाद का विकास दर नहीं प्राप्त हो सकता। मैं "धोखेबाजी" शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि आप इन धारणाओं का आशय लेकर स्वयं को धोखा दे रहे हैं।

लेकिन इस पर हमारा कर्तव्य होता है कि इस पर से पर्दा हटाएं और जनता की बीच जाएं और बताएं कि इस तरह सच्चाई नहीं दिखती हैं

मैं आपको एक-दो बातें बता दूंगा। यह जन-विरोधी क्यों है। पहला है, मूल्य संबंधी प्रश्न आप आश्चर्य कर रहे है कि किस तरह मुद्रास्फीति जो कुछ समय के लिए कम हो गया था, अब ऊपर बढ़ रहा है। मैंने संकेत दिया कि वर्ष 1992-93 के आंकड़े वर्ष 1992-93 के संशोधित आंकड़े से बिल्कुल अलग है। इसका मतलब यह हुआ कि वर्ष 1992-93 में घाटा-आंकड़े के संदर्भ में कम की गई राजस्व वसूली, जो बढ़ा गया है, के अर्थव्यवस्था में वर्ष 1993-94 में दबाव बढ़ता गया है। यही हो रहा है। मैं तो इस वर्ष के संशोधित आकलन संबंधी आपके वक्तव्य पर प्रश्न कर रहा हूं। आप कहते हैं कि, यह 58,000 करोड़ है।

आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि क्या यह दूसरा 40,000 करोड़ रूपये है जिसकी आपने अपनी पूरक मांगों में चर्चा की है, या क्या यह दबाव की बजह से है, जैसा कि हम जानते है कि किस तरह का दबाव में मुद्रास्फीति को बढ़ावा देने वाला है, आपने योगदान दिया है।

इसलिए, यह तथ्य आश्चर्यजनक नहीं है कि अच्छी भावनाओं के बावजूद मेरे दिमाग में कोई संदेह नहीं है और मैं चाहता हूं कि आप स्वीकार करें कि मुद्रास्फीति की दर इस वर्ष दो अंको तक पहुंच जाएगी। आप सभी जानते हैं कि सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्कों में परिवर्तन और इस तथ्य के बावजूद कि बजट के पहले प्रशासनिक मूल्यों में परिवर्तन से रेलवे से 4,100 करोड़ रूपये का और 1,000 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ और फिर 5,300 रूपये का इस सबसे एक ऐसा मूल्य ढांचा उत्पन्न हुआ, जिससे प्रसाधन सामग्री के मूल्यों में कमी आ रही है और खाद्य सामग्री की कीमतों में वृद्धि हो रही है। मैं जानता हूं कि बजट में भी प्रसाधन आवश्यक है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस बजट में प्रसाधन सामग्री पर ध्यान दिया गया है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : चुनाव भी आ रहे हैं।

श्री ए. चार्ल्स : गेंहू और चावल की कीमतें खुले बाजार में कम हो गई है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : तब भी लोग इसे खरीद नहीं सकते।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : यह बहुत ही आश्चर्य जनक अर्थव्यवस्था है कि जब संचालन मूल्यों में वृद्धि होती है तो खाद्य सामग्रियों की कीमतों में कमी आती है।

श्री ए. चार्ल्स : केरल में, पहली बार चावल और गेंहू की कीमत कम हुई है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : उत्पाद शुल्क में परिवर्तन के ढांचे जन विरोधी उपाय भी किए गए है। हम चाहते हैं कि उत्पाद शुल्क को खत्म कर दिया जाए, इस तथ्य को छोड़कर कि 45 प्रतिशत उत्पाद शुल्क राज्यों से आता है। हम चाहते हैं कि उत्पाद शुल्क से प्राप्त करने के स्थान पर, सीमा शुल्क को कम किए बिना निगमित कर और आयकर से यह धनराशि प्राप्त की जा सकती है। 85 प्रतिशत आयकर से और 85% कर भी इसमें जोड़ सकते हैं और यदि आप इससे ज्यादा रखते है तो उत्पाद शुल्कों में कम करने के पक्ष में है क्योंकि अंततोगत्वा उत्पाद शुल्कों का असर गरीब जनता पर पड़ता है। गरीब से गरीब आदमी भी कर के भार से बच नहीं सकता। उत्पाद शुल्क क्यों लगाया जाए ? प्रत्यक्ष करों के मामले में ऐसा नहीं है। यदि आप चाहें तो आप अमीर के लोगों पर भार डाल सकते हैं। आय उनसे प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं - श्री मणिशंकर अय्यर निश्चित रूप से जानते हैं - उस अत्यधिक राशि की कल्पना कीजिए। मैं सोचता हूं कि इसकी पुनरावृत्ति हुई है। उन दिनों स्टॉक बाजार का कारोबार 13 लाख करोड़ था। आपने इस बार यह परिकल्पना की है।

मुझे आश्चर्य हुआ है। मैं उस आधार पर गणना नहीं कर रहा था। अनुमानित कर में, आपने परिकल्पना थी कि यह 5 लाख रूपये से कम होनी चाहिए इसका अर्थ है कारोबार पर 7 प्रतिशत की धनराशि की प्राप्ति पिछले वर्ष के बजट में ऐसा किया गया था। यह इस वर्ष के बजट में भी किया गया। मैं गणना करने की कोशिश कर रहा था कि यदि यह कारोबार का 7 प्रतिशत है, तो 13 लाख करोड़ पर भी 3 प्रतिशत से 4 प्रतिशत का अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन इस वर्ष के बजट में उन्होंने बहुत ही अच्छी घोषणा की है। 50 लाख रूपये के कारोबार तक आप 8 प्रतिशत धनराशि की वापसी का अनुमान लगा सकते हैं। मैं निजी तौर पर 3 से 4 प्रतिशत तक की गिनती का प्रयास कर रहा था। अब कल्पना कीजिए कि 8 प्रतिशत की दर 13 लाख रूपये की आय प्राप्त होगी। यह 1,04,000 करोड़ रूपये है। 8 से गुना करने पर यह

बहुत ही सरल है। 40 प्रतिशत के कम दर से कराधान द्वारा भी आप कितना प्राप्त कर सकते थे ? 40,000 करोड़ रूपये, जैसा कि संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष साक्ष्य से स्पष्ट है। जब हर्षद मेहता समिति के समक्ष साक्ष्य के लिए आता था, तो वह कुछ मंत्रियों को औपचारिक रूप से 'हाय' कहा करता था।

श्री मणिशंकर अय्यर : वे अक्सर हाई-हाई कहा करते थे।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : आप यह नहीं चाहते कि मैं नामों का उल्लेख करूं। यही सब साक्ष्य में हुआ है।

अब, मैं उत्पाद शुल्कों की वसूली के विषय में उल्लेख करना चाहता हूं। मैंने पहले ही बताया था कि उत्पाद शुल्क को लघु उद्योग क्षेत्र पर ज्यादा लगाया गया है। ऐसा नहीं है कि इसे हटाया नहीं गया है। संसाधनों के आवंटन में पूरी स्थिति स्पष्ट है। मैं यह बताना चाहता हूं कि किस तरह यह जन-विरोधी है। सिर्फ लघु उद्योग ही नहीं बल्कि इस्पात क्षेत्र के लोग भी इसकी शिकायत कर रहे हैं। मुझे सभी कागजात प्राप्त हो गए है। शायद, बंगाली साथी चाहते है कि मैं बताऊं कि जूट उद्योग के साथ आप क्या कर रहे हैं। एक कानून पारित किया गया कि जूट के थैलों का सभी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसका उल्लंघन हुआ है क्योंकि वायु निगमित अधिनियम के मामले में इसका उल्लंघन हुआ है। कोई भी इसकी जांच नहीं करता। वे लोग प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने प्लास्टिक के थैलों के निर्माताओं को इस बजट में रियायत दी है। आपने जूट निर्माताओं के लिए भी समस्याएं खड़ी कर दी है। लेकिन आपने जूट उत्पादों पर विशेष शुल्क को नहीं बढ़ाया है। इसका सामान्य कारण यह है कि आपने यथामूल्यानुसार बना दिया है। विशेष शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। जूट उत्पादों पर शुल्क यथामूल्यानुसार बनाया गया है। इसका यह परिणाम निकला जूट उत्पादों पर कर में सौ प्रतिशत वृद्धि हुई है। यह सामान्य कारण अब वैज्ञानिक साबित हो गया है। लेकिन जूट उद्योग के साथ यही आपने किया है। मैं इस बारे में और चर्चा नहीं करूंगा।

अब मैं राज्यों के साथ आपके व्यवहार के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। यह व्यवहार कैसा है? क्या आप आंकड़े प्राप्त करना चाहते हैं? इस तथ्य के बावजूद कि इसमें कमी आई है, यहां इस पृष्ठ पर भी, यह कहा गया है कि जहां तक राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को कुल संसाधनों के स्थानांतरण का संबंध है इसके संशोधित प्राक्कलन 54,127 करोड़ है और बजट में प्रस्ताव 53,000 करोड़ रूपये है और किसी को भी आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि 53,000 रूपये 54,000 रूपये से कम है - मैं किसी ऐसे व्यक्ति बताना चाहता हूं जिसका बजट में उल्लेख भी नहीं किया गया है। इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। ब्याज के भुगतान के मामले राज्यों से केन्द्र सरकारों को स्थानांतरित की गई कुल राशि को इसमे शामिल नहीं किया गया है। ब्याज के भुगतान के मामले में 1994-95 में, आपने संशोधित प्राक्कलन पर 1431.69 करोड़ की अतिरिक्त राशि की मांग की है जो कि आप राज्यों से प्राप्त कर लेंगे। श्री मुरली देवरा ने स्वीकार किया है कि राज्यों को इस तरह पहले कभी नहीं वंचित किया गया - वास्तव में पहली बार भी कभी ऐसा नहीं हुआ था। कृपया इस मुद्दे का महत्व समझिये। वस्तुत: यदि आंकड़े मुद्रा स्फीति की दर की बजह से वहीं होते तो यह कम होता। इतना ही नहीं है। अपितु धनराशि के मामले में, राज्यों को स्थानांतरण के संबंध में संशोधित प्राक्कलन में पूर्ण कमी आई है। केरल एक ऐसा ही राज्य है। यह दूसरी बात है।

वित्त मंत्री चेलैप्पा समिति का उल्लेख करना चाहते हैं। वह इसे कार्यान्वित करने का प्रयास है। मैं चेलैप्पा समिति के प्रतिवेदन को नरसिंहन समिति के प्रतिवेदन से कही कम नकारात्मक समझता हूं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने परेषण कर का उल्लेख किया है। वह उस विषय में प्रसन्न ही है। लेकिन उन्होंने उल्लेख किया है दो प्रतिशत परेषण कर लगाया जाना चाहिए। क्यों ? परेषण कर का क्या औचित्य है? उन्होंने

कहा कि यह दूसरी कठिनाई है। इसके पीछे साधारण तर्क है कि आप कर चोरों से प्यार करते हैं।

हम सभी जानते हैं कि इसे बिक्री के रूप में दिखाने के स्थान पर माल को एक जगह से दूसरी जगह परेषित माल के रूप में भेजा जाता है। वे कहते हैं कि यह बिक्री के लिए नहीं है यहां किसी बिक्री कर की जरूरत नहीं है। यह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को किया गया स्थानांतरण है। हम प्रतिदिन सलाहकार समिति की बैठकों में और निजी चर्चा के दौरान भी डा० सिंह को इस बजट के विषय में बताते हैं। वित्त मंत्री को कहना चाहिए कि हम ज्यादा कर सकते थे क्योंकि यदि परेषित कर लगाया जाता, तो प्रतिवर्ष आप उन्हें 100 करोड़ से अधिक दिया गया होता। पश्चिम बंगाल राज्य की यह कहानी है। यही केरल राज्य की सच्चाई है और महाराष्ट्र में भी ऐसा ही है। आपकी सलाहकार समिति की बैठक में, राज्य सभा सदस्य श्री जगेश देसाई प्रतिवर्ष यह उल्लेख करते रहे हैं कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र सरकार यह चाहती है कि वहां भी ऐसा होना चाहिए। यह इसका दूसरा पक्ष है जिससे पता चलता है कि यह बजट किस तरह से राज्य-विरोधी है।

मैं दोपहर के भोजनावकाश से पहले अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आपको पर्याप्त समय मिला है। लेकिन आप यह उल्लेख नहीं कर रहे कि स्थायी समिति की बैठकों में आपने क्या चर्चा की है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह एक सलाहकार समिति है। अब दूसरी बात है जिसकी हम बार-बार चर्चा करते हैं। मुझे ठीक से याद नहीं कि क्या वह श्री राजीव गांधी की सरकार के समय में या बाद में जब वह वित्त मंत्री थे तो जीवन बीमा निगम सामान्य बीमा निगमों से तथा उन सभी संस्थानों से, भविष्य निधि की धनराशि जिनमें जो भविष्य निधि के खाते में जमा थी और जिनमें राज्यों का हिस्सा था, भविष्य निधि में से वापस ले ली गई और नया जमा खाता खोला गया था और जिसमें 8000 करोड़ रूपये वार्षिक जमा होते थे। हमारे बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद इसे वापस नहीं लिया गया। जब हम कहते हैं कि यह बजट जन-विरोधी है, उस दावे के बावजूद कि ग्रामीण विकास के लिए इतना अधिक धन दिया गया है क्या यह स्मरण रखने योग्य नहीं है कि ग्रामीण विकास और कृषि मुख्य रूप से राज्यों का विषय है। इन आंकड़े के बावजूद यदि आप राज्यों को इन संसाधनों से वंचित करते हैं तो, शायद ईश्वर ही इसकी प्रमाणिकता को जानता है वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों को धन का प्रवाह काफी कम हो जायेगा।

इसका एक ओर पहलू है। इस वर्ष स्टॉक (शेयर) बाजारों के बारे में और आंशिक रूप से क्योंकि हम अमेरिकन के करीब हैं और उनसे सलाह ले रहे हैं, सेवाओं पर एक नये प्रकार का कर लगाया गया है। आप उसका कितना प्रतिशत कर के रूप में राज्यों को देने जा रहे हैं। आपको 600 करोड़ रूपये प्रावधान करने का विचार है। अथवा आपका इरादा यह है कि सारी धनराशि राज्यों को दे दी जायेगी? यह सभी सरकारी उपक्रमों की राशि है क्योंकि हर्षद मेहता केन्द्रीय सरकार का व्यक्ति है। क्या सीमा शुल्क के रूप में एक भाग 45 प्रतिशत दिया जायेगा? आप पहले से ही न कह रहे हैं? इसलिए आप उन रास्तों और तरीकों को खोजने का प्रयास कर रहे हैं जिनके द्वारा राज्यों को इंकार किया जा सके और बाजार से, देश से अथवा अर्थव्यवस्था से प्राप्त नए धन संग्रह राज्यों को न दिये जाएं।

मैं अब विकास के पहलू पर विचार करता हूं। भाषण को देखे। आपने सोच लिया है कि कर प्रस्तावों के कारण आयी कमियों- मैंने पहले ही उल्लेख किया है - का अवशोषण कर दिया जायेगा और विकास 30 से 35 प्रतिशत तक होगा। उसकी आपने कल्पना की है। आपने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर की कल्पना की है जिसे तब तक प्राप्त करना असंभव है जब तक कि मुद्रा स्फीति न हो। मैं जानता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह निर्धन ही क्यों न हो, बचत करना चाहता है। गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्ति अपनी पत्नियों, बच्चों और शायद अपने लिए भविष्य के लिए बचत करते हैं ताकि वे अपनी पत्नियों और बच्चों को बचाने

के लिए कोई रोजगार प्राप्त कर सकें। परंतु धन संबंधी बचतों के संदर्भ में, ऊपरी धनी वर्ग, यू वर्ग, धनी वर्ग ही इसे वहन कर सकते हैं। आप बहुराष्ट्रीय सामान को सस्ता करके उन्हें लालच दे रहे हैं। वित्त मंत्री का कपड़े साफ करने की मशीन के उत्पादकों और श्रृंगार संबंधी सामानों के उत्पादकों का धन्यवाद किया है। इस प्रकार के उपभोग संबंधी व्यय से वे जो आय प्राप्त कर रहे हैं आप उसका अवशोषण करना चाहते हैं। क्या यहां विरोधाभास है? आपने पूर्ति पक्ष के अर्थशास्त्र पर जोर देना, छूट देना, उन्हें उत्पादन में लगने के लिए प्रलोभन का प्रयास करना आदि थैचर, फ्रैटमेन जैसे अमेरिकी अर्थशास्त्री से सीखा है। दूसरी ओर आप उन्हें सस्ते सफेद सामान पेश करके बचतों से अलग कर रहे हैं। क्या यह विकास की रणनीति है? क्या इस बारे में कोई शब्द है, क्या कोई ऐसा कदम उठाया गया है जिसके द्वारा गत चार या पांच वर्षों में गिरती बचत दर को बढ़ाया जा सकता है? मुझे आप एक भी उपाय दिखा दीजिए जो आप करे रहे हैं - जैसे ही मैं पीछे आता हूं यह एक पुनरावृत्ति ही प्रतीत होती है जिसके द्वारा विदेशी पूंजी के प्रवाह से निवेश का ध्यान रखा जायेगा? वास्तव में पूरी प्रक्रिया का परिणाम, जैसाकि आर्थिक सर्वेक्षण में स्वीकार किया गया है और डा० सिंह द्वारा भी दुर्भावना से स्वीकार किया गया है, औद्योगिक ढांचे का विकास होगा, यह पिछले वर्ष कुछ भी रहा हो, यदि तथ्य और आंकड़े स्वीकार किए जाते हैं तो पूंजीगत सामान संबंधी उद्योगों के निर्णायक ढांचे में गिरावट आयेगी।

बैठक आरंभ होने से ठीक पाचं मिनट पूर्व ही मेरे एक मित्र बता रहे थे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर काफी देर तक वाद-विवाद होता रहा। मैं सांख्यिकीय संस्थान में कार्य करता था, आप हमारी अर्थव्यवस्था की सफलता का मूल्यांकन कीजिए, यह वाद-विवाद वित्तीय संदर्भ में ही नहीं था अपितु भौतिक संदर्भ में भी था। वहीं अर्थशास्त्र का संतुलित सिद्धांत है। इसका श्रेय प्रोफेसर माहालानोबिस को जाता है जिनकी रूस में और अन्य देशों में भी कुछ अर्थशास्त्रियों ने सहायता की थी, ने योजना में वास्तविक पद्धति लाए थे। श्री चन्द्र शेखर जी निश्चित रूप से स्मरण करेंगे। हम इस बात पर जोर दे रहे थे कि 1947 के पश्चात् देश की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए, देश की राजनैतिक स्वतन्त्रता के लिए मूल क्षेत्र में विकास आवश्यक है। महोदय, क्या आप मुझे विस्तार से यह उल्लेख करने की अनुमति देंगे कि 'मूल क्षेत्र' से क्या तात्पर्य है। हम यहां पर प्रोफेसर माहालानोबिस की आलोचना करते हैं। प्रारूप के आरंभ में इस्पात उद्योग के उच्च विकास का प्रावधान था। इसमें मशीन निर्माण उद्योग का भी प्रावधान था। परंतु जब प्रारूप बना तो मशीन निर्माण पर अधिक बल नहीं दिया गया। जब तक आप मशीन का निर्माण नहीं करते जो मशीन यंत्र का निर्माण करती है जिससे इस्पात अथवा अन्य मशीनरियों का निर्माण होता है, आप मूलतः आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकते।

मैं देवरिया के नाम का उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि हम इसे पसंद नहीं करते। (व्यवधान) गत वर्ष जो हुआ वह यह है कि यह वही क्षेत्र था। जिसे अत्यधिक क्षति हुई। (व्यवधान) मैंने उल्लेख किया है कि हम प्रोफेसर माहालानोबिस की भी उस समय आलोचना की थी जब प्रारूप का प्रारूप उस प्रकार संशोधित किया गया था। वास्तव में हमारी आयु ने उस समय हमें ढीठ होने की अनुमति दी थी। (व्यवधान) वह भिन्न मामला है। परंतु मैं जो बात कह रहा हूं वह यह है कि आपने गत वर्ष अर्थव्यवस्था का जो मार्ग देखा है उससे ज्ञात होता है कि आप इस संदर्भ में अर्थव्यवस्था के औद्योगिकीकरण को समाप्त करने के रास्ते पर जा रहे हैं। इस बजट के सभी प्रस्ताव यदि सुदृढ़ करते हैं तो ऐसा पूंजीगत सामानों पर शुल्कों में वृद्धि करने के कारण नहीं है। कृपया मुझसे समान शुल्कों के बारे में बात न करें। गत वर्ष उन्होंने पूंजीगत-माल पर शुल्कों में कमी की थी जबकि मशीनों के लिए घटकों, पुर्जो और कच्चे माल की दरें उच्च स्तर पर थी। यह सब देश की वास्तविक अर्थव्यवस्था के मालिकों अर्थात् 'मुम्बई वर्ग' के लिए पचाना कठिन था। इसलिए कुछ संशोधन किये गये थे। परंतु इसके बाद भी गत तीन वर्षों के दौरान हम इतने कमजोर

हो गए है कि ये भी - हमें कहने का शौक था कि वे ही अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखते है; हम अधिक समय तक यह गर्व के साथ नहीं कह सकते- नियंत्रक नहीं है। अर्थव्यवस्था के नियंत्रक भारत में नहीं रहते हैं। उन्हें भी नुकसान नहीं हुआ है। वे पूंजीगत सामान उद्योग के मालिक हैं जो हमें आर्थिक स्वतंत्रता दे सकती है इसे 1994-95 में विकास के बारे में प्रबल कल्पनाओं के बावजूद विकसित नहीं किया जा सकता। विकास के लिए महोदय, आप वर्षा के लिए ईश्वर पर आश्रित हैं। यदि वर्षा होती है तो कृषि फलीभूत होती है। परंतु आप विदेशी सीधे निवेश पर निर्भर है जिसे आप प्रौद्योगिकी में लाने में विश्वास करते हैं। उसके असफल होने पर आप शेयर बाजार में उनका विनियोग कराना चाहते हैं।

मैं एक या दो महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करूंगा और अपनी बात समाप्त कर दूंगा। अथवा क्या आप चाहते हैं कि मैं अभी समाप्त कर दूं?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आप अभी समाप्त कर दें क्योंकि आपने एक घंटे का समय ले लिया है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, सुबह मैं आपकी उपस्थिति भी चाहता था ताकि आप हमारी सहायता कर सकें।

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं, उन पर विचार किया जायेगा।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, आपका धन्यवाद। अब मैं समाप्त करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, आपने उनकी बात ध्यान से सुनी जिससे पता चलता है कि आप इस पद्धति के प्रति वचनबद्ध है। परन्तु वित्त मंत्री ने यहां रहना ठीक नहीं समझा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। वे किसी अन्य कार्य में व्यस्त हो सकते हैं। उनके राज्य मंत्री यहां है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, वे मंत्रिमंडल की बैठक में भाग ले रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यदि परिनिर्धारण के लिए मंत्रिमंडल की कोई बैठक हो रही है तो हम उसका विरोध कर सकते हैं।

श्री चन्द्र शेखर (बालिया) : अध्यक्ष महोदय, हमेशा ऐसा ही होता है। अब जबकि बजट पर बहस हो रही है, तो मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है। मंत्रिमंडल के लिए ऐसी क्या अनिवार्यता थी? अध्यक्ष महोदय, हर रोज ऐसा होता है। मालूम नहीं इस सरकार को क्या हो गया है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं इस वित्त विधेयक के संबंध में आवंटन के स्वरूप और अन्य बातों के बारे में कहना चाहता था। परंतु मैं उसे उचित समय पर कहूंगा। **(व्यवधान)**

12.47 म.प.

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

नियम 331 छ(क) निलम्बन

अध्यक्ष महोदय : नियम 331 छ (क) में प्रावधान है कि बजट पर सामान्य चर्चा समाप्त होने के बाद अनुदानों की मांगे स्थायी समिति को भेजी जायेगी। ऐसी आशा थी कि सामान्य चर्चा आज समाप्त हो जायेगी। तथापि, सदस्यों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए सामान्य चर्चा मध्यावकाश के बाद जारी रखी जायेगी जिससे कि सदस्यों के बजट में शामिल सामान्य सिद्धांतों पर अपने विचार प्रकट करने के लिए और

अधिक समय भी दिया जा सके। अतः नियम 331 छ (क) का निलम्बन आवश्यक हो गया है और सामान्य चर्चा समाप्त होने से पहले अनुदानों की मांगों का स्थायी समिति को भेजने की अनुमति दी जाती है जिससे कि स्थायी समिति द्वारा अनुदानों की मांगों की जांच सरल हो जाये और वही रिपोर्ट सदन को मंत्रालय की मांगों पर अलग से चर्चा के लिए सदस्यों को दी जाती है।

मुझे आशा करता हूं कि सभा इस पर सहमत होगा - .

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

12.48 म.प.

सामान्य बजट, 1994-95 - सामान्य चर्चा - जारी

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मैं केवल एक मुद्दा और जोड़ना चाहता हूं। कृपया सुनिश्चित करें कि केन्द्र से कितना धन राज्यों को योजना के लिए दिया जा रहा है और कितना धन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को दिया जा रहा है।

आपने देखेंगे कि बजट से सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश में कमी आ रही है। यह एक विशेषता है। आपके गैर-योजनागत व्यय में वृद्धि हो रही है। यही मुद्दा अन्य सदस्यों द्वारा उठाया गया है। **(व्यवधान)** अतः मैंने भी इस मुद्दे को उठाने के लिए सोचा है।

मैं इस आंकड़े को उद्धृत नहीं करना चाहता हूं। अतः मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब हमारे पास कुछ समय है। मुझे कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को बोलने के लिए बुलाना चाहिए था। लेकिन मुझे प्रो० रीता वर्मा से एक पत्र मिला है। वह बोलना चाहती है क्योंकि उनको इसके बाद कुछ अन्य कार्य करने है। अतः मेरा विचार है, आप सहमत होंगे कि उन्हें समय दिया जाए और फिर कांग्रेस पार्टी को तथा फिर श्रीमती गीता मुखर्जी को तथा फिर अन्य सदस्यों को समय दिया जायेगा।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा (धनबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़े शायराना अंदाज में वर्ष 1993-94 का बजट प्रस्तुत किया है। मैं भी उनकी खिदमत में एक शेर अर्ज़ करना चाहती थी, पर इस समय वे हाउस में नहीं है। मैं राज्य मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि मेरा शेर वित्त मंत्री जी तक पहुंचा दे।

भूल कर भी न रीझे आप ऊपर की सफाई पर,
वर्क सोने का चिपकाया है, गोबर की मिठाई पर।

वित्त मंत्री महोदय का यह चौथा बजट है और हमें इससे कुछ इस तरह की अनुभूति हो रही है, जैसे "एलिस इन वंडर लैंड" हुई थी कि बहुत तेज चल रहे है, पर वास्वत में गति में कोई परिवर्तन नहीं आता सब कुछ यथावत रहता है। वित्त मंत्री जी की सारी आंकड़ों की बाजीगरी शब्दों के मोहक जाल और शायराना मिजाज के बावजूद तस्वीर के रूख में परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है।

पिछले तीन सालों से वित्त मंत्री जी लगभग एक सा बजट पेश कर रहे है और हर बार यह दावा किया जाता है कि यह बजट विकास को गति देगा। लेकिन राजकोषीय स्थिति इस समय 1990-91 की स्थिति से खराब है। उस समय आपने तर्क दिया था कि मुद्रास्फीति और बी.ओ.पी संकट के कारण राजकोषीय स्थिति संकटग्रस्त हो गई है। इस बार आप किसको दोष देंगे। इस बार ठीकरा किसके सिर फोड़ेंगे? लगातार छह

मानसून के बाद भी आज कीमतें औसतन दस प्रतिशत के हिसाब से प्रति वर्ष बढ़ रही है। पिछले तीन वर्षो में यह औसत दस प्रतिशत से भी ज्यादा रही है। सबसे ज्यादा दाम अनाज और खाद्यान्न के बढे हैं। माननीय सदस्य कह रहे थे कि किसी बाजार में कीमतें नहीं बढ़ी है, वे मुझे बता दे तो मैं वही से खरीदूंगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा उपलब्ध वस्तुओं के दाम इतने बढ़े है कि अब तो खुले बाजार से उनकी कीमतों में कोई फर्क भी नहीं रहा है। गेंहू, चावल, चीनी, मंहगी रसोई गैस, पैट्रोल -डीजल महंगा, साबुन महंगा, लोहा, महंगा और एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक की सभी दवाएं मंहगी और ब्लैक एंड व्हाईट टी. वी. सेट मंहगे, फिर आप कहते हैं कि बजट - कंज्युमर्स फ्रैन्डली - मेरा भारत महान।

वित्त मंत्री जी का चौथा बजट प्रश्नों के उत्तर देने की बजाय ढेर सारे प्रश्न खड़ा करता है और कुछ प्रश्न तो ऐसे है जिनका कोई उत्तर नहीं हो सकता। राजस्व घाटा दुगुना हो गया है जैसे 17 हजार करोड़ से बढ़कर 34 हजार करोड़ और बजट घाटा 4,300 करोड़ से बढ़कर 9 हजार करोड़ यानी दुगुने से भी अधिक और राजकोषीय घाटा 37 हजार करोड़ रूपयों से बढ़कर 59 हजार करोड़ रूपए हो गया है। अब वित्त मंत्री जी को वित्त मंत्री इसलिए बनाया गया था किं वे बजट घाटे को नियंत्रित कर देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को सुधारेंगे। लेकिन तीन वर्षों के बाद ऐसा लगता है कि उनके सारे आकलन तितर-बितर हो गए है और हम फिर वहीं पहुंच गए हैं जहां से चले थे। हर साल वित्त मंत्री जी कस्टम और एकसाईज ड्यूटी कम करते हैं। पिछली बार निजी आयकर में छूट दी गई थी और इस बार कारपोरेट टैक्स में कमी की गई है लेकिन शेयर बाजार अभी भी ठस पड़ा है। लोगों को उम्मीद थी कि बजट के बाद बाजार में उछाल आयेगा लेकिन वे सब चकित है कि आखिर यह माजरा क्या है। 1990 के बाद के चारों बजट निजी क्षेत्र का कार्यक्षेत्र बढ़ाने और सरकार क्षेत्र को सीमित करने के उद्देश्य से बनाए गए थे। अब ठीक इसके उल्टा हुआ। जी डी पी में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान 1990-91 का 26.2 प्रतिशत से बढ़कर 27.2 प्रतिशत हो गया है। इससे स्पष्ट होता है कि सतही तौर पर बजट में जो नजर आता है उससे वास्तविकता का मेल खाना जरूरी नहीं है। जितनी ज्यादा विकास की बात बजट में कही जाती है हमारे औद्योगिक विकास में उतनी ही मंदी आ गई है। नयी आर्थिक नीतियों के 2 वर्ष 9 महीने पूरे होने के बाद हमारी अर्थव्यवस्था स्टैग-फ्लेशन के दौर में आ गई है। विदेशी वस्तुओं की तुलना में स्वदेशी वस्तुएं महंगी होती जा रही है और आयात की मांग बढ़ती जा रही है। फिर भी लगता है कि बी ओ पी की स्थिति नियंत्रण में है। विदेशी मुद्रा का अच्छा भंडार देश में हैं। यह राशि आपके पुरूषार्थ से कमाई हुई राशि नहीं है यह कर्ज की राशि है पर यह राशि हमने शेयर बेचकर, जमाधन लेकर तथा विदेशी निवेश आकर्षित कर इकट्ठा की है। यदि सचमुच कोई देश की देनदारियों से चिंतित है तो विदेशी वित्तीय निवेशकों से आया धन, एन आर आई का जमा धन, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट्स, यूरो कनवरटिबल बान्डस आदि सभी देनदारियां सब मिलकर 95 अरब डालर से ऊपर ही हैं। काफी धन तो हाट मनी है जो पहला संकट आते ही फुर्र से उड़ जायगा और जाते-जाते हमारा भी कुछ साथ ले जाएगा। यह क्षणिक चमक बड़ी लुभावनी पर बड़ी मायावी है।

लेकिन सबसे विचित्र बात तो यह है कि जिस चीज को वित्त मंत्री अपनी खूबी बता रहे है उसी को खत्म करने की पूरी कोशिश इस बजट में उन्होंने की हैं। पिछले तीन महीनों से सरकार अपनी पीठ ठोंक रही है कि आयात घटा है इसलिए वाणिज्य संतुलन बेहतर हुआ है। जाहिर है कि इससे अर्थव्यवस्था को कुछ फायदा तो हुआ ही है। फिर भी वित्त मंत्री आयात बढ़ाने की नीति को बढ़ावा दे रहे हैं, वह भी घरेलू उद्योगों की कीमत पर। सरकार ने अपनी कमियों को छिपाने के लिए कई बहाने ढूंढे है। पहले तो स्कैम के कारण स्टाक एक्सचेंज सुस्त पड़े थे। दूसरा आपका पेटेंट बहाना है अयोध्या की घटना का जिसकी जिम्मेदारी आप अपनी हर कमी के लिए और हर दोष को छिपाने के लिए बोल देते है, इससे बड़ा छल कोई दूसरा नहीं होगा, इससे बड़ा झूठ कोई दूसरा नहीं होगा। वास्तव में आपकी नीतियां इसके लिए जिम्मेदार है। विदेशी

पूंजी और आयात को जो आप विशेष प्रोत्साहन दे रहे हैं उसके कारण ही उद्योग धंधे चौपट हो रहे है।

दरअसल भारतीय उद्योग में वृद्धि सरकार की प्राथमिकता रही ही नही है। कस्टम डयूटी के ढांचे की वे विषमतायें खत्म नहीं की गई है जो घरेलू उद्योगों के खिलाफ जाती है। विदेशों से कच्चा माल मंगाने पर अभी भी ज्यादा डयूटी देनी पड़ती है और बनी बनाई मशीने मंगाने पर कम। इसी का नतीजा है कि देश में मशीनें बनाना महंगा है और मशीनें आयात करना सस्ता पड़ता है।

हर सरकार को कम से कम कोर सेक्टर की जिम्मेदारी अपने तक सीमित रखनी चाहिए। सर्विस सैक्टर भले ही प्राइवेटाइज किया जाये। लेकिन कोर सेक्टर इतना महत्वपूर्ण होता है कि उसके प्रति सरकार की सद्भावना होनी ही चाहिए। मेरा क्षेत्र धनबाद, जिसमें बोकारो भी सम्मिलित है, नई अर्थ नीतियों के दंड भुगत रहा है। अभी ये दंड कई गुना और बढ़ने हैं। फ्रैट इक्वलाइजेशन के बाद इस्पात उद्योग को फायदा तो हुआ था, लेकिन आपकी नई नीति से विदेशी इस्पात उत्पाद भारतीय उत्पाद के मुकाबले सस्ता पड़ रहा है। रेल बजट में भाड़ा बढ़ा और आम बजट में उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया। इस प्रकार से आपने आयात शुल्क घटा दिया तो इसका नतीजा यह हुआ कि सेल सीधे 350 करोड़ रूपयों के घाटे में आ गया। उसके उपर यह भार बढ़ा दिया । वह दिन दूर नहीं जब भारतीय इस्पात उद्योग का उत्पादन तेजी से नीचे गिरेगा और बाजार की जरूरत आयातित स्टील पूरा करेगा। वही हालत कोयला उद्योग की है। अब आयातित धुला हुआ कोयला देशी धुले हुए कोयले से ज्यादा सस्ता पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से कोल इंडिया ने कुछ मुनाफा कमाना शुरू किया था कि आपकी खतरनाक, दृष्टि उस पर पड़ गई । जब कोर सेक्टर की यह दुर्दशा है तो उर्वरक उद्योग की तो नई सरकार के आते ही राहू ने ग्रस लिया। विदेशी कंपनीज स्नेम प्रोगेति और हल्डर टोप्सो को फायदा दिलाने के लिए अपनी भारतीय कंपनी पी.डी.आई एल. का कैसा सत्यानाश किया गया यह काला इतिहास है। पी.डी.आई.एल की गुणवत्ता सर्वविदित है और अच्छी खासी राशि खर्च करके उसे स्नेम प्रोगेति से टेक्नोलाजी ट्रांसफर की गई । फिर भी कंसल्टेसी स्नेम प्रोगति को ही मिली-थाल प्रोजेक्ट में और उसे 150 करोड़ रूपये इसके लिए दिये गये। अभी भी सारा काम तो पी.डी.आई.एल करती है, कमेटी कंट्रेक्टर के रूप में, यद्यपि उसके कोटेशन सबसे कम रहते है और गुणवत्ता विदेशी कंपनीज के समकक्ष है। अभी वे पी.डी.आई.एल मैदान में रहने के कारण विदेशी कंपनियों ने अपने टेंडर में 70 प्रतिशत तक की कमी कर दी है। जैसा कि हल्डर टोप्सो ने नागार्जुन के केस में किया था। लेकिन जब पी.डी.आई.एल मैदान में नहीं रहेगी तब यह विदेशी कंपनीज देश को अच्छी तरह से लूटेगी। सरकार के पास बहाना है कि पैसा नहीं है। मैं कहती हूं कि पी.डी.आई.एल. ने विदेशी कंपनीज की प्रतिस्पर्धा में आकर देश के कितने रूपये बचाये हैं, उनका हिसाब सरकार दे। और वह रूपया पी.डी.आई.एल. को दिया जाये। क्योंकि वही इसका वास्तविक हकदार है। परंतु ऐसा करने से सरकार विदेशी कंपनीज को खुश कैसे करेगी? अभी भी 1200 टन उत्प्रेरक प्रति वर्ष आयात किया जाता है। लेकिन दूसरी और पी.डी.आई.एल 600 टन उत्प्रेरक बनाता है, उसकी बिक्री नहीं होती है। जबकि उसकी गुणवत्ता विदेशी कंपनीज से किसी भी तरह कम नहीं है। यह क्या गोरख धंधा है।

1.00 म.प.

इसके अलावा हैवी वाटर प्लांट का निर्माण करने वाली देश की एकमात्र एजेंसी पी.डी.आई.एल. है। इसके बंद होने से परमाणु प्रौद्योगिकी क्षेत्र में देश को पंगु बन जाने का खतरा रहेगा। मेरा वित्त मंत्री से निवेदन है कि वे पी डी आई एल को इतनी मुद्रा दे दे जो उसने बचायी है क्योंकि यह उसका हक बनता है। इसी तरह सिन्दरी की फर्टिलाइजर फैक्टरी के आधुनिकीकरण के लिय पर्याप्त राशि अलाट की जाये क्योंकि यह संयंत्र अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन कर रहा है। हर सरकारी उद्योग बंद करने के लिये आप

रिसोर्स क्रंच करने की बात करते हैं लेकिन वास्तविकता क्या है? एक उदाहरण इसको का है, जिसकी 1500 करोड़ रूपये की संपत्ति को आप कोड़ियों के मोल बेच रहे है, और वह भी 135 करोड़ रूपये में । जब तक वह राशि आपके हाथ में पहुंचेगी तब तक उसका मूल्य 92 करोड़ रूपये से अधिक नहीं रहेगा। हम निजीकरण का विरोध नहीं करते लेकिन क्या देश की संपत्ति को कोड़ियों के मोल बेच कर बंदरबांट की जा सकती है। कम से कम मूल्य तो पूरा लिया जाये। इसी तरह सरकार खर्चे घटाने की बात तो बार बार करती है लेकिन ये तब तक नहीं घट सकते हैं जब तक भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको और कितने समय की आवश्यकता है क्योंकि हमें निर्णय लेना है कि हम अभी चर्चा जारी रखें या भोजन अवकाश के बाद इसको करें।

प्रो. रीता वर्मा : महोदय, मैं केवल 7-8 मिनट और लूंगी।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप भाषण जारी रख सकते हैं।

प्रो. रीता वर्मा : मेरे क्षेत्र में बोकारो इस्पात संयंत्र है। इस संयंत्र में न जाने कब से चोरियां हो रही है और वे भी उच्च पदस्थ लोगों के प्रश्रय और सरंक्षण में। इन चोरियों का मूल्य खरबों रूपये से ऊपर है परंतु देश की संपत्ति को लूटा जा रहा है और किसी को होश नही है। मैं आपके द्वारा मांग करती हूं कि इन चोरियों की सीबीआई के द्वारा जांच करायी जाये और दोषी लोगों को दंडित किया जाये चाहे वह कितने भी उच्च पद पर ही क्यों न हो। हद की बात तो यह है कि बोकारो संयंत्र की चारदीवारी का एक बड़ा हिस्सा खुला छोड़ दिया गया है और जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा प्रदान करने के बाद भी लोग उसे घेरने के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। इसीलिए कहती हूं कि जब तक उच्च पदस्थ लोगों के भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगेगा तब तक आपके खर्चे नहीं घट सकते हैं। इसी भ्रष्टाचार के कारण कुमारधुवी फायर ब्रिक्स लि. बंदी के कगार पर है और वहीं पर प्राइवेट कंपनियां खूब मुनाफा कमा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब आप विदेशी ऋण से चलने वाले प्रोजेक्ट्स पर एक नजर डालें क्योंकि उसका सरकार बहुत प्रचार करती है। बिहार में राजमहल परियोजना कनाडा सरकार की मदद से चलायी गयी है। करार के मुताबिक इस परियोजना को सादे पांच साल मे पूरा कर देना चाहिए था और 6 महीने में अपनी सफलता का सबूत दे देना था लेकिन नहीं हुआ कनाडा सरकार ने 966 करोड़ रूपये का ऋण दिया जिसमें 550 करोड़ रूपये मशीनों के लिये इक्विपमेंट ट्रांसफर के रूप में आये, 105 करोड़ कंसलटेंसी के लिये, 175 करोड़ रूपया खदानों के विकास के लिये दिये गये और जाहिर है कि कनाडा की कंपनी ने ही यह सब किया और यहां तक कि मैटकैम कंपनी ने कल-पुर्जे भी सप्लाई किये। कोयला उत्पादन का प्रतिदिन लक्ष्य 10.5 मिलियन मीट्रिक टन रखा गया लेकिन 5 साल के अंदर भी प्रतिदिन उत्पादन 6 मीट्रिक टन से ज्यादा नहीं कर सके। यद्यपि 6 महीने के डिमास्ट्रेशन के बाद लक्ष्य प्रतिदिन 69 हजार टन किया गया लेकिन यह भी नहीं हो सका। फिर क्या करना चाहिए। चलो लक्ष्य ही घटा दिया जाए? आपने भी उसको और घटाकर 56 हजार टन प्रतिदिन कर दिया। लेकिन यह लक्ष्य भी पूरा नहीं कर सके। लक्ष्य पूरा न कर पाने की स्थिति में इस कंपनी मैलकैम को 25 करोड़ रूपये की पैनल्टी देनी थी लेकिन इसको बचाने के लिए आपने लक्ष्य ही घटा दिया। दूसरी तरफ कंपनी ने नये-नये बहाने गढ़ने शुरू कर दिये। हालत यह है कि बिक्री मूल्य से भी उत्पादन लागत बढ़ गयी है। बिक्री मूल्य 218 रूपये से 339 रूपये है कर दिया लेकिन लागत है 315 रूपये और इस प्रकार एक टन पर आपको घाटा हो रहा है 76 रूपये का। मैं आपको एक उदाहरण देती हूं कि यदि मैं खराब खाना बनाती हूं और बाहर से होटल का कुछ मंगाकर खाना बनवाती हूं और काफी पैसे खर्च करती हूं और वह भी मुझसे खराब खाना बनाये।

तो फिर इस इंवैस्टमेंट का क्या फायदा हुआ? जब वहां के इंजीनियरों ने हल्ला किया, राजमहल के इंजीनियर्स ने हल्ला किया तो उनको भी फोरेन ट्रिप्स पर, विदेशों की सैर करने के लिए, ट्रेनिंग के बहाने भेज दिया गया, यानी इंजीनियर भी खुश, कोल इंडिया भी खुश और मैटकेम और कनाडा सरकार भी खुश, लेकिन देश को इस कारण जो घाटा हुआ, उसकी किसी को परवाह नहीं है।

राजमहल परियोजना सिर्फ शोपीस बनकर रह गयी। करोड़ों रूपये के वेल्यू की मशीनों का कोई अता-पता ही नहीं है कि वे विदेश से आयी भी नहीं या राजमहल से गायब हो गयी। विदेशी सहायता की ज्यादातर जगहों में यही तस्वीर है।

आपके खुद के निष्पादन बजट के अनुसार बोकारो इस्पात संयंत्र में भी विदेशी सहायता के ऐसे ही परिणाम सामने आये है। इस संबंध में आवश्यक प्रमाण मैं अपने साथ लायी हूं जिससे विदेशी सहायता के परिणाम आपको देखने को मिल जायेंगे। आपके ही अनुसार "बोकारो इस्पात संयंत्र' को अपने निर्धारित निष्पादन और 40 लाख टन क्षमता को प्राप्त करने में विभिन्न उपकरणों का कार्य निष्पादन बेमेल होने और हिस्से पुर्जो आदि की अधिकता होने के कारण गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या विभिन्न विदेशी स्त्रोतों से प्राप्त ऐसे अनेक उपकरण, जो अब अप्रचलित हो गये है और विदेशी स्त्रोतों द्वारा अतिरिक्त कलपुर्जे न सप्लाई किये जाने के कारण और अधिक बढ़ गयी है।

मुझे समझ में नहीं आता कि हम ऐसी विदेशी सहायता के लिय आंखे मूंद कर क्यों भाग रहे हैं और इतना ऋण लेने के बाद भी हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके तो बिना ऋण लिये, क्या हमारे इंजीनियर इससे कम पुरूषार्थ दिखाते। स्वदेशी का रास्ता कठिन अवश्य है परंतु वही एकमात्र रास्ता है जिससे हम देश को आगे ले जा सके हैं। विदेशी ऋण तो एक छलावा मात्र है, मृग मरीचिका है। इस मृग मरीचिका के पीछे हम पावर सैक्टर में भी आंख मूंदकर दौड़े जा रहे हैं। विदेशी कंपनियों को विदेशी मुद्रा में 16 प्रतिशत रिटर्न हम किस दुस्साहस से गारंटी कर रहे है और किस दाम पर उपभोक्ताओं को बिजली देंगे। अमेरिका जैसे देश में भी विद्युत एक अत्यधिक नियंत्रित वस्तु है परन्तु हम तो खुली लूट का मौका दे रहे है। अब तो सुना गया है कि आपने 16 प्रतिशत रिटर्न देने का मन बना लिया है यानी बिजली भी अब सिर्फ सम्पन्न वर्ग के उपभोग की वस्तु रह जायेगी।

छलावा यहां तक ही सीमित नहीं है। खुद सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण कहने के लिये तो 'श्रम प्रधान' आर्थिक वृद्धि की बातें करता है परंतु वास्तव में यह अंधाधुंध मशीनीकरण और व्यापक छंटनी की ओर बढ़ रहा है। हो सक्ता है कि सरकार इसी सत्र में एक्जिट पॉलिसी भी घोषित कर दे परंतु दावा ठीक इसके विपरीत किया जा रहा है। इन खोखले वायदों की असलियत क्या है - प्रचार किया जा रहा है कि ग्रामीण विकास के तहत गरीब हितैषी काम किये जायेंगे और इसके लिए बजट के प्रावधानों को 5603 करोड़ रूपये से बढ़कर 7010 करोड़ रूपये कर दिया गया है ताकि 115 करोड़ काम के दिनों के रोजगार अवसर पैदा किये जा सके, देखने में तो यह सपना बहुत सुहावना लगता है लेकिन हकीकत को हम आँखों से ओझल नहीं कर सकते कुल 150 करोड़ रूपये के सरकारी खर्च में गरीब का हिस्सा 7 हजार करोड़ है यानी 4.6 प्रतिशत तथा 115 करोड़ काम के दिनों का अर्थ 25 करोड़ ग्रामीण जनता के लिये साल में 5 दिनों का रोजगार सिर्फ 5 दिनों के रोजगार से क्या बनने वाला है जबकि ग्रामीण जनता के असली रोजगार यानी कृषि पर तो हमारे वित्त मंत्री जी को भृकुटी हमेशा टेढी ही रहती है आंकड़े इसके साक्षी है कि 1994-95 के बजट में सिंचाई क्षेत्र के लिये आवंटन राशि 6 प्रतिशत कम कर दी गयी है। जिससे मेरे क्षेत्र के लोगों को इस साल भी पानी के लिय तरसना पड़ेगा। दूसरी असुविधाये भी ज्यों की त्यों है। एक ओर तो सरकार रीजनल इम्बैलैंस को दूर करने की बात करती है परंतु हमारे धनबाद को अभी तक वायु सेवा तक से नहीं गया

है। यही बात जमशेदपुर पर भी लागू होती है और कोई फास्ट ट्रैन तक नहीं है। बिना इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा किये आप रीजनल इम्बैलेंस को कैसे दूर करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा विचार है कि आप आग से खेल रहे है। ऊपर से तुर्रा यह है कि सरकार ने तो लगता हे एक नियम ही बना लिया है कि बजट सत्र से पहले सभी आवश्यक चीजों के दाम बढ़ा दिये जाये ताकि बजट बेहद मासूम और निर्दोष दिखाई दे। यदि बाद में आवश्यकता हो तो साल के अंत में या इससे पहले कभी भी रेट बढ़ाये जा सकते हैं। हमारे लोकतंत्र का यह मूलभूत सिद्धांत है कि नो टैक्सेशन विदाउट रिपेजैटेशन परंतु ऐसा लगता है कि यह सरकार लोकतंत्र और संसद की अवज्ञा करने पर तुली हुई है। वैसे भी सरकार से जो हेराफेरी के आंकड़े दिये है, उनसे उसकी विश्वसनीयता पर बड़ा प्रश्नचिन्ह लग जाता है।

अरे हां मैं एक महत्पवूर्ण बात करना तो भूल ही गयी। मैं स्वयं एक कामकाजी महिला हूं और दूसरी कामकाजी महिलाओं के हितों की रक्षा करने का दायित्व मुझ पर है। पिछले साल वित्त मंत्री जी आपने कामकाजी महिलाओं के लिये स्टैंडर्ड डिडक्शन 18 हजार रूपये किया था परंतु इस साल मैं यह देख कर चकित हूं कि उसे घटाकर 17 हजार रूपये कर दिया गया? आपके जैसे शायराना मिजाज और गैलेट महानुभाव से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। आपसे जरूर कोई भूल हुई है। मेरी मांग है कि आप अपनी भूल के परिमार्जन के लिए कामकाजी महिलाओं के लिये स्टैन्डर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 25 हजार रूपये कर दे क्योंकि कामकाजी महिलाओं की संख्या बहुत थोड़ी है। आप कह सकते है कि हमने कास्मैटिक पर तो टैक्स घटा दिया है परंतु इससे हमें क्या लेना-देना। यह तो आपके फायदे की चीज है।

इन परिस्थितियों में, सरकार का नया बजट एक प्रवंचना मात्र है जिसमें तथ्यों का अभाव है और केवल मुलम्मा ही मुलम्मा है। आदरणीय वित्त मंत्री जी मैं आपको लिंकन की एक उक्ति ध्यान में लाना चाहूंगी कि आप सब लोगों को कुछ दिनों के लिए मूर्ख बना सकते है, कुछ लोगों को सब दिन के लिए मूर्ख बना सकते हैं परंतु सभी लोगो को सब दिन मूर्ख नहीं बना सकते। मुझे खेद है कि इस बार भी आप सुगृहिनी नहीं बन सके। इस गरीब विरोधी और जन विरोधी बजट के प्रति में अपना पूर्ण विरोध व्यक्त करती हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या अब हमें भोजनावकाश करना चाहिए? बहुत से सदस्य बोलना चाहते है। यह अच्छा होगा यदि हम भोजन अवकाश के दौरान में चर्चा जारी रखते है क्योंकि इससे कुछ सदस्यों को बोलने के लिए अधिक समय मिल जायेगा। ठीक है आप में से जो सदस्य भोजन के लिए जाना चाहते हैं, जा सकते है और भोजन के बाद वापिस आ जायें। हम सामान्य बजट पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

प्रो० पी.जे. कुरियन : यहां नहीं है श्रीमती गीता मुखर्जी । आप के बाद प्रो० पी. जे. कुरियन बोलेगें।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : कल, मैं पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग की स्थिति पर एक विशेष मुद्दा उठाना चाहती थी लेकिन आपने मुझे इसे सामान्य बजट पर चर्चा में हिस्स लेते समय उठाने की सलाह दी। अत: मैं स्वयं को न केवल उस मुद्दे तक ही सीमित रखने का प्रयास करूंगी बल्कि एक मुद्दा और भी उठाना चाहूंगी। उस पर चर्चा करने से पूर्व मैं आपको समग्र राष्ट्रीयकृत उद्योग और हमारे राष्ट्रीय उद्योग जो निजी हाथों में है, की और सरकार के रवैये के बारे में बताना चाहूंगी। बहुत से सदस्यों ने वर्तमान सरकार के रवैये के बारे में कुछ न कुछ कहा है। अत: मैं उसे दोहराना नहीं चाहती। मैं केवल एक उदाहरण दूंगी।

पिछले वर्ष, 700 करोड़ रूपये की लागत से 20,000 टन यूरिया का आयात किया गया था। उस समय हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन को बंद रखा गया था।

1.14 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

दि हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन ने सरकार से अपील की थी कि यदि सरकार उन्हें 140 करोड़ रूपये दे तो वे कम लागत पर यूरिया का उत्पादन कर सकते हैं। और इसे आयात लागत की तुलना में काफी कम मूल्य पर देगे। लेकिन सरकार ने धन नहीं दिया। आप उनके लिए 130 करोड़ नहीं दे सकते थे लेकिन आप यूरिया आयात करने के लिए 700 करोड़ रूपये खर्च कर सकते थे। यह आपका रवैया है। वे राष्ट्रीयकृत जूट मिलों से भी खिलवाड़ कर रहे हैं।

मैं विशेष रूप से पटसन उद्योग पर ही बोलूंगी क्योंकि पश्चिमी बंगाल के लाखों लोगों का भाग्य उस पर निर्भर है और यह उनकी सबसे बड़ी समस्या है।

पटसन उत्पादकों और कर्मकारों की तादद काफी है। महोदय, आप शायद जानते हैं कि पटसन उद्योग में संकट की वजह से पश्चिम बंगाल में काफी संख्या में आत्महत्याएं हो रही हैं। वस्त्र मंत्री की सलाह पर राष्ट्रीयकृत पटसन कारखानों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया गया था। मैं भी उस समिति के बद्‌किस्मत सदस्यों में से एक सदस्य थी। हमसे यह कहा गया था कि हम राष्ट्रीकृत पटसन कारखानों को पुनरूज्जीवित करने के लिए सरकार की हर प्रकार से सहायता करेंगे। कलकत्ता में सभी संघों के साथ बैठकें हुई थी। उन्होंने कारखानों को युक्तियुक्त बनाने और व्यय कम करने के अनेक सुझाव दिए। हमारा विचार था कि कुछ बातों पर ध्यान दिया जाएगा परंतु किसी पर भी ध्यान नहीं दिया गया।

आज मेरे एक प्रश्न के उत्तर में वस्त्र मंत्री ने बताया है कि एन.जे.एम.सी. की आधुनिकीकरण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्ष 1993-94 के बजट में 4 करोड़ रूपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। महोदय, यह अत्यधिक राशि है और यह कैसा दोहरा व्यवहार किया गया है? मैं विशेष रूप से इस मुद्दे को उठाना चाहती हूं। जब यह उत्तर सदन में दिया जा रहा था तो, उसी समय भारतीय औद्योगिक पुनर्गठन बैंक ने 28 फरवरी के 'बिजनेस स्टैन्डर्ड' में एक विज्ञापन दिया, जिसमें निजी उद्यमियों को इन्हीं कारखानों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने, अर्थात् खरीदने के लिए कहा गया था। यह विज्ञापन मेरे पास है। ये छ: कारखाने है, इनमें से पांच पश्चिम बंगाल में है और एक बिहार में है। इससे सरकार का क्या तात्पर्य है?

एक और तो वे निजी उद्यमियों को इन मिलों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए विज्ञापम दे रहे है और दूसरी ओर प्रश्न के उत्तर में हमें बता रहे हैं कि सरकार यह कार्यवाही कर रही है और इसके लिए चार करोड़ रूपये दिए गए है।

वास्तव में, निजी उद्यमियों को क्यों आमंत्रित किया जा रहा है? किन लोगों ने इन कारखानों को रूग्ण बनाया है; आज, वे कौन लोग हैं जो अपने कारखानों को रूग्ण बना रहे हैं? इनमें केवल भारतीय लोग ही नहीं है। यह कैसी विकट स्थिति है? वास्तव में आर.जे. ब्रेयर्ली नामक ब्रिटेन के एक नागरिक ने भारतीय रिजर्व बैंक से आवश्यक स्वीकृति मिलने पर टीटागढ़ टैगोर जूट फैक्टरी, जिसकी 4 इकाईयों में करीब 20,000 कर्मचारी कार्यरत हे, का अध्यक्ष पद और उसके चार अंग्रेज अधिकारियों ने कर्मचारियों और सरकारी प्रतिनिधियों से अशिष्टतापूर्ण व्यवहार किया ब्रेयर्ली के अधिकारियों ने इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया। जहां तक कर्मचारियों का संबंध है, इनके साथ हुए दुर्व्यवहार का उल्लेख नहीं किया जा सकता। अत: पटसन उद्योग के मामले को निजी उद्यमी समग्र रूप से इस प्रकार सुलझा रहे हैं। कई निजी इकाईयों को तो दलाल चला रहे हैं। कनोरिया जूट मिल में हुई घटनाओं से वहां पर व्याप्त असंतोष का पता चलता है।

सरकार राष्ट्रीकृत इकाईयों के मामले में क्या कर रही है? सभी संघ मिलजुल कर इस प्रश्न पर चर्चा करने के लिए यहां आए थे। एक त्रिपक्षीय बैठक भी हुई थी। वे सरकार से यह निवेदन करते रहें है कि एक पटसन नीति बनाएं और निर्णय करे कि वह क्या करना चाहते हैं। परंतु सरकार ने अभी तक कोई पटसन नीति तैयार नहीं की है और इसी दौरान ये घटनाएं घट रही है। एक के बाद एक कारखाना बंद हो रहा है। क्यों? यह सभी धन की कमी के नाम पर किया जा रहा है।

जैसा कि मैंने कहा मैं बहुत ही संक्षिप्त में बोलूंगी। मैं दूसरी अन्य बातों पर नहीं जाऊंगी। मैं यह जानना चाहती हूं कि धन की कमी क्यों है। मैं अपने सहयोगियों द्वारा कही गई बातों का जिक्र नहीं करूंगी।बहुराष्ट्रीय कंपनियों के समक्ष झुकने का प्रश्न भी है। मैं कोई आंकड़े भी उद्धृत करना नहीं चाहती हूं।

मैं एक बात जानना चाहती हूं। क्या इस धन की कमी का कोई विकल्प नहीं था? इस बजट में निर्धारित धनराशि को किस प्रकार व्यय किया जाता है? इस बजट में व्यय के तीन मुख्य क्षेत्र है।

एक है विदेशी ऋणों पर ब्याज की अदायगी इस पर मैं बाद में बोलूंगी। दूसरा है रक्षा; इस पर व्यय को समझा जा सकता है। तीसरा है, अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा। अब हमारे देश के बजट में अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा व्यय का तीसरा अति महत्वपूर्ण मद है। यह क्या है? क्या हमारा देश इस व्यय को वहन कर सकता है। इससे पहले, मैं जब पहले बजट पर बोली थी तो मैंने वित्त मंत्री से पूछा था कि इससे उनका क्या तात्पर्य है। वे मोटर साइकिलों पर जा सकते है। हमें इन चीजों की क्यों जरूरत है? अगर सुरक्षा द्वारा ही किसी को बचाया जा सकता है तो श्री राजीव गांधी की हत्या ऐसे नहीं हुई होती और इसके अलावा श्रीमती इंदिरा गांधी की भी हत्या नहीं हुई होती। सरकार ने इस प्रावधान को कम करने के बजाय उसे तीसरा अति महत्वपूर्ण मद् बना दिया है।

प्रो० पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) : श्री राजीव गांधी को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यदि नहीं, तो वह आपका कार्य था। इससे स्पष्ट होता है कि सुरक्षा इसका वास्तविक समाधान नहीं है। वे केवल फालतू खर्च कर रहे हैं। .... **(व्यवधान)** किसी भी रूप में, अति महत्वपूर्ण व्यक्ति कितने ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, हमारा देश उनकी सुरक्षा पर व्यय को तीसरी प्राथमिकता नहीं दे सकता। यह मैं अच्छी तरह से स्पष्ट कर देना चाहती हूं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय ने कृपापूर्वक सभा में घोषणा की थी कि आज भोजनावकाश नहीं होगा और सदन की लगातार बैठक होगी। उन्होंने बैठक को जारी रखने के लिए सदन की अनुमति ले ली है।

(व्यवधान)

डा० एस०पी० यादव (संभल) : महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : कोरम घंटी को बजाया जाए। ....

अब कोरम है। माननीय सदस्या, श्रीमती गीता मुखर्जी, अपना भाषण जारी रखे।

श्रीमती गीता मुखर्जी : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा बोल रही हूं। मैं नहीं जानती। जो भी हो, मैं अपने हृदय से बोल रही हूं। **(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी (दक्षिण कलकत्ता) : महोदया, आप अपना भाषण जारी रखें।

श्रीमती गीता मुखर्जी : उनकी आपत्ति यह थी कि उस वक्त कोरम नहीं था। **(व्यवधान)**

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने भोजनावकाश के दौरान कोरम की बात उठाई।

श्रीमती गीता मुखर्जी : पीठासीन अधिकारी अपने पद पर आसीन है। यह मत भूलिए।

महोदय, मैंने पटसन पर बोलना शुरू किया था। मैं इस विषय पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करना चाहती थी। मैंने कुछ विशेष बातें कही थी। चूंकि उस वक्त सदन में बहुत ही कम सदस्य उपस्थित थे अत: मैं पटसन के बारे एक या दो टिप्पणियों को दोहराना चाहूंगी। मैंने कहा है कि राष्ट्रीकृत पटसन कारखानों का राष्ट्रीयकरण समाप्त किया जा रहा है। एक ओर तो आपने कहा है कि बजट में इसके लिए 4 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। दूसरी ओर इन कारखानों को बेचने का विज्ञापन दिया गया है। अत: कर्मचारियों के साथ दो प्रकार की युक्तियों से कार्य किया जा रहा है। आप ये कारखानें उन्हीं मालिकों को बेचना चाहते हैं जिन्होंने वास्तविक रूप से समस्त पटसन उद्योग को नष्ट कर दिया है और आज स्थिति यह हो गई है कि अगर भारत सरकार इसमें गंभीरतापूर्वक हस्तक्षेप नहीं करती हैं तो करोड़ो लोग किसान और पटसन कर्मकार दोनों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के लिए संकट उत्पन्न हो जाएगा। मैं यह समझती हूं कि आप पश्चिम बंगाल को शांतिपूर्वक रहने देना नहीं चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आपको कुछ कदम उठाने होंगे। मैं आपको यह सीधे तौर पर कह रही हूं। अगर आप कदम नहीं उठाते हैं, तों पटसन उद्योग में एक भंयकर स्थिति उत्पन्न हो जायेगी और कर्मचारी यह सब चुपचाप नहीं सहेंगे और उन्होंने यह प्रदर्शित भी कर दिया है। उसी संदर्भ में मैं यह कह रही थी। जरूरी कदमों को उठाने में क्या परेशानी है? क्या धन प्राप्त करने में कोई कठिनाई हो रही है?

मैंने पहले ही कहा है कि विदेशी ऋणों पर ब्याज चुकाने और रक्षा व्यय को पूरा करने के बाद, बजट खर्च में तीसरी प्राथमिकता अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना है। इसके बारे में मैंने विशेषत: आपत्ति भी व्यक्त की है। मैं यह मानती हूं कि हमारे जैसे गरीब देश के लिए यह एक फालतू खर्च है।

जब नई सरकार बनी, तो पहले बजट पर चर्चा के दौरान, मैंने श्री मनमोहन सिंह से कहा था कि वे मोटर साइकिल पर बैठकर आएं। मैंने उनसे यह भी कहा था कि इस युग में भी मैं एक साइकिल पर पीछे बैठकर संसद आ सकती हूं और उनसे यह भी पूछा था कि वह मोटर साइकिल पर पीछे बैठकर संसद क्यों नहीं आ सकते। आप 13 गाड़ियों के साथ क्यों आते हैं। **(व्यवधान)**

श्री चित्त बसु (बारसाट) : क्या उनके पास केवल 13 मोटरगाड़ियां है?

श्रीमती गीता मुखर्जी : प्रत्येक महानुभाव 13 कारों के साथ आता है। जब देश में हजारों कर्मकार आत्म-हत्या कर रहे हों तब भी आप सार्वजनिक धन की इस प्रकार फिजूलखर्ची कर रहे हैं। आप ऐसा नही कर सकते। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।

प्रत्येक सदस्य ने इस बात का उल्लेख किया है कि आप किस प्रकार से अपनी बजट नीतियों के द्वारा राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों और अन्य मिलों के बुनकरों, जूट कर्मकारों, जूट उत्पादकों और अनेक अन्य उद्योगों को नष्ट कर रहे हैं। मैं उसका पुन: उल्लेख नहीं कर रही हूं।

जैसा कि आप जानते हैं सोवियत संघ के दुर्भाग्यपूर्ण पतन के पश्चात् उजबेकिस्तान में श्री करीमोव, जो आज तक भी एक साम्यवादी है, राष्ट्रपति हैं। वे यहां आये थे। हमें उनसे मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन आमंत्रित किया गया था। मैंने श्री करीमोव से पूछा था कि आप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण ले रहे हैं, आप राजसहायता के संबंध में क्या करने जा रहे हैं। क्या वे खाद्य संबंधी राज सहायता, महिलाओं के लिए राजसहायता, स्वास्थ्य के लिए राजसहायता, शिक्षा के लिए राजसहायता आदि जैसी सभी राजसहायताओं को समाप्त कर देंगे? क्या वे इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की शर्तों के कारण समाप्त कर रहे हैं? श्री करीमोव ने मुझे बताया कि एक बार दी गई किसी चीज का वापस नहीं लिया जा सकता। इससे विद्रोह हो जायेगा। अत: वे अपने व्यय को कम कर रहे हैं और बजट द्वारा स्वयं के अनुत्पादक व्यय को कम करके अन्तर्राष्ट्रीय

मुद्रा कोष की शर्तों को पूरा करेंगे। क्या हम ऐसा ही नहीं कर सकते? हमारे यहां करोड़ो ऐसे व्यक्ति है जो अत्यधिक बुरी दशा में रहते हैं। क्या हम उनके लिए अपना व्यय कम नहीं कर सकते? क्या हमारी सरकार अपने व्यय के मामले में कटौती नहीं कर सकती? वे कटौती कर सकते हैं। हमारे द्वारा दिये गये ठोस सुझावों के बावजूद भी उन्होंने कटौती नहीं की।

अंत में, मैं माननीय वित्त मंत्री को एक बात स्मरण कराना चाहती हूं क्योंकि तीन वर्ष बीत चुके हैं। आपने विदेशी विनिमय दबाव के कारण अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने का निर्णय लिया था। मैंने उस समय यह सुझाव दिया था कि विमानन ईंधन अत्यधिक महंगे आयातों में से एक है। अत: कुछ समय के लिए आपने उन कुछ विमानों की उड़ानों को रद्द कर दिया जिनकी आवश्यकता नहीं है। यहां तीव्रगामी रेलगाड़ियां है और इनमें और डिब्बे जोड़े जा सकते हैं। अब, कृपया यह देखें कि इसका क्या हुआ? आपने बेड़े में विमान ही शामिल नहीं किये अपितु उनके लिए ईंधन के आयात में भी मूल्यवान विदेशी मुद्रा व्यय कर रहे हैं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसके मूल्य में गिरावट होने के बावजूद भी अब तेल की वर्तमान मात्रा से स्थिति में सुधार हुआ है। कल जब मैं इंडियन एयरलाइंस से यात्रा कर रही थी तो मैंने देखा कि कलकत्ता-दिल्ली मार्ग पर भी विमान आधा खाली था। आपको हमारी विदेशी मुद्रा व्यय करने की अनुमति किसने दी?

मेरे अनेक साथियों ने पहले ही कहा है कि आपने धनी वर्ग और वह भी विदेशी धनी वर्ग को छोड़ दिया है। बजट में ऐसा करना एक घृणित कार्य है। मैं उन सभी चीजों का सहारा लेती हूं। परंतु अनुत्पादक खर्च में कटौती करने के 101 रास्ते हैं। चूंकि मुझे अब अपनी बात समाप्त करनी है इसलिए मैं अब उन्हें दोहराऊंगी नहीं। परंतु जनता के अनुकूल बजट बनाने का एक ऐसा रास्ता था और वह अब भी है जिसमें हमारी आर्थिक प्रभुसत्ता का ध्यान रखा जाये। दुर्भाग्य से कांग्रेस सरकार ने ऐसा न करने का निर्णय लिया है और वे हमें इस अत्यधिक अपरिहार्य स्थिति की ओर ला रहे हैं।

अत:, महोदय, हमारे अनके साथियों द्वारा बताये गए अनेक कारणों और हमारे राज्य में जूट श्रमिकों और कच्चा जूट उत्पादकों के साथ सरकार के रवैये की वजह से मैं इस बजट का विरोध करती हूं क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जिसमें हमारा राज्य काफी रूचि रखता है। मैं आशा करती हूं कि माननीय मंत्री इन चीजों का ध्यान रखेंगे। मैं जानना चाहती हूं कि वे राष्ट्रीयकृत जूट उद्योगों के बारे में क्या करने जा रहे हैं और जूट उत्पादकों के बारे में वे क्या करने जा रहे है। क्या वे राष्ट्रीयकृत जूट उद्योगों को जीवित रखने के लिए उनकी सहायता हेतु पर्याप्त धनराशि जारी करेंगे और क्या वे जूट उत्पादकों से लाभकारी मूल्यों पर जूट खरीदने के लिए भारतीय जूट निगम की सहायता हेतु भी पर्याप्त धनराशि जारी करेंगे?

इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का विरोध करती हूं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय हम मानते है कि बजट पर बोलते समय माननीय सदस्यों को अनेक बातें उठानी होती है। परंतु क्योंकि अधिकांश सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते है, मैं समझता हूं कि इसके लिए उन्हें सीमित समय दिया जाए ताकि जो सदस्य यहां पर उपस्थित हैं, उन्हें इस वाद-विवाद में अपनी बात कहने का अवसर मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप कितने समय का प्रस्ताव करते हैं? क्या हम 10 और 12 मिनट के लगभग समय रख सकते हैं? क्या यह ठीक है?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

श्री मुकुल वासनिक : एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने इस विषय पर कल से चर्चा आरंभ

की है। लगभग 16-17 सदस्य पहले ही बोल चुके हैं। परंतु कांग्रेस की ओर से केवल तीन या चार सदस्य ही बोले है। अतः यदि इसमें संतुलन रहे तो इससे हमें सहायता मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, क्या मैं निवेदन कर सकता हूं कि मध्यान्ह पूर्व जब माननीय अध्यक्ष महोदय पीठासीन थे, तो एक समझौते के अनुसार कांग्रेस सदस्यों का समय दूसरे सदस्यों को दे दिया गया था जब ऐसा ही समझौता है ....(व्यवधान)। कृपया मेरी बात सुनिए। मैं केवल यह कह रहा हूं कि जब ऐसा समझौता है तो सदस्यों को गणपूर्ति का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए और सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। आपका धन्यवाद। अतः कुल मिलाकर, प्रत्येक इस बात के बीच सहमत है कि समय 10 और 12 मिनट के बीच रखा जाये क्योंकि बार-बार घंटी बजने से सभंवतः आपको बाधा पहुंचाती है और शायद आपको अच्छी न लगती हो।

अब, श्री चिरंजी लाल शर्मा।

[हिन्दी]

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : मै इस बजट का स्वागत करता हूं। "वक्त पोता किस्सा तुलानी", परशियन में कहते हैं "वक्त थोड़ा किस्सा लम्बा", और आपने टाइम पर पाबंदी लगा दी। मैं आपके हुक्म का ऐतराम करूंगा, मुझे कहना बहुत कुछ था लेकिन सिर्फ टाइम की पाबंदी की वजह से मैं केवल दो आइटम पर ही बोलूंगा।

महोदय, कल विरोधी दल के माननीय सदस्य, जो इस समय यहां पर सदन में मौजूद नहीं है। श्री शरद यादव जी की बड़ी लच्छेदार रसीली और नशीली तकरीर थी। उन्होंने महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू के बड़े हवाले दिए और 50 साल पहले के वक्त का आजकल के हालात से मुकाबला किया। महोदय, जिसने गरीबी नहीं देखी उसे अमीरी की कद्र नहीं, जिसे कांटा नहीं लगा उसे फूल की कद्र नहीं। जिसने गुलामी नहीं देखी उसे आजादी की कद्र नहीं, "न हो रात तो दिन की पहचान क्या, उठाए मजा दिन का इंसान क्या।" अगर हिन्दुस्तान की जनता 1977 से 1979 तक और 1990 से 1991 तक सवा दो-ढाई साल पहले और ये 18 महीने, पौने तीन साल जनता पार्टी और जनता दल की सरकार न देखती तो उनको कांग्रेस के 40 साल राज की कद्र न होती। शरद जी मुकाबला कर रहे थे, वह भूल गए कि उनकी सरकार के दौरान देश की क्रेडिबिलटी, देश की शान और सम्मान खत्म हो चुकी था।

बाहर से सौदा मिलना बंद हो गया था, फॉरेन-एक्सचेंज का दीवाला निकल चुका था।...... (व्यवधान)..... साढे 46 टन सोना हवाई जहाज से लाद कर लंदन के बैंक में गिरवी रखवा दिया गया था। .... (व्यवधान)........ चन्द्रशेखर जी आपकी पार्टी के थे, आपकी पार्टी का विभाजन हुआ था।...... (व्यवधान).....

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक कि माननीय अध्यक्ष महोदय अनुमति न दें, कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

श्री चिरंजी लाल शर्मा : चन्द्रशेखर, वी पी सिंह, देवीलाल, ये सब आपकी पार्टी के थे, लेकिन इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। आपकी पार्टी टूटी, क्या इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है? क्या इसका इलजाम आप कांग्रेस पर देगें? आप अपने गिरेबां में झांक कर देखिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। मेरा कहना यह है कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री वी पी सिंह अभी सदन में उपस्थित नहीं है और वे अपने पर लगाए गए आरोपों का उत्तर नहीं दे सकते हैं, इसलिए उनका नाम यहां पर न लिया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यहां किसी के विरुद्ध कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है। यह एक नीति संबंधी मामला है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चिरंजी लाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने किसी पूर्व प्रधानमंत्री की शान के खिलाफ कोई बात नहीं की है।.......... **(व्यवधान)**.........

[अनुवाद]

मैं आपकी सरकार पर दोष लगा रहा हूं और आप इसे स्वीकार कीजिए।

[हिन्दी]

मैं यह कह रहा था कि जनता दल सरकार के वक्त देश की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी थी और साढ़े 46 टन सोना लंदन के एक बैंक में प्लैज करवा दिया गया था। उस सोने को किसने छुडवाया?............ **(व्यवधान)**............

उपाध्यक्ष महोदय, एक शेर याद आ रहा है -

हकीकत आशनां हूं, वाकफे इसरारे हस्ती हूं
समझता हूं मगर दुनिया को समझाना नहीं आता

मैं अपने मोअजिज दोस्तों से जो उन कुर्सियों पर सरफराज़ है, जलवा फरोज़ है, उनसे कहना चाहता हूं कि वे मेरी बात को शांति से सुने, उनको भी जवाब देने का और खंडन करने का पूरा अधिकार है। लोकतंत्रीय प्रजातंत्र में इस सदन में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। यदि कोई वक्ता अपनी बात कह रहा है, उसको अपनी बात कहने का अधिकार है, यह अधिकार आप उससे छीन नहीं सकते हैं .... **(व्यवधान)** ....जो आरोप मेरी पार्टी और मेरी सरकार के खिलाफ लगाए गए हैं, क्या मैं उनको चुपचाप सुनता रहूं, उनका जवाब न दूं? मेरे अधिकार से आप मुझको वंचित नहीं कर सकते।..... **(व्यवधान)**....... उपाध्यक्ष महोदय, यह 5 मिनट का समय मेरे समय में से नहीं कटेगा।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आप सदन का संचालन नहीं कर सकते हैं, आपको यह रूलिंग देने का अधिकार नहीं है कि यह 5 मिनट का समय आपके समय में से नहीं कटेगा।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : मैं कोई रूलिंग नहीं दे रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, फूड ग्रेन प्रोडक्शन में रिकार्ड कायम हुआ है। लेवल आफ क्योर गजब का है। अनाज भंडार में कोई कमी नहीं है, रेट आफ इन्फ्लेशन का कम किया गया है, फॉरेन एक्सचेंज में इंप्रूवमेंट हुई है, फारेन इनवेस्टमेट इनफ्लों में वृद्धि हो रही है। खुशकिस्मती से वित्त मंत्री जी भी सदन में आ गए है।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन जी अभी आए है, सच्चाई को वह हमेशा मानने को तैयार रहते हैं।

[हिन्दी]

मैं अपने क्षेत्र के लोगों के बारे में न कहूं तो मैं अपने फर्ज में कोताही करूंगा। मैंने शुरू में कहा कि बेसिक एप्रोच में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन कुछ बातों की ओर वित्त मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहूंगा। काटन यार्न की कमी है लेकिन सरकार काटन का एक्सपोर्ट करना चाहती थी जबकि धागे की कीमतें बढ़ गई । धागे की कीमतें ठीक तौर पर कायम रखने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को काटन और धागे की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगानी चाहिए। हैंडलूम वीवर्स को मिल और पावरलूम के कपड़े का मुकाबला करना पड़ता है। पानीपत सारे देश की हैंडलूम फैब्रीक्स का चालीस परसेंट एक्सपोर्ट करता है यानि 1400 करोड़ रूपये की एक्सपोर्ट होती है और बीस साल के पीरियड में अकेला पानीपत ही आगे पहुंच चुका है। वहां दो लाख वीवर्स काम करते हैं। इस बजट में वहां की इस हैंडलूम इंडस्ट्री को एक तरह से स्टैंड-स्टील पर खड़ा कर दिया है। वूलन यार्न और क्रास्ड रील यांक यार्न पर एक्साईज डयूटी लगा दी गई है जबकि वहां पर दो लाख श्रमिक काम करते है तो यह बेकारी की तरफ कदम बढ़ाने वाली चीज है जैसे- कुछ करेला चढ़ा और कुछ नीम चढा। सूत पर और इसकी डाईंग पर छह फीसदी एक्साईज डयूटी लगाना सरासर ज्यादती और बेइन्साफी है। हैन्क यार्न ज्यादातर हैंडलूम में इस्तेमाल होता है तो इसकी स्पीनिंग और डाईंग पर डयूटी लगाना मुनासिब नहीं है। वूलन यार्न पर 15 परसेंट एक्सार्ज डयूटी लगा दी है। और कारपेट इंडस्ट्री को प्लेटर पर रखकर चाईना, पाकिस्तान और नेपाल के हवाले कर रहे हैं। काटन यार्न पर पहले एक्साईज डयूटी नहीं थी लेकिन अब चूंकि इन मुल्कों से मुकाबला करना है। कारपेट इंडस्ट्री को आप देखिए। जैसे 70 परसेंट ब्लेन्केट हमारी डिफेंस फोर्स को जाते है तो आप अंदाजा लगाईए कि इस कदम से उनको कितना जबर्दस्त नुकसान होगा। स्माल स्केल और टाईनी इंडस्ट्री को भी एक्साईज डयूटी के नेट में ले आए हैं। जवाहर रोजगार योजना के तहत बजट में प्रोविजन किया गया है और दूसरी तरफ मैसिव अनएम्पलायमेंट क्रिएट करने जा रहे हैं एक्साईज डयूटी लगाकर और लार्ज सैक्टर इंडस्ट्री में उनी कपड़े पर, गारमेंट्स पर और होजियरी आदि पर तो उस पर चालीस परसेंट एक्साईज डयूटी घटाकर उस सैक्टर को बेनीफिट पहुंचाने के लिए 25 परसेंट कम कर दी गई।

स्माल स्केल और मीडियम स्केल सेक्टर में कार्पेट के लिए, ब्लैकेट के लिए धागे पर एक्साइज डयूटी लगा दी। मैं वित्त मंत्री से बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि वह इस पर विचार करे। फैक्ट्रीज बंद पड़ी है। अकेले पानीपत में हजारो मजदूर बेकार बैठे हैं, उनका यही एकमात्र गुजारा है। चार दिन हो गये है, 25 हजार लोगों का जूलूस ढाई किलोमीटर लम्बा निकला था। यह जो एक्साइज डयूटी लगाई गई है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। वे लोग वित्त राज्य मंत्री चन्द्रशेखर मूर्तिजी से और वस्त्र मंत्री वेंकटस्वामीजी से भी मिले थे।

दूसरी बात की ओर मैं मंत्रीजी की तवज्जोह दिलाना चाहता हूं वह है पानी। जिसका जिक्र शरद जी ने भी किया था। वह फसल की जान है। जिस जमीन पर तीन मन फसल एक बीघे मे होती थी, आज उस पर दस मन होती है। पानी बढ़ गया, बीज बदल गया, खाद बदल गई। मेहनत किसान करता है, लेकिन साधन सरकार ने जुटाये। इस सिलसिले में हरियाणा के साथ जो ज्यादती हो रही है, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। 1955 में पंजाब और राजस्थान के बीच हुए समझौते के मुताबिक उस वक्त जो अवेल सरप्लस वाटर था उसके हिसाब से 1921 से 1945 की सीरिज के आधार पर पानी की तकसीम हुई थी। जम्मू कश्मीर 0.65 एम.ए.एफ., अर्स्टवाइल पंजाब, हरियाणा बनने के पहले 54.20 एम.ए.एफ, राजस्थान 8 एम.ए.एफ. 1.11.1966 को पंजाब से हरियाणा बना, हरियाणा ने 7.2 एम.ए.एफ. में से 4.8 एम.ए.एफ क्लेम किया। जबकि पंजाब ने 7.2 एम.ए.एफ. पूरे पर अपना हक जताया। क्योंकि पंजाब और हरियाणा का आपसी फैसला नहीं हो सका, अंडर सेक्शन 78 के तहत 1979 में हरियाणा सरकार ने भारत सरकार का दरवाजा खटखटाया

कि फैसला करो। भारत सरकार ने 24.3.76 के नोटिफिकेशन के आधार पर पंजाब और हरियाणा को 3.5 एम.ए.एफ. बराबर-बराबर कर दिया। बाकी .2 एम.ए.एफ. दिल्ली को दे दिया।

1979 में हरियाणा ने सूट नं. 1 सुप्रीम कोर्ट में दावा दायर किया कि केन्द्र सरकार के फैसले को अमली जामा पहनाया जाये। साथ-साथ पंजाब ने सूट नं. 2 सुप्रीम कोर्ट में दावा दायर कर दिया जिसमें भारत सरकार के फैसले को चैलेज किया। 31 सितम्बर, 1981 को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य मंत्री और यहां के पानी के वजीर के बीच में फैसला हुआ। जिसमें 1921 से 1960 के दरमियान रावी-व्यास पानी सीरिज के आधार पर नया समझौता हुआ। जिससे पंजाब को 4.22 एम.ए.एफ., हरियाणा को 3.5 एम.ए. एफ. राजस्थान को 8.60 एम.ए.एफ जम्मू कश्मीर को 0.65 एम.ए.एफ, और दिल्ली को 0.2 एम.ए.एफ टोटल 17.17 एम.ए.एफ. का फैसला हुआ। इस समझौते से यह भी तय हुआ कि पंजाब सतलुज व्यास लिंक नहर को दो साल में पूरा करेगा। हरियाणा और पंजाब ने अपने-अपने दावे जो सुप्रीम कोर्ट में दायर किये थे, वापस ले लिये। 12 फरवरी 1982 को सुप्रीम कोर्ट ने विदड्राल की इजाजत दे दी। इसके बाद पंजाब में पोलिटिकल डवलमेंट शुरू हुई। जिसकी वजह से प्रधान मंत्री राजीव गांधी और लौंगोवाल के बीच 24 जुलाई, 1985 को समझौता हुआ। पंजाब ने 5 नवम्बर 1985 को एक प्रस्ताव पास करके 1981 के एग्रीमेंट को रिडेडेंट करार दे दिया। इस सैटलमेंट की रूह से गवर्नमेंट आफ इंडिया ने रावी-ब्यास वाटर ट्रिब्यूनल बनाया जिसमें तीन मैम्बरान थे।

[अनुवाद]

माननीय न्यायमूर्ति बालकृष्ण इराडी, उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति ए.एम. अहमदी, उच्च न्यायालय के वर्तमान, न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति पी.सी. बालकृष्ण मेनन, वर्तमान न्यायाधीश। न्यायाधिकरण में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीश थे।

[हिन्दी]

इसने 30.1.87 को अपनी रिपोर्ट दी जिसके मुताबिक पंजाब को 5 एम.ए.एफ, हरियाणा को 3.83 राजस्थान को 8.60 जम्मू कश्मीर का 0.65 और दिल्ली को 0.2 एम.ए.एफ. पानी तकसीम किया गया। इसके बाद पंजाब और हरियाणा ने Interstate Disputes Act, 1956 के तहत गाईडेंस के लिये एप्लाई कर दिया। उसके बाद 1.4.79 को ट्रिब्यूनल की आखिरी हियरिंग हुई तो भारत सरकार की रिक्वेस्ट पर इसको एडजर्न कर दिया। इसके बाद गाड़ी नहीं चली।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि

[अनुवाद]

"मामलों को निम्नलिखित आधारों पर उच्चतम न्यायालय को नहीं सौंपा जा सकता :

(एक) भारत के संविधान के अनुच्छेद 262 के अधीन शक्तियों का निर्वहन करते हुए संसद ने अंतर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 पारित किया है।

(दो) अंतर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार एक न्यायाधिकरण का गठन कर सकती है। जिसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होंगे।

(तीन) अंतर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत किसी ऐसे जल विवाद, जो इस अधिनियम के अधीन न्यायाधिकरण को सौंपा जा सकता है, के संबंध में उच्चतम न्यायालय और अन्य न्यायालय का क्षेत्राधिकार सीमित है।

अंतर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम की धारा 11 यह उल्लेख है :

"किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी अन्य बात के होते हुए, न तो उच्चतम न्यायालय, न ही कोई अन्य न्यायालय ऐसे किसी जल विवाद के संबंध में, जो इस अधिनियम के अधीन किसी न्यायाधिकरण को सौंपा जा सके, क्षेत्राधिकार रख सकेगा अथवा उसका प्रयोग कर सकेगा।''

[हिन्दी]

कितना अर्सा हो गया है हरियाणा को पंजाब से अलग हुए। पंजाब हमारा भाई है, एक ही पेड़ की दो डाल है। अब हमने तो एस.वाई.एल. का 85% भाग पूरा कर दिया है और जो 15 परसेंट रह गया है उसकी वजह से हम अत्यधिक कष्ट उठा रहे है। हमारे अधिकारों को पंजाब सरकार के द्वारा अनेक कारणों से जिनकी हमें जानकारी नहीं है कुचला जा रहा है।

[हिन्दी]

पानी हमें मिलता नहीं है, यह हमारा अधिकार है। मैं तो आपके माध्यम से फाइनेंस मिनिस्टर से अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे जाज्बात से खिलवाड़ न करे। हमारे जज्बात का एहतराम करते हुए हमारा हक दिलवाइये। ट्रिब्यूनल मुकर्रर किया गया लेकिन उसका फैसला भी नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट में हम जा नहीं सकते हैं और इस तरह से सारा मामला ठप्प हो गया है। नहरें बनी हुई है जो टूट रही है। आप हमारी मदद करे।

उपाध्यक्ष महोदय, वक्त होता तो किस्सा सुनाते, दिमागी समन्दर में ख्यालात जज्बात और तासिरात है और हर सब्जेक्ट के लिए तैयार था लेकिन आपकी घंटी बार-बार मुझे मजबूर कर रही है कि आपके हुक्म का एहतराम करूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और फाइनेंस मिनिस्टर से अर्ज करूंगा कि काटेज, स्माल इंडस्ट्रीज, हैंड यार्न, वूलन, डाई पर एक्साईज डयूटी का विदडा करके गरीब आदमी को जो टुकड़ा मिल रहा है, उसको न छीने। धन्यवाद।

2.00 म०प०

श्री राजेश कुमार (गया) : उपाध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। सदन में वित्त मंत्री जी ने वर्ष 1994-95 से संबंधित जो बजट पेश किया है, वह हमें एक मकड़ी के जाल की भांति नजर आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप देश के किसी भी कोने में चले जाइये, गरीब और ज्यादा गरीब होता चला जा रहा है। स्थिति यहां तक पहुंच गयी है और हम सबके लिये यह बड़ी शर्मनाक बात है कि कई आदिवासी इलाकों में लोग आज भूख के लिए अपने बच्चों को बेचने के लिए मजबूर हो गये है। हरिजन महिलाएं सड़कों पर अपने बच्चे पैदा करने पर एवं बेचने को मजबूर है। हमारे वित्त मंत्री जी कहते है कि हमने बहुत अच्छा बजट पेश किया है, यदि अच्छा बजट पेश किया गया होता तो लोग क्यों भूखों मरते। सड़को पर लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं यहां आंकड़ों में जाना नहीं चाहता परंतु जो बजट यहां पेश किया गया है, यदि वह अच्छा होता तो उससे लोगों को अच्छा भोजन मिलता, उनका रहन-सहन अच्छा होता, अच्छा कपड़ा मिलता लेकिन आज आप किसी भी इलाके में जाकर देख लीजिये सभी जगह लोग परेशान है। शायद हमारे वित्त मंत्री जी थोक व्यापारियों की बाते करते होंगे, बड़ी मिल वालों की बाते करते होंगे, यदि वे गांवों को देखे तो वहां गरीब व्यक्ति के लिये कपड़ा महंगा हो गया, चीनी, चावल, गेंहू, तेल, रसोई गैस सारी की सारी चीजें महंगी हो गयी है, फिर हम कैसे इस बजट को अच्छा कह सकते हैं।

बजट को देखने से लगता है कि यह वित्त मंत्री जी का स्वयं का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि आई.एम.एफ और वर्ल्ड बैंक के दबाव में बना बजट है। आई.एम.एफ और वर्ल्ड बैंक दोनों हमारे वित्त मंत्री जी पर नजरे लगाये बैठे हैं। इसमें विदेशी निवेशकों का ज्यादा ध्यान रखा गया है, बड़े लोगों और निवेशकों कि फायदे के लिये इसमें अनेकों प्रावधान किये गये है, इसीलिये मैंने कहा कि वित्त मंत्री जी ने गरीबों के लिये अच्छा बजट पेश नहीं किया है। हमारे नेता शरद जी ठीक बोल रहे थे कि इसके कारण देश में भुखमरी फैलेगी, गरीब लोग भूखों मरेंगे और सरकार ने गरीब लोगों का गला घोटने वाला बजट पेश किया है। आपने देखा होगा कि देहातों में जब बिल्ली को मारते है तो पहले वह छप्पर पर चढ जाती है। यदि उसके पीछे फिर डंडा लेकर जाते है तो छप्पर से वह आदमी की गर्दन पर वार करने की कोशिश करती है। हमारा देश 90 करोड़ आदमियों का है और वे सब इस बजट के कारण भुखमरी के शिकार होंगे। यह सरकार उनसे बच नहीं पायेगी, ऐसा मेरा मानना है। जब गरीब आह भरता है तो वह आह आप पर पड़ेगी। तब आपको पता चलेगा कि गरीब की आह क्या होती है।

हमारे नेता शरद जी ने ठीक कहा था कि यह सरकार गांधी जी की नीतियों से बिलकुल हट गयी है। महात्मा गांधी ने हमें स्वदेशी अपनाने की सलाह दी थी, स्वदेशी कुटीर उद्योगों को बढ़ाने का आव्हान किया था लेकिन यह सरकार ठीक गांधी की नीतियों के विपरीत काम कर रही है और विदेशी चीजों को देश में बढ़ावा देने की और जा रही है। हमारी जितनी खामियां है, मैं यहां कुछ आंकड़े देना चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी ने जब 1991-92 का बजट यहां प्रस्तुत किया था, तो उसे कठोर बजट की संज्ञा दी गयी थी, 1992-93 का जो बजट प्रस्तुत किया गया था, उसे संवेदनशील बजट की संज्ञा दी गयी थी, वर्ष 1993-94 के बजट को उदारवादी बजट गया गया था और वर्तमान 1994-95 के बजट को हम क्या कहे। यदि हम इसे गरीबों के मामले में गला घोटू बजट कहते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है।

आप देखें कि चौथे बजट में हमारे वित्त मंत्री जी ने 1,45,699 करोड़ रूपये की प्राप्ति और 1,51,699 करोड़ रूपये का कुल व्यय दिखाया है, जिसमें दो नई बातें आपको देखने को मिलेगी। पहली बात यह है कि 1997-98 तक केन्द्रीय सरकार आर बी आई से कर्ज लेना बंद कर देगी और जहां तक 1994-95 के बजट के 6 हजार करोड़ रूपये के घाटे का सवाल है, मैं समझता हूं कि हमसे तथ्यों को छिपाया गया है, वास्तविक घाटा इससे दो गुना या तीन गुना है, जिसे वित्त मंत्री जी ने हमसे छिपाया है। मैं वित्त मंत्री जी से दो सवाल करना चाहता हूं। पिछले बजट में नई आर्थिक नीति के ढेर सारे फायदे गिनाये गये थे और आपने शेयर पढ़कर हम लोगों को बताया था कि आने वाले दिनों में हिन्दुस्तान की तकदीर बदल जायेगी, हिन्दुस्तान का नक्शा ही बदल जायेगा। हमारे बम्बई के एक माननीय सदस्य दत्ता मेघे यहां बैठे हैं और वे मेरी बात तो मानेंगे कि यदि आप बिहार जैसे गरीब इलाकों में जाये तो वहां आपको पानी भी नहीं मिलेगा।

(व्यवधान)

नागपुर और बम्बई में ज्यादा फर्क नहीं है। मैं यहां मुद्रास्फीति के बारे में पहला सवाल आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से करना चाहता हूं और अपेक्षा करता हूं कि जब वे बहस का उत्तर देंगे तो इस पर भी चर्चा करेंगे।

मुद्रास्फीति के संबंध में, मैं बताना चाहती हूं कि यह वर्ष 1991 में 17% था और आपने अपने भाषण में कहा था कि इस बहुत कम कर दिया जाएगा। 1993 में 6.9% पर आ गई फिर भी 8.5% हो गई, लेकिन इस वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण जो हमे उपलब्ध करवाया गया है उसमें यह दर 8.8% बताई गई है। जब आपने अपनी नीतियों के कारण मुद्रास्फीति की दर कम होने की बात कही थी तो यह बढ़ती क्यों जा रही है। हमारे इस प्रश्न का उत्तर आप जब बजट पर हुई बहस का जबाव दे, तो अवश्य दे।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल राजकोषीय घाटे के संबंध में है। आपने जो वायदा किया था कि हम धीरे-धीरे इसको कम करते चले जायेंगे, वह तो हर साल बढ़ता ही चला जा रहा है। हालांकि मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन मैथमैटिकस को विद्यार्थी रहा हूं सो जोड़ और घटावं के आधार पर मैं बता रहा हूं कि 1992 में राजकोषीय घाटा 6% था और 1993 में 5.2% हो गया और वायदा किया गया कि आगे 4.7% हो जाएगा यदि सब कुछ ठीक-ठाक रहा और मार्च 1994 तक 3% रह जायेगा, लेकिन यह तो उल्टा हो गया 5.2 और फिर बढ़ा मार्च 1992 में 6.6% के आंकड़े को भी पार कर गया 7.3% पर जा पहुंचा जहां से हम लोगों ने शुरूआत की थी 1991 में और फिर जाकर हम लोग वहीं पहुंच गए है। क्या यही आपका, गरीबों को बचाने का बजट है? मैं तो आप पर सीधा आरोप लगाना चाहती हूं कि आपका बजट तो बड़े-बड़े पूंजीपतियों, टाटा और बिड़ला जैसे लोगों के लिए है क्योंकि आपने अपने बजट में इन्हीं लोगों को राहत दी है, गरीबों को कोई राहत नहीं दी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहता हूं कि हमारी कस्टम डयूटी से जो आय 58 हजार करोड़ और राजस्व प्राप्तियों 32 हजार करोड़ रूपये की बताई गई है, यह गलत है। इन आंकड़ों से दबे पिसे और कुचले लोगों का फायदा नहीं होने वाला है। जो लोग गांवों में रहते हैं, जो मजदूर सड़क बनाने का काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, ईंट जोड़ने का काम करते हैं उनके लिए आपके मन में कोई चिंता नहीं है कि ये लोग कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। आपने तो अपने प्रधान मंत्री की नीतियों की भी अवहेलना की है। प्रधान मंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से घोषणा करते हुए कहा था और देश को आश्वासन दिया था कि 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जायेगा, लेकिन बेरोजगारों को कोई राहत नहीं दी जा रही है। इस कार्य के लिए मात्र 145 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। हिसाब लगाकर देखेंगे तो यदि इसको प्रति व्यक्ति देखे तो एक आदमी को रोजगार देने पर 1450 रूपये प्रति वर्ष, प्रति बेरोजगार के लिए बैठते हैं। इससे आप स्वयं अनुमान लगा लीजिए कि यह छलावा नहीं तो और क्या है। वित्त मंत्री जी यह देश किसी के लिए रूकता नही है। जब हम उधर होंगे और आप इधर होंगे, तो भी इससे देश पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप गरीब लोगों का मारने का काम करेंगे और 80% देश के किसानों को मारने का काम करेंगे, तो यह देश ऐसा देश है और यहां के लोग ऐसे हैं कि वे आपको कभी माफ नहीं करेंगे।

जब गरीब की आह लगेगी तो वह आपको भी नहीं बख्शेगी। सफल वित्त मंत्री वही हो सकता है जो गरीबों के लिए सोचे, उनकी रोजी-रोटी, रहन-सहन आदि के बारे में सोचे। आपने उसका उल्टा किया है। आपने बजट पर लोन की चर्चा की है। लेकिन हम आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहते हैं कि आपके समय में रिवैन्यू डैफीसिट 4.3 प्रतिशत हो गया जबकि पहले 2.7 प्रतिशत था। कैसा आपका खेल है? 27.1 से 43.1 पहुंचाकर भी आप संतुष्ट नहीं है। इसे आगे बढ़ाकर देश को बेच दीजिए। यह बहुत खतरनाक बात है। इसलिए बधाई है, आपने कस्टम डयूटी के बारे में चर्चा की। मेरा एक सुझाव है। यदि आप उस सुझाव को मानेंगे तो उससे सबको फायदा होगा। आप सबसे ज्यादा बड़े उद्योगों के लिए मददगार हुए है। क्या आपने कभी किसानों के बारे में भी सोचा है? यदि इस देश के किसानों के बारे में सोचेंगे तो उससे देश को फायदा होगा, देश के लोगों के फायदा होगा।

पानी निकालने वाले डीजल पम्प के रेट जो आपने बढ़ा दिए हैं, उस बारे में बात करने के लिए हमारे पास आगरा से कुछ लोग आए थे। पानी निकालने वाली मशीन जो खेत में इस्तेमाल होती है, यदि आप उस पर कर लगा देंगे तो उससे किसानों को नुकसान होगा। आपने ट्रैक्टर के दाम भी बढ़ा दिए।

मैं स्माल स्केल सैक्टर के बारे में बताना चाहता हूं। आपने कौरपोरेट सैक्टर में जो रिलीफ दिया है, उससे बड़े उद्योगों को फायदा होगा लेकिन छोटे उद्योग मारे जाएंगे।

चौधरी चरण सिंह, जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, ने पहले बजट में कहा था कि यदि हम छोटे-छोटे उद्योगों में उत्पादन करे तो बहुत अच्छा होगा। हमें लिप्स्टिक और सौन्दर्य उपकरणों में थोड़ा सा टैक्स लगाने में घबराहट नहीं होनी चाहिए। आपने रसोई गैस, स्टोव के दाम बढ़ा दिए। होटल का खाना सस्ता और घर का खाना महंगा।

हम कहां जायेंगे? हम तो घर में खाना खाते हैं। घरेलू उद्योगों पर अपने बहुत कुठाराघात किया है।

मैंने कुछ दिन पहले उद्योग मंत्री जी से सदन में एक सवाल पूछा था कि लैदर के सामान पर आपने कस्टम डयूटी 50% से 70% क्यों कर दी है? आज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने इस पर कस्टम डयूटी क्यों बढ़ा दी है। गांवों में हरिजन जाति के माइनोरिटी लोग जूता बनाने का काम करते थे, उनको इससे बहुत नुकसान हो रहा है। आज विदेशी जूता देशी जूते के मुकाबले में बहुत सस्ता है। इस कारण हर कोई विदेशी जूता लेना चाहता है। कुछ दिनों के बाद 'मेरा जूता है जापानी' का ही नारा लगना शुरू हो जायेगा। ऐसे में गांवों में जो जूता बनाने का काम करते हैं, उनका क्या होगा? आप गांव में बने सामान को महंगा और विदेशी सामान को सस्ता बेच रहे हैं। ऐसा करके कोई अच्छा सलूक नहीं कर रहे हैं।

जब सरकार सत्ता में आई थी तो उसने गरीबी समाप्त करने के बड़े वायदे किये थे, लेकिन गरीबी दूर करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। आपने ताले, कपड़े, कुर्ता, पैजामा, चावल, गेंहू, तेल, चीनी, रसोई घर का सामान हैलमेट, छतरी और मच्छरदानी के दाम बढ़ा कर गरीब लोगों पर चोट पहुंचायी है आप देश को किधर ले जा रहे है? यह गलत होगा। देशवासियों को तबाह मत कीजिए।

आज विदेशी टेलिविजन, वी.सी.आर., रेडियों और घड़ियां यहां सस्ती मिल रही है। इस कारण सब विदेशी सामान ही खरीद रहे हैं। दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में देशी टी.वी, वी.सी.आर., आदि महंगा मिल रहा है। आप उन्हें सस्ता कीजिए।

इस देश में दो तरह की नीति चलती है। कुछ लोग ऐसे है जो गांधी जी नीति पर चलते हैं और दूसरी नीति पर जो लोग चलते हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वे बड़े-बड़े उद्योगों को ही बढ़ावा दे रहे हैं। गांधी जी स्वदेशी चीजों को ज्यादा पसंद करते थे और उनको डैवलप करना चाहते थे। दूसरी नीति पर चलने वाले लोग 8 परसेंट बड़े-बड़े उद्योगों पर और 20 परसेंट छोटे उद्योगों पर ही खर्चा करते हैं। मेरी, मेरी पार्टी के नेताओं की और देश के बडे-बड़े अर्थशस्त्रियों की यह मान्यता है कि जब तक छोटे-छोटे देशी उद्योगों को उन्नत और प्रोत्साहित नहीं करेंगे तब तक बेरोजगारी और गरीबी दूर नहीं होगी।

मैंने जो सुझाव दिये हैं, उन पर आप विचार करें। 1994 में हम पहुंच गये है। मुद्रास्फीति 8.5% हो गई है। इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। विदेशों से कर्ज लेना जारी है। मुद्रास्फीति को खत्म करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है।

उसको खत्म करने के लिए आपने विदेशों का सहारा लिया है। आप IMF और वर्ल्ड बैंक के सहारे को त्यागिये और यहां के बड़े बड़े विद्वान और अर्थशास्त्री लोगों से भी राय कीजिए। अगर आप उनसे राय नहीं लेते हैं तो हमसे भी छोटी-छोटी राय लीजिये कि देश में तरक्की करने का क्या रास्ता हो सकता है। जब तक आप छोटे-छोटे उद्योगों की मदद नहीं करेंगे, उनको बढ़ावा नहीं देंगे, जब तक देशी उद्योगों की हम मदद नहीं करेंगे, तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। साथ ही साथ इस बजट का मैं डटकर विरोध करता हूं। क्योंकि यह बजट बड़े-बड़े लोगों के लिए है। तथा आई.एम.एफ. और वर्ल्ड बैंक के इशारे पर यह बजट बनाया गया है।

[अनुवाद]

श्री उदयसिंह राव गायकवाड (कोल्हापुर) : उपाध्यक्ष महोदय मैं बजट का समर्थन करता हूं। मैं डा० मनमोहन सिंह को उनके द्वारा वर्ष 1994-95 के केन्द्रीय बजट को प्रस्तुत करने में असाधारण प्रतिभा का परिचय देने पर बधाई भी देता हूं। वर्ष 1991 में जब हमारा देश गंभीर आर्थिक कठिनाई से गुजर रहा था तो उन्होंने अंतिम बजट प्रस्तुत किया था लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री पी. वी. नरसिंहराव की निर्भीक नेतृत्व में उन्होंने साहसिक कदम उठाये तथा औद्योगिक लाइसेसिंग, व्यापार नीति, वित्त तथा बैंकिंग नीति में बुनियादी ढांचागत परिवर्तन किये। उन्होंने वास्तव में हमारे देश को गहरी आर्थिक कठिनाइयों से उबारा है। वर्ष 1991 में उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा था 'यदि मुझे तीन बजटों को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है तो मैं देश को प्रगति के पथ पर ले आऊंगा तथा कठिनाइयों से उबार दूंगा' शब्द भिन्न हो सकते है लेकिन उनके कहने का अभिप्राय यही था।

मुझे याद है कि मराठी में एक कहावत है 'बोल तैसा, चाला ताची वेडोर ओवाली' जिसका अर्थ है जो व्यक्ति अपने वचनों का पक्का होता है वह सम्मान के योग्य है। उन्होंने अपने वचनों को निभाया है। अत: वह सम्मान के योग्य है, ये दो नाम हमारे देश के आर्थिक इतिहास में उन व्यक्तियों के रूप में लिखे जायेगें जिन्होंने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बदला है।

इस बजट के बाद की श्री एन. ए. पालकीवाला जैसे वरिष्ठ कर विशेषज्ञों ने, वरिष्ठ उद्योगपतियों, प्रमुख अर्थशास्त्रियों तथा सामाजिक विचारकों ने भी सराहना की है। इस बजट को लीक से हटकर सुदृढ़ बजट माना गया है। इसलिए मैं अपने वित्त मंत्री को इस सराहनीय कार्य के लिए एक बार फिर से बधाई देता हूं।

आप आदमी के लिए इस बजट का एक अन्य महत्वपूर्ण योगदान यह है कि आय-कर के लिए छूट सीमा 35,000 रूपये तक बढ़ा दी गई है। जिस व्यक्ति की वार्षिक आय 50,000 रूपये तक की होगी उसे अब कोई कर नहीं देना पड़ेगा। इसी तरह उत्पाद शुल्क में सभी तरफ की कटौती से मांग बढ़ेगी तथा यह सुनिश्चित है कि उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र में निवेश से फायदा होगा।

इस में वित्त मंत्री का कार्य असाधारण रहा है वित्त मंत्री जी ने उत्पाद तथा सीमा शुल्कों का प्रबल सरलीकरण करने, सरलीकृत कर प्रशासन लागू करने, तथा नई खामियों को कम करने तथा व्यवस्थित कर प्रणाली लागू करने जैसे कई क्रान्तिकारी कदम उठाये हैं। आई. एम. एफ. के ऋण की किश्त समय से पहले भुगतान करने से भुगतान संतुलन तथा विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति से सरकार का विश्वास और मजबूत हुआ है और उनका यह दावा है कि इस बजट के प्रस्तुतीकरण से आम आदमी के बीच विश्वास की भावना उत्पन्न हुई है। आम आदमी के हित के लिए खाद्य पदार्थों तथा उर्वरकों पर एक बार फिर राजसहायता जारी रखी गई है। आय कर को ध्यान में रखते हुए मकान निर्माण पर राहत देने के लिए उधार पूंजी पर ब्याज कटौती का 5000/- रूपये से 10,000/- रूपये तक दुगुना कर दिया गया है। इससे मध्यम वर्ग की जनता को राहत मिलेगी । इसी तरह दवाइयों, सौंदर्य प्रसाधनों तथा कपड़े धोने की मशीनों और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं पर निर्धारित सीमा शुल्क छूट से आम आदमी को प्रत्यक्षत: लाभ हुआ है।

वित्त मंत्री ने दूसरी औद्योगिक क्रान्ति की आवश्यकता पर जोर दिया है जो अधिक कार्यकुशल तथा अधिक रोजगारोन्मुखी होने की आशा है। यह क्रांति पूंजीगत सामान पेट्रोलियम उत्पादों तथा करते हुए धागें को मोडवेट के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। छूट के तहत लघु उद्योगों का पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत इकाइयों के रूप में वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया है। बड़े उद्योगों को मूल्यानुसार दी गई छूट अधिक लाभदायक है, नये संशोधन लघु औद्योगिक इकाईयों पर कर भार तथा उन की बिक्री को प्रभावित करेंगे।

छूटों को वापिस लेने के कारण बिक्री तथा कच्चे माल के मूल्य अधिक हो जायेंगे। अत: यह आवश्यक है कि लघु औद्योगिक इकाइयों की शुल्क मुक्त छूट सीमाओं के संबंध में स्लैब क्लीयरेंस वैल्यू को बढ़ा दिया जाये। इसके अतिरिक्त इसमें मूल्य वर्धन के सरल लेकिन प्रक्रियात्मक उपाय करने की आवश्यकता है। इसके साथ यह भी आवश्यक है कि लघु औद्योगिक इकाइयां अपनी प्रौद्योगिकियों को नवीकरण करें। होटलों पर व्यय कर में कमी करने से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा बने बनाये वस्त्र क्षेत्र में आयात कर में रियायतें दी जानी चाहिए क्योंकि वस्त्र क्षेत्र में निर्यात को बढ़ाने में बहुत क्षमता है। ब्याज दर में एक प्रतिशत की कमी से औद्योगिक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

इस बजट की एक अन्य विशेषता यह है कि ग्रामीण विकास की परिव्यय लागत में पिछले वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसके अंतर्गत ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। गांव में रोजगार उपलब्ध कराना, पीने के पानी की आपूर्ति, बागवानी विकास तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक कारगर बना कर इस बजट के माध्यम से स्वर्गीय राजीव गांधी के स्वप्न को पूरा किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में लम्बी अवधि के लिए ऋण उपलब्ध के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं। नाबार्ड, एस सी बी तथा डी सी सी बी से समझौता ज्ञापन के माध्यम से वित्त मंत्री जी सहकारी ऋण ढांचे को सुदृढ बनाना चाहते हैं। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि सहकारी ऋण संस्थाओं को स्थानीय क्षमता बचत जुटाने में समर्थ होना चाहिए। वित्तीय उदारीकरण के ढांचे में निचले स्तर तक की वित्तीय संस्थाओं को पुन:संगठित तथा मजबूत किया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने लम्बी अवधि के लाभ के लिए सहकारी ऋण संगठनों की पुर्नसंरचना पर जोर दिया है। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए पांच वर्ष तक कर मुक्त रियायतों की घोषणा की है। इससे क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में मदद मिलेगी।

महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा जो कि मेरे विचार से इस बजट या आने वाले बजटों के लिए आवश्यक होंगे।

पहला सुझाव यह है कि प्रत्यक्ष कर ढांचे को विस्तृत करना तथा कर दरों में और कमी करना जरूरी है। दूसरे सहकारी ऋण प्रणाली की पुन:संरचना करके ग्रामीण बचतों को इकट्ठा करने के काम में लगाया जाए तथा ग्रामीण वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऐसी संस्थाओं को आत्म निर्भर बनाया जाएं। तीसरे सभी प्रकार की राजसहायता निचले स्तर तक के लाभभोगियों तक पहुंचे। चौथे, यह देखना भी आवश्यक है कि कर छूट आम उपभोक्ताओं को मिलनी चाहिए। पांचवें, मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वित्तीय घाटे को पूरा किये वह उपस्थित ढंग से एक विस्तृत योजना तैयार करने का प्रयास करें कि वित्तीय घाटे को हम किस तरह पूरा कर सकते हैं।

मुझे कुछ मुद्दे और उठाने हैं। मैं ब्रान्ड नाम से संबंधित उपबंधों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। लघु औद्योगिक इकाइयों के पूर्तिकर्ता, जो मूल उपकरण निर्माताओं के आर्डर के अनुसार उत्पाद पर कोड नम्बर डालते हैं, को अब पूरे उत्पाद शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। उत्पाद पर केवल ड्राइंग, डिजायन, और कोड डालने से शुल्क की पूरी दर से भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रान्ड व ट्रेड के नाम कार्यो के अनुरूप रखने से संबंधित वर्तमान उपबंधों को तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए। ऐसे कार्य के लिए लघु औद्योगिक इकाइयों को दी जा रही छूटों को बने रहने देना चाहिए।

सेवाओं पर उत्पाद के बारे में, यह नया शुल्क विवादास्पद है। क्या इस पर पुर्नविचार करना संभव होगा क्योंकि अभी हाल ही में सेवाक्षेत्र विकसित होना शुरू हुआ है तथा इस शुल्क से इसके विकास पर बुरा असर डाल सकता है ?

अस्पतालों की एसोसिएशन ने शीर्ष संख्या 94-02 के अन्तर्गत आने वाली चिकित्सा, स्टील के फर्नीचर तथा इसके हिस्से (पार्ट) पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यानुसार 20 प्रतिशत लगाये जाने से संबंधित एक ज्ञापन दिया है। धर्मार्थ अस्पताल तथा कॉपरेटिव अस्पताल तथा अन्य अस्पतालों को देखते हुए, मैं माननीय मंत्री से पूरे मामले पर पुन: विचार करने का अनुरोध करता हूं।

जहां तक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद का संबंध है सेवाओं पर कर देने से स्वास्थ्य बीमा सेवाओं ने वरिष्ठ नागरिकों को भी प्रभावित किया है। मुझे विश्वास है कि सरकार की ऐसी मंशा नहीं थी अत: इस शुल्क को वापिस लेने पर पुन: विचार किया जाना चाहिए।

अपना भाषण समाप्त करते हुए, मैं कहना चाहूंगा कि यह बजट नि:संदेह एक व्यवहारिक बजट है और इससे सरकार ने भारतीय क्षेत्र के लोगों को तथा विदेशों में रहने वाले भारतीय का विश्वास प्राप्त किया है। इसका मुख्य कार्य मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना तथा कर- प्रशासन को प्रभावकारी बनाना है और इस प्रकार की वृहद प्राथमिकताएं है जिन पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मनमोहन सिंह जी ने जो चौथा बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा, क्योंकि इस बजट से महंगाई, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी और आर्थिक विषमता का समाधान नहीं होगा। यह बजट जन-विरोधी और मुद्रास्फीति को बढ़ाने वाला बजट है और खुले रूप से राजनीतिक बजट है। केवलमात्र कविताओं से या शायरी से, मौधर्य से लोगों की पीड़ा दूर नहीं होगी। चाशनी में लपेटने से कड़वी वस्तु की कड़वाहट दूर नहीं होती है। इन प्रयासों से माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट को अच्छा रूप देने का प्रयास किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, बजट से पहले ही राशन, चावल, चीनी, गैस, पैट्रोल, डीजल आदि के दाम बढ़ा कर 910 करोड़ रूपया अर्जित कर लिया गया, इसके पश्चात् यह आशा थी कि आने वाले बजट मे कोई नया कर नही लगाया जाएगा और इन्कम टैक्स की सीमा 50 हजार कर दी जाएगी, लेकिन सारी आशाएं धूमिल हो गई है। आप देखिए कि देश का राजकीय कोष का घाटा कहां से कहां पहुंच गया है।

1991 जो सरकारी तौर पर सबसे अधिक बुरा साल था, राजस्व घाटा 18 हजार करोड़ का था और आज राजस्व घाटा 34 हजार करोड़ तक पहुंच गया। क्या यही आपकी सफलता का मापदंड है? वित्त मंत्री जी ने अपने पिछले भाषण में कहा था कि राजकोषीय घाटे को सकल राष्ट्रीय उत्पाद से 4.7 प्रतिशत कम रखेंगे। यह बजट विदेशी कंपनियों को मदद देने के लिए बनाया गया है। पहले हमारे बजट में सीमा शुल्क का 26.75 परसेंट योगदान होता था, लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी की मेहरबानी से अब यह योगदान मात्र 15 प्रतिशत रह गया है। यह लाभ सीधा ही विदेशी कंपनियों को दिया गया हैं। वित्त मंत्री जी ने मार तो इस देश के गरीब कारीगरों पर लगाई है। सुना है कि अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान के मखमल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए थे ताकि इंग्लैंड का कपड़ा हिन्दुस्तान में बिक सके। आज वही काम हमारी सरकार भी कर रही है जो लघु उद्योग हमारे कपड़ा निर्यात का 30 से 35 प्रतिशत हिस्सा उत्पन्न करता है उसे यह बजट अकाल मृत्यु का संकट प्रदान करता है। जिस एक किलो सूती धागे पर पहले 16 पैसे का कर लगता था अब वह बढ़कर तीन रूपये साठ पैसे हो गया है।

कारपेट उद्योग पर संकट पहले से ही है क्योंकि राजस्थान की वूलन कारपेट इंडस्ट्री पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग कम हो जाने से गंभीर संकट का सामना कर रही थी। वित्त मंत्री जी ने वूलन यार्न पर 17.25 परसेंट एक्साईज डयूटी लगा दी है। इस उद्योग से लगभग दस लाख श्रमिकों को रोजगार

मिलता है और लगभग 1100 करोड़ रूपये का निर्यात करता है। उद्योग के नष्ट होने से दस लाख श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे।

आपकी कृपा दृष्टि गरीब जूता मजदूरी पर क्यों जा गिरी? आपने क्या सोचकर हाथ से जूता बनाने वालों को मशीन से जूता बनाने वालों की बराबरी पर खड़ा कर दिया। हाथ से जूता बनने वाले जूतों पर भी एक्साईज डयुटी लेने लगे हैं। क्या आप ऐसा मल्टीनेशनल जूता कंपनियों को खुश करने के लिए कर रहे है। जूता लघु उद्योग कुल जूते व जूतों की सामग्री का 40 से 80 प्रतिशत हिस्सा निर्यात करते हैं। इस उद्योग के लाखों श्रमिकों को भूखमरी से बचाने का दायित्व इस सदन पर है। यह सरकार राजस्थान से कुछ नाराज है। राजस्थान के कारपेट, जूता उद्योग और साथ ही साथ राजस्थान के मारबल उद्योग को आपकी मार लगी है। इस पर भी आपने एक्साईज डयूटी लगा दी है। यह राजस्थान का औद्योगिक रूप से पिछड़े इलाकों का इकलौता उद्योग है। इस उद्योग में 20 लाख श्रमिक काम करते हैं लेकिन आप प्रगति की खिड़की को बंद कर रहे हैं। आप छह करोड़ रूपए का लाभ राजस्थान के मारबल उद्योग से कमाने जा रहे हैं तो उसे बहुराष्ट्रीय सिरेमिक टाईल्स उद्योग को क्यों दे रहे हैं? बहुराष्ट्रीय सिरेमिक टाईल्स पर 15 प्रतिशत एक्साईज छूट और राजस्थान के मारबल पर शत-प्रतिशत की वृद्धि, ऐसा भेदभाव क्यों? अपनों पर जूता और परायों पर प्यार क्यों? क्या यह निर्देश आपको विश्व बैंक ने दिया है?

इसी प्रकार से माननीय वित्त मंत्री जी बतायें कि बेरोजगारी बढ़ी है या घटी है? लघु उद्योग पर मार उस समय की जा रही हैं जबकि देश में बेराजगारी बढ़ रही है। आठवीं योजना में दो करोड़ तीस लाख व्यक्ति बेरोजगार थे जिसमें से सत्तर लाख पढ़े- लिखे थे। इस योजना के अंदर चार करोड़ लोग और बेरोजगारों की श्रेणी में आ जायेंगे। आपने आश्वासन दिया था कि एक करोड़ रोजगार के अवसर निर्मित किये जायेंगे। लेकिन आपकी सरकार 5.8 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने में असफल रही है, जो उसने सोची थी इस योजना के पहले वर्ष में आपको अनुमान था कि साठ लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि दो करोड़ में दस लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि दो करोड़ में दस लाख बेरोजगार और जुड गये। आखिरकार मंहगाई कम होने वाली नहीं है, वह और बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है तो आप किस लिए वित्त मंत्री बने हुए है। आपसे लोगों को बहुत आशा थी। आप बतायें कि बेरोजगारी की विकराल समस्या से कैसे निपटेंगे? छोटे उद्योगों पर एक्साइज लगाकर उन्हें बंद कर दिया है। सार्वजनिक उपक्रमों में वही सारा रोग अभी तक मौजूद है। आपने केवल बजट में कारीगरी दिखाई और कह दिया कि खर्च को कम कर दिया, खर्च कम करने के नाम पर आपने चिकित्सा पर, शिक्षा पर खर्च कम कर दिया, सार्वजनिक उद्योगों पर खर्च कम कर दिया। इसी प्रकार सार्वजनिक सुरक्षा पर भी खर्च कम कर दिया। आपने इन सब पर खर्चा कम कर दिया।

वर्ष 1994-95 के बजट में सिंचाई क्षेत्र के लिए आंबटित जो पहले राशि थी उसमें 6 प्रतिशत की कमी कर दी। इससे जल संसाधन की जो विकास गति होनी चाहिए थी, वह नही होगी। राजस्थान से जहां से मैं आता हूं, हिन्दुस्तान की जनसंख्या का वहां 5 प्रतिशत हिस्सा रहता है। वहां पर इतनी नदियां हैं, लेकिन हमें केवल एक प्रतिशत जल मिलता है। पानी के अभाव में हमारे 11 जिले जो रेगिस्तान से भरपूर है, सिंचाई के साधन कम कर दिये जाने पर काफी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। एग्रो बेस्ड पेपर इंडस्ट्री को भी राहत नहीं दी है। आपने इसी प्रकार ट्रैक्टरर्स के दाम बढ़ा दिये, खेल के क्षेत्र में भी कटौती कर दी है। आपने पहले जिन 580 वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क में छूट दे रखी है, इस बजट में एक ही वाक्य में कह दिया कि मैं वह छूट समाप्त कर रहा हूं। छतरी पर कर लगा दिया, प्लास्टिक के सामान पर कर लगा दिया। पापड़ पर कर लगा दिया, ऊन पर कर लगा दिया। प्रत्येक गृह उद्योग पर कर लगा दिया। गृहिणी जो सूत

बनाती थी, पापड़ बनाती थी, ऊन के स्वेटर बनाती थी, उस पर कर लगा दिया। अब इंस्पेक्टर जाकर कहता है कि उत्पादन शुल्क लाओ और अपने खातों की जांच कराओ।

आयुर्वेदिक दवाये जिनका 76 करोड़ रूपये का निर्यात था, उस पर भी 10 प्रतिशत उत्पादन शुल्क लगा दिया। आपको इन चीजों पर कर को वापस लेना चाहिए।

खर्च तो आखिरकार बढ़ रहा है। आपके मंत्रियों की फौज पर बराबर खर्च हो रहा है। 1990-91 में मंत्रियों पर 6.38 लाख रूपया खर्च होता था जो कि अब बढ़कर 16.93 लाख रूपये हो गया है। उनके टी. ए. और डी. ए. पर पहले 433.58 लाख रूपये खर्च हुआ करता था, अब बढ़कर 3486.06 लाख रूपये हो गया है यानि लगभग नौ गुणा की वृद्धि हुई है। आपको इस पर कमी करनी चाहिए थी। इसके अलावा मंत्रियों के आवागमन और आवभगत पर होने वाला खर्च अलग है। वह भी बहुत ज्यादा है। उन पर तो कमी नहीं की, उल्टे लघु उद्योगों और गरीबों पर मार कर दी। आपको यह शोभा नहीं देता।

बजट में महाकांड बैंक घोटाले की क्या भूमिका है, इसका कुछ पता नही चल रहा है। पता नही रूपया कहां से आता है और भुगतान किस प्रकार से हो रहा है। इसको भी स्पष्ट करना चाहिए। यदि आप इन सारी बातों को छुपाना चाहते है तो मुझे लगता है बजट का घाटा और बढ़ेगा। मैं आपके इस राजनैतिक बजट, बेरोजगारी बढ़ाने वाले बजट, मंहगाई बढ़ाने वाले बजट, मुद्रास्फीति बढ़ाने वाले बजट और आर्थिक विषमता बढ़ाने वाले बजट का घोर विरोध करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपका जैसा नाम है मनमोहन सिंह, आपसे आशा थी कि आपका मन मोहक होगा, वह वैसा नही है। आप जब बजट पेश करते हुए कविता और शायरी करके मीठी-मीठी भाषा में भाषण करते है तो उस वक्त तो कुछ समझ में नहीं आता लेकिन जब बजट को गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि आप मनमोहन नहीं लोगों को कष्ट देने वाले मंत्री है।

मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा आपका नाम है, वैसा ही कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

पी. जे. कुरियन (मवेलीकरा) : मुझे बोलने का अनुमति देने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। मुख्य बात का जिक्र करने से पहले मैं श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा उठाए गए एक मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहूंगा। वह अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा पर खर्च की गई धनराशि की बहुत आलोचना कर रही थीं। मुझे खेद हैं माननीय सदस्य को ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि जबकि हम सब जानते है कि हमारी राष्ट्रीय नेता श्रीमती इन्दिरा जी और राजीव जी के साथ क्या हुआ और उनको कितना खतरा था। अत: मैं वित्त मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि हमारे नेताओं की सुरक्षा के लिए सभी संभव प्रबंध किये जाने चाहिए। हमें श्री राजीव गांधी की हत्या का अनुभव हो चुका है। उनको प्रदान की गई एस. पी. जी. सुरक्षा वापस ले ली गई थी। श्री भाटिया जी यहां उपस्थित हैं, उन पर भी पंजाब में कातिलाना हमला हुआ था। ईश्वर का शुक्र है कि वे सुरक्षित हमारे बीच मौजूद हैं। अत: हमारे राष्ट्रीय नेताओं की सुरक्षा का मामला ऐसा नहीं है जिसे केवल अवसरों पर छोड़ दिया जाये। मुझे खेद है कि एक माननीय सदस्य ने सुरक्षा व्यवस्था पर खर्च की जाने वाली धनराशि की आलोचना की है।

मैंने कुछ माननीय सदस्यों को ईस्ट इण्डिया कं० के बारे में बोलते हुए सुना था। यह बहुत ही निराशपूर्ण बात है कि ईस्ट इण्डिया कं० की घटना का भय अभी तक लोगों में विद्यमान है।

महोदय, यह देश कोई बाजारू गणराज्य नहीं है कि कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी इसे हड़प ले। हम लोग अब ईस्ट इण्डिया कं० का उदाहरण देकर अपनी अवमानना कर रहे हैं। हमारा देश एक सशक्त देश है। कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी या कोई अन्य देश हमारे देश को हड़प नहीं सकता है। जो ढांचागत परिवर्तन या आर्थिक नीति में परिवर्तन किए गए हैं उनका निर्णय लोगों की भलाई के लिए सोच विचार कर लिए गया निर्णय हैं। आप इससे असहमत हो सकते है, परन्तु बार-बार ईस्ट इण्डिया कंपनी का उदाहरण देना निश्चित ही हमारे लिये अपमानजनक हैं जो सुधारों की आलोचना करते हैं वे किसी वैकल्पिक व्यवस्था या वैकल्पिक प्रणाली का आदर्श स्थापित नहीं कर पाते हैं।

वर्ष 1991 में हम गम्भीर संकट में थे जब ऋण प्राप्त करने हेतु हमारी साख बहुत गिर गई थी और मुद्रास्फीति 17 प्रतिशत हो गई थी। यदि श्री नरसिंहराव के नेतृत्व वाली इस सरकार और वित्त मंत्री स० मनमोहन सिंह ने कुछ कदम न उठाये होते तो मैं कह नहीं सकता हूं कि क्या होता। यहां तक कि हमारी हालत भी सोवियत संघ जैसी हो सकती थी। अत: मैं यह कहूंगा कि इस सरकार ने देश को बचाया है। जो लोग आलोचना करते हैं, वे यह क्यों नहीं देखते हैं कि हमारे देश के आस-पास के देशों में क्या हो रहा है? निश्चय ही चीन ने हमसे काफी पहले अपनी अर्थव्यवस्था को लचीला बना लिया था और वे उसके लाभ उठा रहे हैं। दो वर्ष पहले मुझे चीन जाने का अवसर मिला था। मैंने स्वयं वहां हुए परिवर्तन को महसूस किया है। मैंने वहां पर कम्युनिस्टों, स्थानीय नेताओं और अन्य लोगों से बातचीत की थी।

अत: हमें इन वास्तविकताओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि दूसरे पक्ष के हमारे माननीय मित्र पिछले तीन वर्षों की हमारी उपलब्धियों को मज़ाक बना रहे हैं। मैं उनकी बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। इन उपलब्धियों की जानकारी सबको है।

हमारी विदेशी मुद्रा का भण्डार जो 1990-91 में एक मिलियन डालर था, यह बढ़कर 13 मिलियन डालर हो गया है। विपक्ष इस वास्तविकता को जानबूझकर स्वीकार नहीं करना चाहता है। अत: वे वर्ष-वार आंकडे जानना चाहते है। वर्ष-वार आंकडे कुछ भी हो, 13 मिलियन डालर का विदेशी मुद्रा भण्डार होना एक सराहनीय बात है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था में स्थिरता आयी है और इसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हो पायी है। यदि सम्पूर्ण 13 मिलियन डालर विदेशी मुद्रा सीधे निवेश से प्राप्त हुई होती तो मुझे प्रसन्नता होती। परन्तु इसमें से कुछ तो पोर्टफोलियों निवेश हो सकता है और कुछ अप्रवासी भारतीयों की जमा धनराशि। यदि देश की अर्थव्यवस्था उल्टी दिशा में जाती है तो सभी भण्डार समाप्त हो जायेंगे

13 मिलियन डालर का विदेशी मुद्रा भण्डार इस बात का संकेतक है कि पिछले तीन वर्षों में हमारे देश ने किस प्रकार आर्थिक स्थिरता प्राप्त की है। इसका आप कम आंकलन न करें। इसके अलावा आप यह भी देखें कि निर्यात में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है; जबकि वर्ष 1990-91 में यह निर्यात 3 प्रतिशत था। यह न के बराबर था। सभी लोग आयात की बात करते हैं, अत्यधिक आयात, परंतु आयात के आंकड़े देखिये।

मैं भी इस पर अपनी सहमति देता यदि आयात में भी लगातार वृद्धि हो रही होती। आयात में वृद्धि नहीं हो रही है।

वस्तुत: चालू वर्ष में आयात वर्ष 1990-91 के आयात के लगभग बराबर है। अनियमन से पहले प्रतिवर्ष आयात में वृद्धि हो रही थी। अत: केवल यह कहना कि केवल उदारीकरण के कारण आयात में वृद्धि होगी, यह सही नहीं है। यह बात नहीं है कि जो भी पैसा है उससे सब लोग आयात ही करेंगे। तथ्य यह है कि आयात के मुकाबले निर्यात में अधिक वृद्धि हो रही है। आयात केवल बहुत धीमी गति से बढ़ रहा है।

इन सब कारणों से विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है और यह भी सच है कि मुद्रा स्फीति 17 प्रतिशत से कम होकर 8 प्रतिशत हो गई है। आपको इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए। कि अर्थव्यवस्था में ढांचागत

परिवर्तनों से अच्छे परिणाम सामने आये हैं। आपको यह तथ्य स्वीकार करना चाहिये। हमें वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। जहां आप सहमत न हो, वहां आप कह सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है।

ऋणग्रस्तता के बारे में बहुत कुछ-कहा जा चुका है। मैंने बहुत ही जिम्मेदार माननीय सदस्यों को यह कहते हुए सुना है कि हम ऋणग्रस्तता की ओर जा रहे हैं, पर मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है। यदि ऐसा है तो इसका मतलब यह है कि वित्त मंत्री महोदय ने गलत आंकड़े दिये है। यदि मैं वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट अभिभाषण में दिये गये इन आंकड़ो पर विश्वास करूं तो वर्ष 1990-91 में हमारा विदेशी ऋण बढ़कर 8 बिलियन डालर हो गया था वर्ष 199-91 में यह 3 विलियन डालर और बढ़ गया था; वर्ष 1992-93 में भी यह उसी दर से बढ़ा था परन्तु इस वर्ष पहले छ: महीनों में यह ऋण राशि केवल 300 मिलियन डालर थी अर्थात् कुल ऋण के 1/10वां भाग इसका अभिप्राय विदेशी ऋण की दर पर नियंत्रण पा लिया गया है। यदि ऐसा है तो क्या हम ऋणग्रस्तता में फंस रहे है। या हम इससे बाहर निकल रहे हैं? मेरी समझ में यह नहीं आता है कि किस प्रकार कोई भी माननीय सदस्य यह कर सकता है कि हम ऋणग्रस्तता में फंस रहे हैं? यदि ये आंकड़े गलत है, तो कृपया मुझे बतायें। कोई भी तर्क यह सिद्ध नहीं कर सकता है कि हम ऋणग्रस्तता की ओर जा रहे हैं। वास्तव में सरकार द्वारा किये गये उपायों के कारण हम ऋणग्रस्तता से बचते जा रहे हैं।

इसके अलावा हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की किश्तों की निर्धारित समय से काफी पहले अदा कर देते हैं। इसके लिए मैं वित्त मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। यही वास्तविकता है तो फिर अर्थव्यवस्था के संकटग्रस्त होने का प्रश्न कहां उठता है; इस संबंध में कई तरह ही बातें कही गई है।

मैं नहीं जानता कि कुछ माननीय सदस्यों ने रोजगार कार्यालय के आंकड़ों पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगाया है। सत्ता पक्ष के भी एक दो माननीय सदस्यों ने ऐसा किया है। रोजगार कार्यालयों में दर्ज व्यक्तियों के नामों से देश में बेरोजगारी का संकेत मिलता है। यह जरूरी नहीं है कि वे लोग जिन्होंने रोजगार कार्यालयों में अपने नाम दर्ज किये हैं, वे बेरोजगार हों। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जिनका नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज है, परन्तु उनके पास कुछ न कुछ रोजगार है। परन्तु फिर भी रोजगार कार्यालयों में दर्ज नामों से देश में बेरोजगारी का संकेत मिलता है। यदि किसी एक वर्ष में रोजगार कार्यालय में दर्ज नामों में 1.4 प्रतिशत की गिरावट आई है, तो आप इसे सरकार द्वारा किये गये नये उपायों का सकारात्मक परिणाम क्यों नहीं मानना चाहते हैं?

मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि उदारीकरण का मतलब न केवल विदेशों से बल्कि देश के भीतर भी अधिक पूंजी का निवेश करना है। यह इसलिए है क्योंकि निवेश के क्षेत्र में एक नया माहौल तैयार किया गया है और इसके फलस्वरूप और अधिक निवेश किया जा सकता है। अत: अधिक रोजगार, अधिक निवेश और अधिक व्यापार। निर्यात में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इसका मतलब है, अधिक कारोबार और अधिक कारोबार का मतलब है अधिक रोजगार। अत: आप इस तथ्य को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं कि पिछले एक वर्ष के दौरान अधिक कारोबार हुआ, अधिक निवेश किया गया, अत: अधिक रोजगार का सृजन किया गया। अत: इस समय रोजगार कार्यालयों में दर्ज व्यक्तियों की संख्या में गिरावट आयी है। ये ऐसे ठोस तथ्य हैं जिस बारे में मैं समझता हूं कोई विवाद नहीं कर सकता । मुझे आशा है कि विपक्ष के मेरे माननीय मित्र इस बात को स्वीकार करेंगे।

मैं औद्योगिक क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जो कुछ भी मैंने कहा वह सकारात्मक पक्ष की कुछ बातें हैं। परंतु मैं इस बात से भी सहमत हूं कि कुछ क्षेत्र ऐसे है जो चिंता के विषय हैं। सर्वप्रथम औद्योगिक क्षेत्र है।

औद्योगिक विकास उतना नहीं हुआ है जितनी कि अपेक्षा थी और चालू वर्ष के दौरान यह विकास दर दो प्रतिशत से भी कम रही है। वित्त मंत्री महोदय ने यह कहा है कि इसका कारण यह है कि पूंजीगत क्षेत्र का कार्य निष्पादन अच्छा नहीं रहा है। यह समझा जा सकता है, क्योंकि उद्योगों के पुर्नगठन में पुर्नरचना के लिये कुछ समय लगेगा और निश्चित ही पूंजीगत क्षेत्र कुछ और अधिक समय लेंगे। तथापि, मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि केवल पूंजी क्षेत्र में औद्योगिक विकास में स्थिरता लाने के लिए क्या यह वास्तविकता के अनुरूप है।

2.59 म०प०

(प्रो० रीता वर्मा पीठासीन हुई)

मैं चाहता हूं कि वे इस बात की निष्पक्ष रूप से जांच करें कि क्या सुधारों के परिणामस्वरूप हमारे उद्योग पर काफी अधिक प्रतिस्पर्धात्मक दबाव पड़ा है।

यद्यपि मैं उदारीकरण और आर्थिक सुधारों संबंधी उठाये गये कदमों का पूर्णत: स्वागत करता हूं, तथापि मैं यहा केवल यही चेतावनी देना चाहूंगा कि हमें बुनियादी वास्तविकताओं को समझते हुये यह काम लिखित रूप से उसी ढंग में करना चाहिए। जो हमारी स्थितियों के उपयुक्त हो। माननीय मंत्री जी भी यह बात जानते हैं। इसी कारण उन्होंने आयातित पूंजीगत सामान पर बराबर शुल्क लगाया है।

3.00 म०प०

मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री इस बात का अध्ययन करें कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक दबाव के कारण कौन-कौन से क्षेत्र प्रभावित हुये हैं? हमारे यहां भंडार -विरोधी कानून है। उस कानून को और अधिक कठोर बनाया जाना चाहिए। इसे और अधिक ठोस बनाया जाना चाहिए। नि:संदेह मूल्य में कटौती अथवा कमी करके माल के ढेर लगाने से भारतीय उत्पादों को हानि पहुंचती है अथवा पहुंचने की संभावना हो सकती है। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री इस पहलू की जांच करें।

लघु क्षेत्रों की बात पर आते हुये प्रत्येक सदस्य ने इस संबंध में कुछ उल्लेख किया था। इस बारे में मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। यह हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मैं कहूंगा कि यह एक बेजोड़ क्षेत्र है। कृपया यह न सोचें कि हमारे देश में इस क्षेत्र की प्रौद्योगिकी निकृष्ट है। जी नहीं। हमारे निर्यात का 40 प्रतिशत भाग लघु क्षेत्र से प्राप्त होता है। इस क्षेत्र की प्रभावात्मकता के लिए इससे अधिक और क्या प्रमाण पत्र चाहिए? उदारीकरण इस प्रकार का होना चाहिए कि लघु क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित रखा जा सके। माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस सदन में और इसके बाहर कई बार यह कहा है कि इस क्षेत्र को सुरक्षित रखा जायेगा ओर मैं जानता हूं कि वित्त मंत्री लघु क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए अपने काम से पीछे नहीं हट रहे हैं। मुझे उनसे मिलने और इस विषय पर चर्चा करने का अवसर मिल चुका है। मैं जानता हूं कि वे भी इस क्षेत्र को सुरक्षित रखने की आवश्कता महसूस करते है। यदि इस वर्तमान बजट में कदाचित अथवा अनजाने में यह क्षेत्र प्रभावित होता है, तो मैं चाहता हूं कि उसमें सुधार किया जाये।

वैज्ञानिक पुनगर्ठन संबंधी कार्य अच्छा है। वित्त मंत्री ने अधिसूचनाओं की संख्या में कटौती की है। कृप्या यह देखा जाये कि इसने किसे प्रभावित किया है। यदि इसने लघु क्षेत्र को प्रभावित किया है तो मैं उसका समर्थन नहीं करता। मेरा कहना है कि वैज्ञानिक पुनगर्ठन और पुन:सरंचना हमारे अपने तरीके अर्थात भारतीय पद्धति से की जानी चाहिए। चीन, जिसने हमसे काफी पहले ही सुधार कर लिया है, ने भी अपने तरीके से सुधार कार्य कर लिया है, ने भी अपने तरीके से सुधार कार्य किया है। उन्होंने सुधार के लिए कतिपय क्षेत्रों का चयन किया था। उस क्षेत्र में, हमसे हमारे देश से बहुत अधिक पूर्णत: उदारीकरण हुआ है। वे कार्य दूसरे ढंग से करते हैं। **(व्यवधान)**

कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मुझे अपनी बात कहने दीजिए।

सभापति महोदया : कृपया उनके भाषण में व्यवधान न डालें।

प्रो. पी. जे. कुरियन : मेरा कहना यह है कि अपने देश की मूल वास्तविकताओं को समझते हुयें, हमें अपने सुधारों को क्रियान्वित करना चाहिए। ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए जिससे लघु क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, एकक निवेश से कभी-कभी लघु क्षेत्र बड़े क्षेत्रों की तुलना में दस गुणा ज्यादा रोजगार के अवसर का सृजन करेगा। इसलिए, यदि इस क्षेत्र को कुछ रियायतें दी भी जाती हैं तो इसका स्वागत है। लेकिन दुर्भाग्य से, कुछ उपायों ने इस क्षेत्र को प्रभावित किया है। यहां कई उद्धरण दिये गये हैं। मुझे बताया गया है कि नया उत्पाद शुल्क लगाने के कारण हवाई चप्पल बनाने वाली कुछ इकाईयां बंद होने जा रहीं हैं।

इसी प्रकार छाते पर भी उत्पाद शुल्क लगाया गया है। हवाई चप्पलों का प्रयोग गरीब जनता द्वारा किया जा रहा है। इसी तरह हस्तनिर्मित साबुन पर भी उत्पाद शुल्क लगाया गया है। ऐसे अनेक दूसरे उत्पाद हैं जिनपर उत्पाद शुल्क लगाया गया है। श्री चार्ल्स कह रहे हैं कि मछली पकड़ने के जाल पर भी उत्पाद शुल्क लगाया गया है। मुझे कीटनाशकों के संबंध में भी अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं।

आयुर्वैदिक दवा के संबंध में, हालांकि यह लघु उद्योग के क्षेत्र में नहीं है, फिर भी इस पर कर नहीं लगना चाहिए। आयुर्वैदिक दवा हमारे देश की महान सम्पत्ति, महान परिसंपदा और महान कुल परंपरा हैं। इसलिए, इस क्षेत्र को कुछ विशेषता दी जानी चाहिए। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे उन उपायों पर पुनर्विचार करें जो इस बजट के माध्यम से लाये गये हैं जिसने लघु क्षेत्र को प्रभावित किया है।

अब मैं वित्तीय घाटे की बात पर आता हूं। माननीय वित्त मंत्री चाहते थे कि यह सकल घरेलू उत्पाद का 4.7 प्रतिशत होना चाहिए लेकिन यह बढ़कर 7.3 प्रतिशत हो गया है। मेरे विचार से विपक्ष के मित्र सदस्य प्रसन्न होंगे क्योंकि वित्त मंत्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आदेशों, यदि कोई हों, का पालन नहीं कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यह चाहता है कि वित्तीय घाटे को कम करना चाहिए। लेकिन वित्त मंत्री ने स्वेच्छा से वित्तीय घाटे को 7.3 प्रतिशत तक पहुंचने की अनुमति दी थी और अगले वर्ष के लिए वे इसे 6 प्रतिशत कर रहे है। मेरे विचार से विपक्ष यह कहते हुये उनकी आलोचना नहीं कर सकता कि वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आदेशों के अनुसार कर रहे हैं। लेकिन मैं वित्त मंत्री जी का इस व्यापक अंतर को रखने के लिए एक भिन्न आधार के संबंध में समर्थन करूंगा। वे इस अंतर को पूरा कर सकते थे। वित्त मंत्री यहां पर उपस्थित हैं जिन्होंने गरीब जनता पर पर्याप्त ध्यान देकर और गरीबी हटाओ कार्यक्रम पर बल देकर एक-एक करके सुधारों को क्रियान्वित किया है। वे गरीबी हटाओ कार्यक्रम पर होने वाले व्यय को कम करके इस अंतर को पूरा कर सकते थे, वे रक्षा संबंधी व्यय में कमी कर सकते थे और वे राजसहायता पर होने वाले व्यय में कमी कर सकते थे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की इच्छा यदि कोई है के विरूद्ध और आपकी इच्छाओं के खिलाफ, चूंकि आप चाहते थे कि राजसहायता में कमी की जानी चाहिए ताकि आप यह आरोप लगा सकें कि वित्त मंत्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार कार्य कर रहा है, उन्होंने राजसहायता में कमी नहीं की। वित्त मंत्री ने आपके हाथ से अंकुश ले लिया है। उन्होंने खाद्य और उर्वरक संबंधी राजसहायता में वृद्धि की है। इसलिए, यह अंतर है। उन्होंने पिछले दो वर्षों में ग्रामीण विकास परिव्यय में 100 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि की है। वर्ष 1992-93 में यह 3,100 करोड़ रूपये थी और आज यह बढ़कर 7010 करोड रूपये हो गया है अर्थात् इसमें 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। मेरे विचार से, किसी अन्य क्षेत्र में इस प्रकार की अत्यधिक वृद्धि नहीं हुई है। इसका अर्थ है कि उन्हें गरीब जनता की वास्तव में चिंता

है और वे यह नहीं चाहते कि गरीबी हटाओ कार्यक्रम को नुकसान पहुंचे। लेकिन आप सबको निराशा हुई है क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संलक्षण पुन: नहीं जा सकते। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। चालू वर्ष के आंकड़ों को पुन: देखते हुए, अंतर में बजट अनुमानों में 4.7 से 7.3 की वृद्धि हुई है। इसलिए क्या सकल घरेलू उत्पाद के 6.0 प्रतिशत निर्धारित लक्ष्य से, पिछले वर्ष के वित्तीय घाटे में और अधिक वृद्धि की जाये? मुझे आशा है कि औद्योगिक क्षेत्र बेहतर ढंग से कार्य करेगा, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होगी और निश्चित रूप से हम वित्तीय घाटे को 6.0 प्रतिशत पर रखने में सफल हो जायेंगे। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री यह सुनिश्चित करें कि आगामी वर्ष में, किसी भी स्थिति में घाटे में वृद्धि न हो।

अगर उसमें फिर से वृद्धि होती है, तो मुद्रास्फीति होगी। इसका अर्थ है कि हर चीज का उल्टा होगा।

उसमें उन्होंने ब्याज की न्यूनतम दर में 1 प्रतिशत की कमी की है। उन्होंने लघु उद्योग क्षेत्र के लिए कुछ अच्छे काम भी किये हैं। उन्होंने पंजीकृत और अपंजीकृत इकाइयों के बीच अंतर को समाप्त किया है। इसकी मांग काफी अर्से से की जा रही थी। उन्हें देश में ही विकसित प्रौद्योगिकी की चिंता है। हमारे देश के वैज्ञानिक दूसरे देशों के वैज्ञानिकों से किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हैं। वस्तुत: मैं तो यह कहूंगा कि वे उनसे बेहतर हैं। आप जानते है कि आई आई टी के हमारे कई उत्पाद विदेशों में जा रहे हैं और वहां उनकी काफी मांग है। लेकिन कभी-कभार हमारे वैज्ञानिकों द्वारा देश में विकसित की गई प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिक उपयोग नहीं हो पाता। खोज और वाणिज्यिक उपयोग के बीच किसी चीज का अभाव है। संभवत: ऐसा निधियों के अभाव के कारण हो। वित्त मंत्री ने इस समस्या को समझा है और देश में ही विकसित प्रौद्योगिक के वाणिज्यिक उपयोग हेतु निधियों का प्रावधान किया है। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र था, जिसकी उपेक्षा की गई। माननीय प्रधान मंत्री ने स्वयं यह घोषणा की थी कि इसके लिए अत्यधिक परिव्यय का प्रावधान किया जायेगा और उस पथ का अनुसरण करते हुये, उन्होंने प्राथमिक शिक्षा और विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग, दोनों की शिक्षा के लिए आबंटन में वृद्धि की है। मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय : प्रो. कुरियन कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें। अन्य सदस्य भी बोलना चाहते हैं।

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदया, मैं केवल दो मिनट का समय और लूंगा। महोदय, वित्त मंत्री ने नकदी फसलों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है। शून्य काल के दौरान आज भी इस मामले को सदन में उठाया गया था। केरल में नकदी फसलों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, नारियल। इसके अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं। एक मूल्य समर्थन पद्धति होना चाहिए। मैं उनको आग्रह करूंगा कि वे इस और ध्यान दें और समर्थन मूल्यों के लिए पर्याप्त धन राशि की व्यवस्था करें।

कृषि क्षेत्र में, कुछ कृषि विज्ञान केन्द्रो के खोले जाने का प्रस्ताव था। मैं नहीं जानता कि उन प्रस्तावों का क्या हुआ। इस योजना की घोषणा पिछले वर्ष की गई थी। वह लाल-फीते शाही के नीचे कही छिप गयी है। मैं नहीं जानता कि उसका क्या हुआ। कोई धन राशि नहीं रखी गई है। मुझे बताया गया है कि योजना आयोग को इसमें आपत्ति है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस योजना को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के साथ तुरंत लागू किया जाए। राज्य इस योजना के लिए धन राशि देने में असमर्थ हैं।

पिछले वर्ष, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कायमकुलम-ताप-परियोजना, जिसकी घोषणा स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने 1987 में की थी, के लिए केन्द्र द्वारा कुछ धन राशि उपलब्ध कराया गया था। यह परियोजना अभी तक शुरू नहीं हुई है। पिछले वर्ष केंद्र ने कायमकुलम-ताप-परियोजना के लिए कुछ धनराशि उपलब्ध करायी थी। मैं नहीं जानता इस वर्ष उसका क्या हुआ है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस प्रस्ताव

पर विचार करें और कायाकुलम ताप परियोजना को लागू करने के लिए केन्द्र की ओर से जोर लगाया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को समर्थन दें। मैं माननीय वित्त मंत्री से भी आग्रह करूंगा कि उन क्षेत्रों में, विशेष कर लघु उद्योग क्षेत्र में, जहां बजट में भारी कटौती की गई है, पर पुन: विचार किया जाए। मैं आशा करता हूं कि आप इन असंगतियों को सुधारेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट की समर्थन करते हुए, अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब श्री तेज नारायण सिंह बोलेंगे। सभी सदस्यों ने स्वीकार किया है कि वे लम्बा भाषण नहीं देगें। वे केवल 10 मिनट ही बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री तेजनारायण सिंह (बक्सर) : माननीय सभापति महोदया, मैं इस बजट का विरोध करता हूं। विरोध इसलिए करता हूं कि यह बजट गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है। यह देश और विदेश के पूंजीपतियों को मालामाल बनाने वाला बजट है। मैं इसलिए इस बजट का विरोध करता हूं माननीय वित्त मंत्री ने यह चौथा बजट पेश किया है। इन्होंने 1991 में बजट पेश किया था उस समय विपक्ष की तरफ से जब आलोचना हुई तो इन्होंने कहा कि इसका फल आपको आगे देखने को मिलेगा। इन्होंने अपने भाषण में कहा था कि जब मैं चौथा बजट पेश करूंगा तो देश की हालत बहुत सुधर जाएगी, बेकारों की कमी हो जायेगी, सिंचाई का अधिक-से-अधिक इंतजाम हो जाएगा और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या घट जाएगी। लेकिन मैं देखता हूं कि चौथे बजट में भी वही स्थिति है जो स्थिति पहले 1991 के बजट में थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरसिंह राव जी ने भाषण दिया था कि मैं इस तरह की व्यवस्था करना चाहता हूं जो देहातों से शहर में आने की कोशिश करते हैं वे शहर में न आएं और मैं शहर की तरह ही देहातों को भी बना दूंगा।

महोदय, उन्होंने कहा था कि जो छोटे उद्योग हैं उनको मैं प्रधानता दूंगा और जो छोटे उद्योग शहर में लगाए जाएंगे वे देहात में भी लगाए जाएंगे। लेकिन बजट को देखने से मालूम होता है कि जो भी सीमेंट के छोटे उद्योग इस देश में थे उन तमाम उद्योगों पर इतना टैक्स बढ़ा दिया गया है कि वे सब के सब बंद होने वाले है, कुछ तो बंद हो गये है और कुछ होने वाले हैं। जहां 6 सौ टन का उत्पादन होता है उस पर 185 रूपया टैक्स लगा है और जिस फैक्ट्री में 3 सौ टन का उत्पादन होता है उस पर तीन सौ रूपया लगा है। आप खुद ही देख लीजिए कि इससे बड़े उद्योग पनपेंगे और जो हमारे छोटे उद्योग हैं वे समाप्त हो जाएगें और इस टैक्स की बढ़ोतरी से ढाई करोड़ मजदूर बेकार होने वाले हैं। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस बात पर आप विचार करें कि छोटे उद्योगों पर टैक्स लगाना चाहिए या नहीं। मेरी मांग है कि छोटे उद्योंगों पर इस टैक्स को हटा देना चाहिए और जो प्रधानमंत्री ने देश को आश्वासन दिया था कि हम लोगों को शहर की तरफ नहीं जाने देंगे तो इसलिए आप इसको हटा दें जिससे कि लोग शहर में न आएं देहात में ही रहें।

महोदय, वित्त मंत्री ने एक बात कही है कि यह घाटे का बजट केवल 6 हजार करोड़ का ही है। मेरा कहना यह है कि जब आपको हर साल घाटे का ही बजट पेश करना है, नफे का बजट पेश नहीं करना है तो फिर 6 हजार करोड़ का ही क्यों करते हैं। देश में बहुत बड़े-बड़े सार्वजनिक क्षेत्र हैं जो कि रूपए

के अभाव में बंद हो रहे हैं। कोलार का गोल्ड मांइस है जिसमें 36 हजार मजदूर काम करते हैं वे रूपए के अभाव में बंद होने वाला है और बर्नपुर का इस्को है, जिसमें 26 हजार मजदूर काम करते हैं वह भी रूपए के अभाव में बंद हो रहा है। अगर आपको घाटा ही पेश करना है तो और कर दीजिए लेकिन जो लोग बेकार होने वाले हैं, जो नौकरी छोड़ने वाले हैं आप कम से कम उनको तो काम दीजिए लेकिन मैं जानता हूं कि सरकार यह काम नहीं करने जा रही है। यह सरकार अगर घाटे का बजट भी पेश करेगी तो मजदूरों के पक्ष के लिए नहीं, व्यापारियों के पक्ष के लिए पेश करना चाहती है। अगर गरीब पक्ष की सरकार होती तो घाटे का बजट पेश करती लेकिन कोलार गोल्ड मांइस जो बंद होने वाली है उसे चालू करने का इंतजाम करती। ऐसे ही और जो कई कारखाने बंद होने वाले हैं उनके लिए भी सरकार क्या करती हैं। सरकार विदेश से खाद मंगाने के लिए तैयार है, चाहे कितना ही घाटा हो या मुनाफा हो। हमारे देश में जो खाद की फैक्ट्री बंद है, जो बरौनी का खाद का कारखाना है वहां मजदूरो को बिठा कर पैसा दिया जाता है लेकिन फैक्ट्री चलाने के लिए पैसा नहीं दिया जाता है। इसलिए मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि आप देश के प्रति नीयत साफ रखिए। विदेश आपके काम नहीं आएगा, अगर इस देश के लोग मजबूत रहेंगे तो वे सब के साथ मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन अगर विदेश मजबूत रहेगा तो आपको गुलाम बना सकता है, गुलामी से हटा नहीं सकता है।

इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां लोग बेकार होने वाले हैं, बड़ी से बड़ी मुसीबत उठाकर भी आप उनकी रक्षा कीजिए। भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्रों का विकास किया, जवाहर लाल जी का कहना था कि सार्वजनिक क्षेत्र हमारी रीढ़ है। हमारी रीढ़ मजबूत होगी तो हम मजबूत होंगे, हमारा देश मजबूत होगा। सार्वजनिक क्षेत्र खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। आज जो अपने आपको असली कांग्रेसी कहते हैं, वहीं इंदिरा जी और नेहरू जी के सिद्धांतों के खिलाफ काम कर रहे हैं। यह बजट नेहरू और इंदिरा जी के सिद्धांतो का बजट नही है, यदि इंदिरा जी या नेहरू जी के समय में बजट प्रस्तुत किया गया होता तो उसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इतनी छूट न दी गई होती। तमाम अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इस बजट के बाद विदेशी कंपनियां बहुतायत से इस देश में आएंगी और देश को लूट कर बरबाद कर देगी, एक नहीं अनेक लोगों द्वारा यह बात कही गई हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है।

सरकार कहती है कि खेलों में हमें प्रगति करनी है, दुनिया में कंपीटीशन में आना है, लेकिन खेल मद में 1994-95 के बजट में 5.98 करोड़ की कटौती की गई है। इस तरह से कैसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

इसी तरह से कृषि में बजट में अधिक प्रावधान दिखाया गया है, लेकिन सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मद में कटौती कर दी गई है। बाढ़ नियंत्रण के लिए 1993-94 में 275, संशोधित 280 करोड़ रूपया रखा गया था, लेकिन अब 261 करोड़ रूपया रखा गया है। इस तरह से इस मद में 19 करोड़ रूपए की कटौती की गई है। इस तरह से बाढ़ से गरीबों की रक्षा कैसे होगी और सिंचाई में कटौती करेंगे तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा। अभी तो सिंचाई के क्षेत्र में मेरे ही क्षेत्र में पच्चीसों करोड़ रूपए की आवश्यकता है। यदि सोन नहर को पक्का बना दिया जाए तो इससे 30 लाख एकड़ क्षेत्र सिंचित होगा, लेकिन इस बारे में जब भी भारत सरकार से कहते हैं तो कह दिया जाता है कि खजाने में पैसा नहीं हैं, लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बुलाने के लिए आपके पास कुबेर का भंडार है।

इसलिए मेरा कहना है कि यदि आप उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो सिंचाई के मद में कटौती मत कीजिए और सोन नहर, गंडक नहर, कोसी नहर और मलयी नहर परियोजनाओं को बनाने और पूरा करने का

प्रावधान करिए। सिंचाई नहीं बढ़ेगी तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा और हम मजबूत नहीं हो सकेंगे। आप भले ही कहें कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बुलाकर देश को मजबूत कर लेंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी यह धारणा गलत है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जिसमें 70 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर करती है। यदि सिंचाई का इंतजाम नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा, बेरोजगारी दूर नहीं होगी। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि सिंचाई के लिए किए गए प्रावधान को दुगना कर देना चाहिए।

सभापति महोदय, सरकार हरिजन कल्याण का बहुत ढिंढोरा पीटती है, लेकिन आप देखिए कि गांव के गरीब हरिजन जो जूता बनाने का काम करते हैं, उनको भी नहीं छोड़ा गया है और जूते पर भी टैक्स लगा दिया गया है। इस सरकार की हालत इतनी खराब हो गई है। जूता बनाने वाले हरिजन गरीब लोग गरीबी की रेखा के नीचे के स्तर का जीवन-यापन करते हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग अपना काम करके अपनी जिंदगी का गुजर-बसर करतें हैं। आप हरिजनों की मदद करने का ढिंढोरा पिटते हैं तो इस टैक्स को वापिस ले लीजिए और बहुराष्ट्रीय कंपनियां जितनी लगानी है लगा लीजिए। आपने कहा कि हरिजनों को पढ़ाने के लिए जोर लगा रहे हैं। अनुसूचित जाति विकास निगम को मिलने वाली राशि पिछले 20 वर्ष से अस्थिर है और एक चौथाई की कटौती उस पर की गई है और इस मद में सिर्फ पांच लाख रूपए रखे गये हैं। हरिजन भाईयों को शिक्षा के लिए दी जाने वाली मदद में कटौती करेंगे तो किसको पढ़ायेंगे? मैं यह कहना चाहूंगा कि इस मद में जो सहायता दी जाती थी उसको चालू रखें, उसे कम करने की कोशिश नहीं करे। भारत सरकार के द्वारा कहा जाता है कि मंहगाई पर रोक लगा देंगे। जब बजट पेश होता है तो सवाई या डेढ़ा मंहगाई बढ़ जाती है चाहे लाख वित्त मंत्री जी कहें कि हम रोक लगा देंगे तो मैं नहीं समझता कि मंहगाई पर रोक लगी है। 1991, 92, 93 और 94 में बजट पेश हुआ तो मंहगाई बढ़ती जा रही है। इस बार मंहगाई सुरसा की तरह बढ़ती जा रही है क्योंकि इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। पहले बजट पेश होने के बाद बढ़ती है लेकिन अब बजट पेश होने से पहले ही बढ़ी है। जैसे बजट पेश होने से पहले ही रसोई गैस, पेट्रोल-डीजल, गेंहू, चावल आदि चीजों के दाम बढ़ गए हैं तो दूसरा बजट भारत सरकार ने पेश किया है। इसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर भी दाम बढ़ने वाले हैं। आपने कहा कि उत्पादन बढ़ा दिया है लेकिन कहां बढ़ाया है जबकि मंहगाई बढ़ती जा रही है। डिमांड और सप्लाई का नियम है कि जब पूर्ति अधिक रहती है तो दाम कम रहता है। आप कहते है कि इतना अन्न भंडार है जो खत्म होने वाला नहीं है तो फिर मंहगाई पर रोक लगाई जानी चाहिए। बेकार नौजवानों को काम देने का बजट में प्रावधान नहीं है, अगर है तो बहुत असंतोषजनक है। आप पबलिक सैक्टर को बंद करके प्राईविट सैक्टर को शुरू कर रहे हैं। सरकार की कोई योजना नही है तो कितने करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में छह करोड़ नौजवान बेकार हैं। कोई चरवाहा जैसे लोग नहीं है बल्कि बी.ए. एम ए. या तमाम तरह के इंजीनियर्स हैं जो घर में बैठे हुए हैं। सरकार के पास कोई जगह नहीं है उनको काम देने की तो कम से कम बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम देने का वादा कीजिए। आप प्रधान मंत्री से अनाउंस कराएं की एक साल में एक करोड़ बेकार नौजवानों को काम देंगे।

लेकिन मैं समझता हूं कि भारत सरकार यह काम करने वाली नही है। क्योंकि उसको लगता है कि कहीं गरीब आदमी खुशहाल न हो जाये और फिर उसकी मदद न करे। भागने से आपका काम नहीं चलेगा। राज करना है और राज चलाना है तो बेकार लोगों को काम देना होगा। अगर ऐसा नही करोगे तो बेकार नौजवान आपको बैठने नहीं देगा।

सरकार गोबर विदेश से मंगा रही है। कहती है कि यहां कमी हो गई है। लेकिन पशुपालन के लिए अपने बजट में राशि का प्रावधान बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। अगर ऐसा करे तो सरकार जितना चाहे गोबर यहीं से ले सकती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 358 करोड़ रूपये पिछले साल खर्च किये गये थे

और इस साल उसको घटाकर 325 करोड़ रूपये कर दिया गया है। आप यहां पर पशुपालकों को मदद नहीं देते है और बाहर से गोबर मंगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो काम आप विदेश से करना चाहते हैं, वह काम यहां के पशुपालकों की मदद करके यहीं पर हो सकता है और हमें गोबर का आयात नहीं करना पड़ेगा।

यहां पर गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 50 प्रतिशत है। जिनके पास घर नहीं है। एक ही छोटे से कमरे में सारे लोग रहते हैं। आपने सीलिंग एक्ट बनाया, लेकिन देश के पैमाने पर वह लागू नही किया। अगर जहां पर लागू किया भी है तो अधूरा लागू किया है। यदि वास्तव में लागू किया गया है। तो वह बिहार में, बंगाल में और त्रिपुरा में लागू हुआ है। बिहार में पचास हजार एकड़ जमीन पर गरीब लोगों को कब्जा दिलाया गया और मुख्य मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार उनकी मदद करेगी। जमींदारों पर तो गोली चल सकती है, लेकिन गरीबों पर और मजदूरों पर अगर वे कब्जा करेंगे गोली नहीं चलाई जायेगी। जहां कांग्रेस की हुकूमत है वहां पर सीलिंग एक्ट लागू नही हुआ है। इसका नतीजा यह हुआ कि गरीबों को जमीन नहीं मिल पाई है। सीलिंग एक्ट केवल देहातों में ही लागू नहीं होना चाहिए, यह शहरों में भी लागू करना पड़ेगा। आज शहरों में एक-एक व्यक्ति के पास कई मकान और दुकानें हैं। देहात से जो गरीब आदमी वहां नौकरी के लिए आता है और एक हजार रूपये तनख्वाह पाता है वह फुटपाथ पर सोता है। दिल्ली में ऐसे बड़े लोगों की कमी नहीं है जिनके मकानों में रहने वाला कोई नहीं है, लेकिन गांव का आदमी फुटपाथ पर सोता है। आपको यह व्यवस्था बदलनी होगी। जैसे 1979 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने को बदला था। अगर नहीं बदलेंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि आपके सामने बैठने वाले "जै श्रीराम" कहने वाले है तो कहते है कि आपको इधर नहीं बैठने देगें। हम भी पीछे नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि आपको हटाकर हम बैठ जायें। जिस दिन लाल झंडे का राज होगा, उस दिन यह सब हो जायेगा। हम भी परिश्रम करते हैं। इसलिए गरीब के पक्ष में काम करिये और शहरों में भी सीलिंग एक्ट लागू करें। जिससे गरीबों को उनका हक मिले।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का विरोध करता हूं, क्योंकि यह पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाला बजट है और विदेशी कम्पनीज को मालामाल करने वाला बजट है।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : सभापति महोदया, बजट न केवल आय व्यय का हिसाब करने वाला होता है, बल्कि सरकार की विभिन्न विकास नीतियों और वास्तविक नीति का दर्पण होता है। मैं आरम्भ में इतना ही कहना चाहूंगा कि यह बजट अंतर्राष्ट्रीय तथा देश की परिस्थिति और देश की आवश्यकता और हितों को ध्यान में रख कर औद्योगिक विकास का दरवाजा खोलने वाला बजट है। डा. मनमोहन सिंह ने तीन बजटों के द्वारा आवश्यक वातावरण तैयार करके कर ढांचों में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। इससे स्वाभाविक है कि इतना बड़ा काम करने के निर्णय से कुछ अन्य क्षेत्रों को नुकसान भी पहुंच सकता है।

इस पहलू की बारीकियों पर वित्तमंत्री जी गंभीरता से विचार करेंगे। डा. मनमोहन सिंह ने कर ढांचे के चार प्रमुख स्तम्भों- प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क की सीमा दरो में न केवल अनुकूल परिवर्तन किया है बल्कि बहुत चिन्तन करके सरलीकरण किया है। निस्संदिह टैक्स इवेजन, ब्लैक मार्किटींग के कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बजट के 6 मुख्य मुद्दे हैं। 1994-95 के बजट में कुल मिलाकर 6 हजार करोड़ रूपये का घाटा है। जब पिछला बजट पेश किया गया था तो उसमें जो घाटे का अनुमान लगाया गया था, इस बार इससे ज्यादा हो रहा है। क्या इस बार भी जो 6 हजार करोड़ का घाटा है, उससे बढ़ जायेगा ? दूसरा सरकार अपने खर्च में कमी लाने का प्रयत्न कर रही है या नहीं कर पा रही है? आम नागरिकों में ऐसी धारणा है कि जब परिवार का खर्च बढ़ता है तब खर्च को रोकने के लिए हर किस्म का प्रयत्न किया जाता है लेकिन सरकार के अनावश्यक खर्चों में कमी करने का कोई

संकेत नहीं मिल रहा है। उदाहरण के लिये न केवल सरकार के ठाठ-बाठ में कमी हुई है बल्कि 327 छोटी और मध्यम दर्जे की परियोजनाओं में अरबों रूपये खर्च करने के बाद भी अधूरी पड़ी हुई हैं। सरकार के पास सोचने के लिये फुर्सत नहीं कि इन योजनाओं को पूरा करना है या नहीं ? इस लापरवाही के कारण सरकार को 50-60 करोड़ रूपये का अनावश्यक खर्चा करना पड़ रहा है। और अब तो परियोजना को पूरा करने के लिये कई गुणा अधिक खर्च करना पड़ेगा।

दूसरी बात यह है कि प्रतिवर्ष सरकार के विदेशी ऋण पर ब्याज बढ़ता जा रहा है तो आज 46 हजार करोड़ हो गया है। सवाल उठता है कि यह सब कहां से आयेगा ? इसके कारण हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था पर दूरगामी परिणाम होंगे।

तीसरा मुद्दा यह है कि सरकार ने औद्योगिक विकास का द्वार खोला है जो आवश्यक है। कर-ढांचे में आवश्यक परिवर्तन किया है लेकिन भारत के उद्यमियों के पास धन कहां से आयेगा ? वे बैंको से कर्जा लेकर काम करते हैं लेकिन भारी ब्याज देना पड़ता है। माननीय वित्त मंत्री को इस पर चिन्तन करना चाहिए। हमारे देश में ब्याज की दर 14 से 16 प्रतिशत है जबकि विदेशों में 4-6 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है इतने अधिक ब्याज दर के चलते हमारे देश के उद्यमी विदेशी उद्यमियों के साथ भाव के मामले में कैसे मुकाबला कर सकते हैं ? इसलिये जब तक ब्याज दर कम नहीं होगी, उद्योग विकास में बाधा रहेगी। गांव के किसानों को तो 14 प्रतिशत दर पर भी ऋण नहीं मिलता है।

चौथा मुद्दा यह है कि मैं मानता हूं कि उद्योगों को बढ़ावा देने से अधिक लोगों को अधिक काम नहीं मिलेगा या रोजगार देने में बढ़ोत्तरी नहीं होगी। देश के युवक समझने लगे हैं कि सरकारी, अर्द्ध सरकारी दफ्तर क्यों न हों, सब को काम नहीं मिल रहा है। दुनिया के देशों की तरह ही हमारे देश के युवक भी खेती के काम में इच्छुक नहीं हैं। करोड़ो युवक बाध्य होकर खेतों में काम कर रहे हैं। इससे उद्योगों का विकास होगा और इससे देश को करोड़ो युवकों को काम मिल सकता है। मैं इतना बताना चाहता हूं कि केवल उद्योग के विकास से ही देश का सर्वागीण विकास हो सकता है।

खेती और उद्योगों में इतना पारस्परिक संबंध है कि अकेला रह कर कोई भी विकास नहीं कर सकता। एक दूसरे के विकास से ही दोनों क्षेत्रों में विकास हो सकता है। जैसे उद्योग बिना कच्चे माल के विकसित नहीं हो सकता उसी तरह कृषि का विकास बिना सिंचाई के नहीं हो सकता। अब आवश्यक हो गया है कि ब्रहमपुत्र नदी को गंगा नदी से जोड़ते हुए कावेरी नदी और गोदावरी नदी से जोड़ा जाये। इस ग्रांड कैनाल की योजना को अमल में लाये बिना हमारे देश के खेतों को अधिक पानी नहीं मिल सकता। यहां एकदम सवाल उठेगा कि इसके लिये पैसा कहां से आये। हमारे देश में कई योजनाएं बिना धन के अभी भी अधूरी पड़ी हैं। मैं चाहता हूं कि संसद सदस्य जागें और ऐसी अंडगेबाजी को दूर करें। हमें अविलम्ब इस ग्रांड कैनाल की योजना को कार्यान्वित करने का निर्णय लेना चाहिये।

[अनुवाद]

जहां चाह वहां राह

[हिन्दी]

हमने देश में अभी हाल ही में बैंकों की सहायता से हजारों करोड़ रूपये का गोलमाल होते हुए देखा है और हमने बैंकों को उनकी गलतियों से हो रहे दिवालियेपन को छिपाने के लिए पिछले बजट में 5700 करोड़ रूपये की व्यवस्था की थी और इस बार के बजट में भी 5-6 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। क्या हम आशा करें कि वित्त मंत्री जी बैंको को इस तरह आगामी बजट में 6 हजार करोड़ रूपये देने

की व्यवस्था करने के स्थान पर पहली बार ग्रांड कैनाल के लिए कम से कम 5 हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था अवश्य करेंगे, चाहे वित्त मंत्री कोई भी हो। इस योजना को तेजी से 10 वर्षों में पूरा किया जा सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसे हम कह देते है कि उद्योगों के लिए एक लाख करोड़ रूपये हमें मिल जायेंगे लेकिन कभी ऐसा नहीं कहते कि सिंचाई के लिए भी बाहर से यहां फौरेन इंवैस्टमेंट लाया जा सकता है।

बजट में कृषि के नये क्षेत्र - फल और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये विशेष व्यवस्था की गयी है। इस क्षेत्र में उत्पादन बढ़ने से ही देश और विदेश में भी व्यापार के नये क्षेत्र खुलेंगे जिसमें लाखों नवयुवकों को रोजगार मिलेगा।

पांचवां मुद्दा यह है कि वित्त मंत्री ने इस बजट में उद्योगो के विकास के लिये अनेक क्रांतिकारी कदम उठाकर सही काम किया है। इतने बड़े क्रांतिकारी कदम उठाने से कुछ छोटे उद्योगों को नुकसान पहुंचने की बात सही है। मुझे पूरा विश्वास है कि वित्त मंत्री का उद्देश्य किसी भी तरह से उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं हो सकता। ध्यान रखने की बात यह है कि हमारे देश के छोटे उद्योगों के मालिक कम धन वाले लोग है और गरीब लोग करोड़ो की संख्या में उनमें काम कर रहे हैं तथा अपने उत्पादन से वे देश को 38 प्रतिशत मुद्रा कमा कर दे रहे है।

छठा मुद्दा यह है कि सन् 1993-94 के बजट में फिस्कल डैफिसिट यानी राजकोषीय घाटा 36,959 करोड़ रूपये तक होने का अनुमान था जो अब बढ़कर 58,551 करोड़ रूपये हो गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि कुल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत 4.5 से बढ़कर 7.3 हो गया है जो बहुत चिन्ता का विषय है। वित्त मंत्री ने स्वयं अपने भाषण में इसे स्वीकार किया है। इन समस्याओं का हल किया जा सकता है और वित्त मंत्री औद्योगिक उत्पादन में 3-4 प्रतिशत की वृद्धि के बजाये 7-8 प्रतिशत की वृद्धि के उपाय अपनाये और देश को खाद्य पदार्थो के मामले में पुन: विदेशी सहायता पर निर्भर न रहने हेतु कृषि उत्पादन में 10-12 प्रतिशत की वृद्धि करने के लिये आवश्यक कदम उठायें। जब तक यह नहीं होगा, तब तक हमारे देश का विकास बहुत मुश्किल होगा।

सभापति महोदया, वित्त मंत्री के सामने दो विकल्प है जिनको स्वयं उन्होंने अपने भाषण में कहा है। एक तो औद्योगिक उत्पादन के वर्तमान दरें को ज्यों का त्यों रहने दिया जाए और रूस के विघटन से हम सबक न लें। उन्होंने यह बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी दी है और दूसरा विकल्प यह है कि आधुनिक विज्ञान और तकनीकी ज्ञान की सहायता से उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए और दुनिया के बाजारों की दौड़ से हम आगे बढें। मेरा निश्चित मत यह है कि डा. मनमोहन सिंह ने दूसरे रास्ते पर चल कर एक खतरा उठाया है लेकिन उनका यह कदम सही दिशा में है।

अब इस बजट में ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण नियोजन, महिला एवं बाल विकास, अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जातियों के विकास के लिए अधिक धन की व्यवस्था की गई है। वर्तमान पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास के लिए 30 हजार करोड़ रूपए रखे गए है, जो अन्य पंचवर्षीय योजनाओं से कहीं अधिक है। यह एक दम सही निर्णय और ठीक कदम है, लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि इसमें रखी गई धनराशि जरूरतमंद लोगों के पास कितनी पहुंचती है।

यह भी सही है कि ग्रामीण क्षेत्र के युवक अपना नया धंधा खोलने के लिए बैंकों से धन निकालने की कला को नहीं जानते हैं और वे नहीं जानते है कि धंधे में पैसा कैसे लगाया जाए। इसका कारण क्या है? मैं इसका एक ही कारण समझता हूं कि उनकी पढ़ाई का स्तर नीचा है। गांवों में पढ़ाई की जितनी उपेक्षा हुई है वह किसी से छिपी नहीं है। गांवों में पढ़ाई का स्तर एकदम गिरा हुआ है। देश के विकास में वे कैसे सहयोगी बन सकते हैं यही एक मुख्य कारण है। गांव और शहर के बीच खाई बढ़ती जा रही है। गांव के

लोग देश की मुख्य धारा में शामिल होने के बहुत इच्छुक हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है। इसलिए गांव के 60 प्रतिशत लोगों को विकास में शामिल किए बिना देश का विकास कैसे होगा?

मेरा सुझाव है कि देश के 5 लाख 76 हजार गांवों के स्कूलों में ऐसे ट्रेड शिक्षक रखे जाएं जो गांवों में रहे और गांवों में पढ़ाई को ही अपना मुख्य धंधा मानें। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि शिक्षा राज्य सरकारों का विषय है और उसी का उत्तरदायित्व है। इसलिए मेरा सुझाव है कि या तो केन्द्रीय सरकार देश की शिक्षा व्यवस्था को अपने अधिकार में ले या केन्द्र और राज्य सरकारें मिलकर विभिन्न राज्यों में मिला-जुला बोर्ड बनाएं और शिक्षा की समुचित व्यवस्था यानी आर्थिक और प्रशासनिक भार उस को सौंपें। ग्रामों की अर्थव्यवस्था में शिक्षा में ही तकनीकी ज्ञान कराने की भी व्यवस्था हो। इसके लिए मेरा सुझाव है कि प्रत्येक मिडिल और हाइस्कूल में एक लेथ मशीन पर प्रशिक्षण दिया जाये ताकि शिक्षा के साथ-साथ बच्चों को तकनीकी ज्ञान भी प्राप्त हो सके और हमारी शिक्षा जॉब ऑरिएंटेड हो सके। जब तक हम जॉब ऑरिएंटेड शिक्षा नहीं देंगे तब तक इस देश के गांवों का विकास होने वाला नहीं है।

महोदया, जब तक गांवों में स्कूल जाने वाली लड़की की हाईस्कूल तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा नहीं देंगे तब तक गांवों का विकास नहीं हो सकता है। मेरा तो यह सुझाव है कि देश के शिक्षकों और डाक्टरों की संख्या का 50% स्थान महिलाओं को देना अनिवार्य होना चाहिए। इससे समाज को और देश को कितना लाभ होगा, उसकी अधिकांश लोग कल्पना भी नहीं सकते हैं। जहां महिलाएं ज्यादा शिक्षित हो जाएंगी वहां देश की सबसे बड़ी समस्या, यानी बढ़ती हुई आबादी की समस्या स्वयं हल हो जायेगी।

उदाहरण के लिए आप केरल में देख लीजिए। वहां सब महिलाएं शिक्षित हैं। वहां पर आबादी की संख्या घट रही है। अभी जो टैक्नोलीजी व्यवसायिक शिक्षा में खर्च की जा रही है, वह बिल्कुल बेकार है। उससे किसी को लाभ नहीं है। उस टैक्नोलीजी को इस शिक्षा में लगाएं। इस तरह से परिवार नियोजन के लिए रखे गए अधिक धन को इसमें लगाइए।

अब सवाल यह आता है कि देश में रीजनल इमबैलेंसेस कितना बढ़ता जा रहा है। बजट में प्रादेशिक असमानताओं को दूर करने के लिए कहीं कोई चर्चा नहीं की गई है। मेरा सुझाव है कृषि के विकास के लिए हर 10 लाख की आबादी के क्षेत्र में कम से कम एक कृषि प्रदर्शन फार्म हो और ऐग्रो-इंडस्ट्रीज ट्रेनिंग-कम-डैवलपमैंट फार्म हो।

स्कूलों में कम्प्यूटर ट्रैनिंग की व्यवस्था हो। जिन युवकों को नए उद्योग में लगाया जाए, उनको पहले ट्रैनिंग दी जाए। कानून-व्यवस्था में हिन्दी-भाषी राज्य सबसे अधिक पिछड़े हुए है। इसके कई कारण है जिनकी चर्चा मैं अभी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वह विवाद का विषय बन जाएगा। हिन्दी क्षेत्रों में विकास के लिए अभी तक आवश्यक इनफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है। रेल, सड़क, टेलीफोन और अच्छे प्रशासन की कमी है।

सरकार बार-बार कहती है कि वह आदिवासी क्षेत्रों के विकास में बहुत ध्यान देती है। आप जानते है कि मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और वहां आदिवासियों की संख्या भी सबसे अधिक है। देश के सबसे बड़े आदिवासी जिले बस्तर के मुख्य कार्यालय जगतपुर को रेल से नहीं जोड़ा गया है। इसी तरह से मध्य प्रदेश के दूसरे आदिवासी जिले सरगुजा के मुख्य कार्यालय को भी रेल से नहीं जोड़ा गया है जबकि इन दोनों जिलों में लोहे और कोयले के सबसे अधिक भंडार है। उन क्षेत्रों में अनेक धातुओं की खदानें है।

बिहार के बहुत से लोग कहते हैं कि शहर की आबादी तेजी से बढ़ रही है। इसके बहुत से कारण है। मेरा सुझाव है कि सरकार प्रत्येक जिले में 200-500 एकड़ की जमीन पर सैटेलाइट टाउन बनाए। सड़कें,

स्कूल और अस्पताल की व्यवस्था हो और वही पर एग्रो-इंडस्ट्रीज की टैनिंग दी जाए, कम्प्यूटर ट्रेनिंग दी जाए।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : सभापति महोदया, सामान्य बजट पर चर्चा का प्रारंभ इस आकांक्षा को लिए करता हूं :

न कामये राज्यं
न स्वर्ग न पुनर्भवम्
कामये दु:खतप्तानाम,
प्राणिनामार्तनाशनम्।

चाह नहीं मुझे राज मिले
या स्वर्ग लोक को पा जाऊं,
या पुनर्जन्म लेकर आऊं,
मेरी बस अभिलाष यही,
दु:ख से व्यथित जगत के,
कष्ट मिटाने काम आऊं,

ईशावास्यमिदं सर्वयत् किंच्च
जगत्यां जगत।

जहां देखता हूं वहीं तू ही तू है
जर्रे जर्रे में तेरी ही जुस्तजू है।

खालिक, खलक में; खलक में; खालिक;
सब घट रह्या समाई।

बजट पर हम यहां कर रहे है चर्चा आमदनी कम और ज्यादा ही खर्चा
अनाज महंगा शक्कर महंगी, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ जाये।
बजट के आने के पहले से महंगाई को दिया बढ़ाय।
कहे सरकार सुनो भई साधो, बजट से सब ही को राहत होई जाये।
अरे, ऐसी राहत मिली बजट में, लिये गरीब के वस्त्र उतराय।
हाल हुए हमारे कुछ ऐसे, जिसका वर्णन कहा न जाये।

अरे फूटे करम फकीर के भरी चिलम दुल जाये।
सौ दिन में महंगाई कम करने वालों के हो गये हैं पूरे दिन हजार,
किन्तु, जनता को दिया "वादों का सपना" वह अब तक नहीं हुआ साकार।

गरीब की रोजी--रोटी के लिये रोजगार नहीं है।
वादों से पेट भर जाये, ऐसे भी आसार नहीं है
लेकिन, असरदार नहीं है।

मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर,
लोग साथ आते गये कारवां बनता गया।
काश,
यदि ऐसा कुछ हुआ होता। अकेले ही चले होते मंजिल की तरफ।
और कारवां बना होता। जमीं हमारा होती, आसमां हमारा होता।
विदेशी के चले जाने के बाद स्वदेशी का आलम होता।
लोगों को रोजगार और भरा पूरा कारोबार होता।
आत्मनिर्भरता का सपना भी साकार हुआ होता।

नौजवानों में बेबसी नहीं होती बुलंदी को पार किया होता।
विदेशी कर्ज से दबी सरकार नहीं होती यदि,
स्वतंत्रता स्वावलम्बन से हमारा सरोकार होता।

अंकल, डंकल का प्रभाव न होता, वस्तुओं का अभाव न होता।
"गैट" गेट वे आफ इंडिया से अन्दर नहीं बाहर हुआ होता।
सरकार ने, 15 दिसम्बर 1993 को गैट करार स्वीकार किया।
गैट में अन्तर्निहित है डंकल प्रस्ताव।
कृषि के लिये आवश्यक बीज, बिजली और सिंचाई
सबसिडी अर्थात् अनुदान के अभाव में, कृषि लागत में आयेगी महंगाई।
सरकार का समर्थन मूल्य, नहीं कर पायेगा भरपाई।
इतना ही नहीं विदेशों से करना पड़ेगा देश के कृषि उत्पादन आवश्यकता का 3.3 प्रतिशत आयात।
जिसका भुगतान देश को करना पड़ेगा, अथवा विदेशी कर्ज बढ़ेगा।
अर्थात कर्ज लेकर भी करो आयात।

अब हम करे अपने किसान की बात।
देश के अधिकांश किसानों के पास कृषि भूमि नहीं पर्याप्त और रकबा
पीढ़ी दर पीढी कम होता ही जायेगा।
ऐसे में किसान क्या बेचेगा और क्या खायेगा?
सरकार का कहना है कि
देश का किसान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि उत्पाद का व्यापार करने जायेगा?
अर्थात उसके माल को कोई खरीदेगा और कोई, बेचने जायेगा।
अपनी बैलगाड़ी से ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका तो नहीं जायेगा।
अर्थात बिचौलिया जो भी होगा वही तो माल ले जायेगा।
यह सब "सदाव्रत" में तो नहीं होगा अपना-अपना मुनाफा हरेक लेगा।
मंहगी खेती करने के बाद मेरे देश के किसान को क्या मिलेगा?
बीजों का भी पेटेंट होगा, अर्थात किसान 'बीज' का व्यापार नहीं
कर सकेगा न आपसी समझ से बीजों का आदान-प्रदान करेगा।
इस प्रकार खेत और किसान पर विपरीत ही होगा 'डंकल' का प्रभाव।
गैट के डंकल से जुड़ा व्यापार "बौद्धिक संपदा का अधिकार"
अर्थात TRADE RELATED INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS - TRIPS
"ट्रिप्स" की ट्रिक्स कुछ इस प्रकार हमारे सारे उद्योग धंधे होंगे मंद,
फलेगा-फूलेगा विदेशी व्यापार। जब पेटेंट के दायरे में आयेगी दवाये
मूल्य होंगे अधिक जन सामान्य की पहुंच से बाहर होगा उपचार पेटेंट में
अब तक उत्पाद विधि आती डंकल के पेटेंट में आयेंगे उत्पाद।
जिसके होंगे बहुआयामी प्रभाव, दवाये बनाने, रसायन खाद्य सामग्री और
वस्त्र उद्योग पर होगा गैट का दबाव।
हमें 20 वर्ष पेटेंट में जीना है। G-7 की जी में जी-जी करना है।

माना कि तेरी दीद के, काबिल नहीं हूं मैं।
मेरा शौक तो देख, मेरा इन्तजार तो कर।
हालांकि किसी दीद के काबिल नहीं है तू, तेरे शौक के खातिर, हमें लाचार तो न कर।

यह देश विदेशी आक्रमण से, सदा हुआ आक्रांत।
हम अपने स्वभाव से सदा रहें हैं शांत।

अंग्रेज यहां आया था व्यापार के लिये,
व्यापार करते-करते ही सरकार बन गया।

अंग्रेजी हुकूमत से, बमुश्किल मिली निजात।
अब विदेशी कंपनियों की क्यों करे बात।

देश की आजादी की जब भी करता हूं बात,
याद मुझे आते हैं चन्द्रशेखर आजाद।

शहीदे वतन भगतसिंह सुखदेव और राजगुरू,
जंगे आजादी को जिन्होंने दिया सुरूर।

लाल-बाल-पाल से स्वतंत्रता सेनानी।
वीर सावरकार का सा नहीं कोई सानी।

सुभाष ने कहा - तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी की दे दूंगा सौगात।

गांधी ने देश को दी, सत्य अहिंसा की शिक्षा,
स्वदेशी स्वावलम्बन करें तो मांगे क्यों भिक्षा?

आजादी के महापुरूषों को, करते यदि हम याद।
आजादी के साथ ही, होते हम आबाद।

धरती पर पांव जमें तो कुछ बात बने,
हवा में चलने वालों की बुनियाद नहीं होती।

बुलन्द वादों के सहारे बुलन्दियां नहीं आती,
जमीं पर चलने वाले ही, बुलन्दिया आसान करते है?

बुलन्द वादों की बस्तियां, लेकर हम क्या करेंगे।
हमें हमारी जमीं दे दो आसमां लेकर क्या करेंगे।

4.00 म०प०

इस बजट से उद्योगों में आयेगी मंदी, उत्पादन होगा कम,
बेकारी होगी अधिक, गरीबी होगी ज्यादा।
ऐसे मे कैसे पूरा करोगे, गरीबी हटाने का वादा।
हां, ऐसा जरूर होगा, न मर्ज रहेगा और न ही मरीज।
गरीब के बिना, गरीबी कैसे रह पायेगी?
गरीब की याद में तड़प-तड़प कर मर जायेगी।

महंगाई- सरकार का कहना है, बजट के घाटे से महंगाई नहीं बढ़ेगी।
मैं पूछता हूं सरकार से, क्या अब तक महंगाई सरकार से पूछ-पूछ कर बढ़ती थी?
जो अब आगे नहीं बढ़ेगी।
अरे, महंगाई, महंगाई है, सरकार की चेरी नहीं है।

यह मूल्य सूचकांक, जिसे प्राइस इण्डैक्स भी कहते हैं, सन 1960 से इसकी गणना करने लगे और यह है कि बढ़ा तो बढ़ने ही लगा।

बढ़ते-बढ़ते इतना बढ़ गया कि सरकार का कद छोटा लगने लगा।
इसलिए, सरकार को आधार वर्ष बदलना पड़ा,
अब देखना यह है कि सरकार महंगाई से निजात दिलाती है अथवा
महंगाई, सरकार से निजात दिलाती है।
यह तो आने वाला वक्त ही बतायेगा कि कौन, किससे निजात पाता है।

घाटा बजट में हर साल बढ़ता ही गया,
ज्यों-ज्यों दवा की, मर्ज बढ़ता ही गया।

राजकोषीय घाटा 1980-81 से 8,299 करोड़ रूपया, पांच वर्ष बाद 1985-86 में 21,587 करोड़ रूपया, इसके पांच वर्ष बाद 1990-91 में 44,632 करोड़ रूपया और अब अनुमानित बजट 1994-95 में 54,915 करोड़ रूपया और राजस्व घाटा 1980-81 में 2,037 करोड़, पांच साल बाद 1985-86 में 5,889 करोड़, इसके पांच वर्ष बाद 1990-91 में 18,562 करोड़ और अब अनुमानित बजट में 32,727 करोड़। वास्तविकता की तुलना करें तो विगत वर्ष से होगा वर्ष 1993-94 में राजकोषीय घाटा 58,551 करोड़, जबकि अनुमानित में था 36,959 करोड़ रूपये से 21,592 करोड़ बढ़कर 58,551 करोड़ हो गया और इसी अनुपात में बढ़े तो वर्ष 1994-95 में बढ़ेगा, प्राय: 30,000 करोड़ और हो जायेगा 85,000 करोड़। अर्थात् देश को 1991 की जनगणना के आधार पर प्रत्येक पर 1000 रूपये का राजकोषीय घाटा। देश की जनसंख्या पर जब बराबर-बराबर बांटा।

देश के कुल खर्च में से गांव को बीस,

इस बीस का करो प्रतिशत पन्द्रह।

क्योंकि, दिल्ली से जब चलता है सौ, तो पहुंचता है पन्द्रह।

गांवों पर होने वाले व्यय में कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास,

इन तीनों को मिलाकर होता है बजट अनुमान।

सन् 1993 में 6940 करोड़ और वर्ष 1993 में 8934 करोड़।

हमारे पास कुल केन्द्रीय आयोजना का क्षेत्रवार जोड़।

सन् 1993-94 में 63,936 का 6940 करोड़ अर्थात् प्रतिशत 11.

सन् 1994-95 में 70,141 का 8934 करोड़ अर्थात् प्रतिशत 12.5.

इसका 15 प्रतिशत 1,339 करोड़, ग्रामीण आबादी में प्रत्येक को रूपये मिलेंगे 15 सलाना, इसमें कितना होगा विकास ?

जब आयात शुल्क होगा कम विदेशी कम्पनियों से,

देश का बाजार भर जायेगा तो अपना माल कहां जाएगा?

क्योंकि हमने लघु उद्योगों से उत्पादित माल पर लगा दिया है कर,

उद्योगों से उत्पादन होगा बंद, इस बजट में कर दिये है ऐसे प्रबंध।

आयुर्वेद-युनानी दवा, देशी इलाज अब हो गये हैं हवा।

इन पर भी लगाया है कर, जीना हो तो जी नहीं तो मर।

दवा और वो भी देशी, बात कर रहे हो कैसी-कैसी।

देश में देशी दवाएं दबी-दबी सी थी,

कर लगाने से पूरी तरह दब जायेगी और देसी दवाओं से हुई रिक्तता

विदेशी दवाओं से भरी जायेगी।

शिक्षा

गांवों में निरक्षरता का प्रतिशत पचपन से ज्यादा है,

गांवों का बचपन तो ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है।

शिक्षा के हालात कुछ ऐसे बने हैं,

गांवों का स्तर एक, नगर के अलग हैं।

क्योंकि गांव का पढ़कर करेगा भी तो क्या ?

पढ़ कर के ज्यादा से ज्यादा बनेगा भी तो क्या ?

शिक्षक और पटवारी।

शहर की शिक्षा को बनना है प्रशासनिक अधिकारी

और बनाना है नेता।

जो कहता, मेरा देश गांवों रहता।

पीने का पानी -

पीने का पानी का अभाव और समस्या ग्रस्त गांव है,

पीने के पानी का प्रबंध नही है, सरकारी गणना के आंकड़े सही नहीं है।

पीने के पानी को सर्वोच्च प्राथमिकता दो।

शीघ्र नगर गांवों की आवश्यकता पूरी करो।

ग्रामीण विकास -

गांवों में विकास शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा,

सड़क और समृद्धि के लिये करने होंगे सार्थक प्रयास।

इसके लिये विशेष उपाय सभी करने होंगे,

तभी देश की प्रगति को नया आयाम मिलेगा।

आजादी की रोशनी, नया पैगाम मिलेगा।

रेलवे बजट में उपेक्षित रहा मध्य प्रदेश

सर्वाधिक क्षेत्रफल का विस्तार, किन्तु प्रगति और विकास बिजली

और सिंचाई क्षमता, सिंचित कृषि क्षेत्र का रकबा,

विकास हो सके सभी का, इसके लिये देना है प्राथमिकता

आवश्यक सहायता शीघ्र करें।

क्षिप्रा शुद्धिकरण,

नर्मदा, क्षिप्रा जोड़ा योजना,

एच.बी जे. पाइप लाइन से,

बिजली घर के लिये लिंकेज,

उज्जैन के विनोद-विमल मिल और मध्य प्रदेश के बंद कपड़ा मिलों को चालू करो।

जिससे मिले मजदूरों को रोजगार और कपड़ा उद्योग को पुनर्जीवन का आधार

बजट में किये गये प्रावधानों से छोटे उद्योगों के अस्तित्व को संकट होगा।

सूती-कृत्रिम रेशों से निर्मित कपड़ा, ऊन से निर्मित वस्तुएं,

छोटे स्टील कारखाने, कम क्षमता वाले सीमेंट उद्योग

देशी-यूनानी औषधि निर्माता प्रभावित होंगे।

इसलिये मैं वित्त मंत्री से करती हूं अनुरोध

हटाये स्वदेशी के मार्ग में आयें जितने अवरोध।

करें ऐसे कारगर उपाय विदेशी कम्पनियों का

होने पाये न दुष्प्रभाव।

खुदी को कर बुलंद इतना कि
हर तकदीर से पहले
खुदा बंदे से पूछे,
बता तेरी रज़ा क्या है।

ॐ विश्वामिदेव सवितर्दुरितानि परासुव
यद्भद्रं-तन्नासुव"
सर्वशक्तिमान।
सबके कष्ट दूर कर, सुखी समुध्द बनाये।

माननीय सभापति !

सामान्य बजट की चर्चा में,
प्रतिवाद के लिये अवसर देने के लिये
आपके और सदन के प्रति
व्यक्त करता हूं हृदय से धन्यवाद।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : सभापति महोदय, मुझे इस सदन में पांच बजट देखने का मौका मिला, वर्ष, 90, 91, 92, 93 और यह 94 का बजट देख रहा हूं। 1989 में जब मैं सांसद बन कर आया था, उस समय 89-90 में जो बजट प्रस्तुत किया गया था और हमारी ही सरकार थी, उस समय जो बजट आया,. ......(व्यवधान)........

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : आप किस पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं ?....(व्यवधान)...

श्री सूर्य नारायण यादव : मैं इस समय कांग्रेस दल की तरफ से बोल रहा हूं और आप डिस्टर्ब न करें तो अच्छा होगा।

सभापति महोदय, 1990 का बजट जब वी पी सिंह जी के समय में श्री मधु दण्डवते द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो उसमें कहा गया कि देश का खजाना खाली है। 1991 में जब चन्द्रशेखर जी के समय में बजट प्रस्तुत किया गया तब तो यह कहा गया कि देश का खजाना इतना खाली है कि उनको देश का सोना बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। फिर मध्यावधि चुनाव आ गए और पी वी नरसिंहराव की सरकार आई, जिसमें मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री बने।...........(व्यवधान)...............

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ इनफरमेशन है। टी. वी. पर इस समय दिखाया जा रहा है सूर्य नारायण यादव, सहरसा (बिहार), लेकिन पार्टी का नाम नहीं दिया गया है। टी. वी. में पार्टी का नाम भी करवा दिया जाए।..........(व्यवधान).........

श्री सूर्य नारायण यादव : सभापति महोदय, सहरसा भी हिन्दुस्तान का ही एक जिला है। इनको पता है कि मेरी बात ये बरदाश्त नहीं कर पाएंगे, जो मैं आगे उगलने जा रहा हूं, इसलिए ये पहले से ही तैयार हो रहे हैं।

सभापति महोदय, पी वी नरसिंह राव की सरकार में जो तीन बजट प्रस्तुत किए गए और यह चौथा बजट प्रस्तुत किया गया, इनमें सुधार की प्रक्रिया लगातार चलती रही है। पी वी नरसिंह राव जी ने यह नहीं कहा कि देश का खजाना खाली है, गांवो का विकास नहीं होगा, बेरोजगारों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा या शहर और गांव में कोई भेदभाव किया जायेगा। इस बजट से मंहगाई नहीं बढ़ी है, बल्कि मंहगाई बढ़ने का सिलसिला जो वर्ष 1990 से शुरू हुआ, वही सिलसिला अभी तक चल रहा है।

आज वामपंथी दलों के साथी कहते हैं कि श्रमिकों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, छंटनी हो रही है, "डंकल" आ गया है। डंकल को यदि आप लोग मजाक मजाक न बनाएं तो अच्छा होगा।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : डंकल आया नही है, आप डंकल के पास जाकर फंसे है।

श्री सूर्य नारायण यादव : हम डंकल में फंसे नहीं हैं, मैं स्वयं किसान हूं और उन गांव के लोगों की, किसानों की स्थिति में डंकल के माध्यम से होने वाले सुधार को देखना चाहता हूं। किसान को डंकल के नाम पर गुमराह न करें तो अच्छा होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आज से 15 वर्ष पहले जब रूस से मेक्सिको बीज आया था तक क्या हिन्दुस्तान में गेंहू की खेती नहीं की जाती थी? जब यह बीज रूस से आया, उसका डेमांस्ट्रेशन किया गया, गांवों में उन्नत बीज पहुंचा और उसकी खेती की गई।......(व्यवधान)........ कहीं से भी आया था, लेकिन विदेश से आया था।......(व्यवधान).........

आप देश को बचाओ। वह बीज है जिसने देश को अनाज के मायने में आत्म-निर्भर करने का काम किया है। कहा जाता है कि किसान बीज नहीं बेच सकता। किसान एक बार बीज खेत में डालकर पैदा करता है और दुबारा उस बीज को डालता है तो ज्यादा पैदावार नहीं हो पाती है। एक एकड़ में ज्यादा पैदावार हो सके तो उस बीज की तलाश है। यह तलाश डंकल के माध्यम से होने वाली है इसलिए आप किसान को गुमराह करना बंद करे। कोयला और स्टील जैसे उद्योग करोड़ों के घाटे में चल रहे हैं, अगर यह देश कंपीटीशन की मार्किट में आता है तो उदार नीति के चलते क्या आपत्ति हो सकती हैं। बेकार नौजवानों को कहते है कि आई ए एस या आई पी एस के कंपीटीशन में बैठो तो यह कंपीटीशन उदार-उदार नीति से किया। जैसे-टाटा ट्रक बनाता है और उस ट्रक को चैलेंज किया जाता है कि हमारा मुकाबला करो, लेकिन संसार में कोई मुकाबला करने वाला नहीं है जबकि संसार में इसकी सप्लाई हो रही है। क्या आप उद्योग को कंपीटीशन की मार्किट में नहीं लाना चाहेंगे ? लेकिन कभी इससे नहीं भागना चाहिए। आप चाहे इस चेयर पर या उस चेयर पर बैठे। हमारे जैसा गरीब आदमी लोक सभा में चुनाव जीतकर आता है तो क्या आप सांसद या विधायक बनने से रोकना चाहते हो ? देश में परिवर्तन आते हैं।............(व्यवधान) मैं बंधुआ मजदूर नहीं हूं। मैं अपने विवेक से और हिम्मत से हूं.........(व्यवधान) जिस प्लेटफार्म से मैं सेवा कर सकता हूं तो उस प्लेटफार्म को लाईक करूंगा। मैं जनप्रतिनिधि हूं इसलिए जो मुझे लगता है वही सेवा करूंगा। 17 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है चाहे वाम पंथी हो या नेशनल मोर्चा हो, तो आप धन्य हो.........(व्यवधान) इसीलिए मैंने इस प्लेटफार्म को चुना है।.......(व्यवधान) हम अभी चुनाव के लिए तैयार है......(व्यवधान) हमको अभी बजट पर बोलना है। इनकी आलोचना हो रही है इसलिए इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है.... .....(व्यवधान)

कई सांसदों ने बजट की आलोचना की है, लेकिन इसमें गुण क्या है, उनकी प्रशंसा किसी ने नहीं की। मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या इस बजट में खामियां ही खामियां हैं ? अगर खामियां थी और हैं तो आपने क्या सुझाव देने का काम किया है कि इसको कैसे सुधारा जाये, कैसे ग्रामीण इलाकों में पैसा भेजा जाये? कोई सुझाव नहीं आया है। भूमि हदबंदी की बात चल रही है। वह जरूर होनी चाहिए। इससे अच्छा कोई दूसरा काम नही हो सकता। लेकिन क्या भूमि हदबंदी उड़ीसा में या बिहार में हुई है,

नहीं हुई है। बंगाल में हुई है, उसके लिए वहां की सरकार को धन्यवाद देता हूं। यह काम राज्य सरकार के करने का है। दिल्ली में जहां संघीय सरकार है, उसको करना है। जहां राज्य सरकारें है, क्या वहां के बजट घाटे के नहीं है? देश की आबादी बढ़ेगी, देश में रथ यात्रायें होंगी, देश में मस्जिद पर हमला होगा, देश में कश्मीर में और पंजाब में आतंकवाद होगा जिस पर अरबों-खरबों रूपया खर्च होगा तो इस बजट में उसकी भरपाई करने के लिए किसी के लिए भी कठिनाई होगी। उसके लिए इस मंच पर चाहें आप हों या नरसिंह रावजी हों, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। जिस परिस्थिति में देश चल रहा है उसमे आवश्यकता इस बात की है कि यहां जो भी सरकार अच्छा काम करे उसका बुलंदी से समर्थन करना चाहिए। अगर बुरा करे तो उसका यहां विरोध करना चाहिए। लेकिन अगर अच्छे काम का भी विरोध करेंगे तो देश की जनता को लाभ नहीं हो सकता है। मैं कहां कहता हूं कि भ्रष्टाचार नहीं है, सब जगह है। बजट के माध्यम से हर राज्य में पैसा जायेगा और वहां लूट हुआ करती है। हर राज्य में लूट हो रही हैं। जवाहर रोजगार जैसी सघन योजनाऐं चल रही है। बिहार सरकार उसके लिए पैसे की मांग करे और केन्द्र सरकार वहां पैसा भेजे तो उसका क्या हुआ, यह सभी जानते हैं। उस योजना में जिनमें हार्ड मेनुअल वर्क से काम हुआ, आज भी यह कहा जा रहा है कि उस पैसे का पूरा उपयोग नहीं हुआ, लूट हो रही है। उस लूट को रोकने का काम राज्य सरकार का है। अगर भ्रष्टाचार मिटाना है तो राज्य सरकार को सख्ती से काम लेना होगा और भारत सरकार को कहना होगा कि तुम भी ताकत दो और भारत सरकार ताकत देने का काम करे।

हमारे जार्ज साहब अति-समाजवादी नेता हैं। वह देश के ही नहीं विदेश के भी ज्ञाता हैं, उनका चिन्तन हैं। वे सुझाव भी देते हैं, लेकिन मैं जनता दल के साथियों से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके सुझावों को आप मानते है? अच्छे लोगों की पूछ नहीं होती, उनके सुझावों को नही माना जाता, अच्छे लोग बजट पेश करें तो उसको माने तो तैयार नहीं होते, तो कैसे काम चलेगा। जब आपका राज आयेगा तो आप पहले ही टूटकर खत्म हो जाओगे। सूर्य नारायण को क्या कहते हो, वह भी उसी का अंग है। जो बजट मनमोहन सिंह जी ने पेश किया हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे देश में जितने भी वित्त मंत्री आये है, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, एक अच्छा बजट उन्होंने पेश किया है। मैं कंवीस होकर कह रहा हूं कि यह बजट देश के ग्रामीण क्षेत्रों का उद्धार करेगा। मेरा वामपंथी साथियों से निवेदन है कि वे भी जरा नरमी बरतें, इसमें सहयोग दें ताकि इसको आगे ले जाकर कार्यरूप दिया जा सके।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं छह मूल कारणों से, जिनको मैं बहुत संक्षेप में सभा में रखना चाहता हूं, बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

पहला मुझे विश्वास है कि यह बजट मुद्रास्फीति के ठहराव का विधान है।

दूसरा, सबसे अधिक राजस्व घाटा इस बजट की सुस्पष्ट विशेषता है।

तीसरे, इस बजट से ऐसी कोई आशा नहीं दिखाई देती कि 1993-94 की राजस्व असफलता अगले वर्ष भी नहीं दोहराई जाएगी।

चौथे, यह बजट अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक की शर्तों को प्रभावकारी बनाने की एक रूपरेखा है और गैट समझौते की एक बाध्यता है।

पांचवे, हमारे देश के सत्ता वर्गों द्वारा इस बजट के माध्यम से हमारे समाज के कर्मकारों कृषकों तथा शोषित वर्ग के विरूद्ध एक संघर्ष की घोषणा कर दी गई है।

अन्त में, यह बजट उस आर्थिक दिशा के अनुसरण में नहीं तैयार किया गया है जो हमारे समाज में जनसामान्य के लिए मितव्ययता लाए तथा उसकी उन्नति में हो बल्कि इसका लक्ष्य तथा उद्देश्य हमारे समाज के एक बहुत ही निरर्थक वर्ग की उपभोक्ता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है और यदि आप मुझे यह कहने की अनुमति दें तो हमारी कुल जनसंख्या के तीन प्रतिशत आबादी की बढ़ती भौतिक आवश्यकताओं उपभोज्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है।

महोदया, इन छह: मुख्य कारणों से, मैं वर्तमान वर्ष के बजट संबंधी प्रावधानों का विरोध करता हूं।

महोदया, बजट संबंधी प्रस्ताव नई आर्थिक नीति पर आधारित है। यही समय है कि हम वर्ष 1991-92 में लागू की गई आर्थिक नीति के परिणामों की समीक्षा करें।

संक्षेप में, मैं आपके माध्यम से सभा और सरकार के सामने यह पक्ष रखना चाहता हूं कि देश में स्थिति और बिगड़ गई है। नई आर्थिक नीति के एक परिणाम को देखते हुए, यह समृद्धि नहीं है। यह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में कमी नहीं है। बल्कि कुल मिला कर इससे गरीबी को और बढ़ावा मिला है। गरीबी की स्थिति में और भी गिरावट आई है।

विश्व बैंक के मूल्यांकन के अनुरूप भारत 57 गरीब देशों में एक है। गरीब देशों से मतलब उन देशों से है जिनकी प्रतिव्यक्ति आय 350 डालर से कम है।

जैसा कि आप को मालूम है कि नई आर्थिक नीति ढांचागत समायोजन पर आधारित है जिसे वर्ष 1991 में शुरू किया गया है और ठीक तभी से, प्रतिव्यक्ति आय पर डालर की दृष्टि से विचार करें। वर्ष 1990 में यह 320 डालर था, वर्ष 1992 में यह डालर 310 था और वर्ष 1993 में यह और भी कम हो गया। अत: नई आर्थिक नीति के परिणामस्वरूप हमारे देश में, गरीबी की स्थिति और भी बदतर होती गई है। गरीबी की जकड़न और भी मजबूत हो गई है।

वे इसके विषय में कुछ भी दावा कर सकते है। फिर मैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रतिवेदन का उल्लेख करना चाहूंगा। उस प्रतिवेदन के अनुसार, मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत 173 देशों में से 134वें स्थान पर हैं हम मानव विकास सूचकांक पर कितना खर्च करते हैं। भारत अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 2.5 प्रतिशत ही मानवीय प्राथमिकता पर वाले विषय पर जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर खर्च करता है। आपको यह जानकर बहुत ही दु:ख होगा और मुझे भी दु:ख होगा कि इस प्रकार तो हम मलेशिया के बराबर भी खर्च नहीं करते है। वे अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 6.3 प्रतिशत खर्च करते हैं। जिम्बाबे अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 12.2 प्रतिशत ही खर्च करता है। जॉर्डन सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 6.5 प्रतिशत खर्च करता है। और वे दावा करते हैं कि श्री मनमोहन सिंह तो विश्व के सबसे अधिक सफल वित्त मंत्री है। और उनके अनुसार, इन देशों के वित्त मंत्री अयोग्य है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, हम औद्योगिक विकास पर विचार करें। याद कीजिए कि वर्ष 1990-91 नए आर्थिक कार्यक्रम का सबसे अच्छा वर्ष था। वर्ष 1990-91 में यह 8.3 प्रतिशत का, वर्ष 1991-92 में कोई औद्योगिक विकास नहीं हुआ। विकास दर शून्य रहा है। वर्ष 1991-92 में, यह 1.8 प्रतिशत का, वर्ष 1993-94, यह 1.6 प्रतिशत था। क्या यह नए आर्थिक कार्यक्रम के कारण एक ढांचागत समायोजन कार्यक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व-बैंक द्वारा शोषण और लूटने का यह एक तरीका है। वे कहते है कि वे व्यवहारिक नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था, जैसा कि आप हमसे सहमत हो सकते हैं, गंभीर मंदी के दौर से गुजर रहा है। और यह मंदी की पद्धति आगे भी बढ़ेगी। अत: मैं कहता हूं कि यह बजट गतिरोध और मंदी का कारण है।

पूंजीगत उत्पाद औद्योगिक उत्पादन में अभिवृद्धि का संकेतक है। यह जानकर दुःख होता है कि इसमें 8.8 प्रतिशत की कमी आई है। यह जानकर दुःख होगा कि सरकार ने विदेशी निवेशकों को 16 प्रतिशत के मुनाफा का वचन दिया है। उन्हें बगैर बोली लगाए गए अपना उपकरण लाने की अनुमति दे दी है। इससे देशा में पूंजीगत उत्पाद उद्योग की कठिनाईयां और भी बढ़ जाएगी। खासकर सरकारी उपक्रमों की समस्या और भी बढ़ जाएगी। यह जानकर दुःख होता है कि बजट में पूंजीगत खर्च के लिए किए गए आवंटन में 6 प्रतिशत की कटौती की गई है। वर्ष 1993-94 में यह 19672 करोड़ रूपये था और इसे आने वाले वर्षों में 18520 करोड़ कर दिया गया है। परिणाम यह होगा कि सभी सार्वजनिक उपक्रम जैसे बी एच ई एल और अन्य उपक्रम, जो पूंजीगत उत्पाद का उत्पादन करता है, भी इस तरह की प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा और इन विदेशी कंपनियों पर यह जिम्मेदारी नहीं होगी कि वे पूंजीगत मशीनरी की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बोली लगाकर खरीदारी कर सकें। और हमारे सरकारी उपक्रमों को बोली लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। वे बोली लगाने में भाग नहीं ले सकते हैं।

सीधे विदेशी निवेश के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। मैं यही कहूंगा कि यह बहुत ही निरूत्साहजनक है।

अप्रैल-दिसम्बर 1993 के दौरान कुल विदेशी निवेश का प्रवाह 1.8 विलियन डालर था। मैडम, क्या आपको मालूम है कि 1 विलियन डालर पोर्टफोलियों निवेश के माध्यम से आया है और यह निवेश विदेशी संस्थागत निवेशकों ने किया है। रूपये के मामलों में यदि मेरे पास समय हो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अतः, यह विदेशी निवेश उत्साहवर्धक नहीं है और यह स्थायी नहीं है। अगर मुद्रास्फीति इसी तरह बढ़ता रहा है तो यह बदल सकता है।

महोदया, वे निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना चाहते है, लेकिन देखिए उन्होंने क्या किया है। निजी क्षेत्र का निवेश भी अब कम होता जा रहा है। मैं बजट दस्तावेज के आधार पर कह रहा हूं। वर्ष 1990-91 में, यह निर्जीव क्षेत्र का निवेश सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 16.2 प्रतिशत के बराबर था। वर्ष 1993-94 में यह 14.6 प्रतिशत था। अब देश में निजी पूंजीगत निवेश भी कम हो रहा लेकिन सरकार का कहना है कि नई आर्थिक नीति से हमारी औद्योगिक व्यवस्था में बेहतरी के लिए तीव्र परिवर्तन आ रहा है। मैडम, कृषि उत्पादन में भी काफी कमी आई है। मैं काफी इसलिए कहूंगा कि यह अच्छा वायुमंडल और मानसून के कारण है।

अब मैं राज्य के बारे में दूसरे मुद्दे उठाऊंगा। राज्य की अर्थव्यवस्था भी हमारी जिम्मेदारी है। मैडम, राज्यों के लिए कुछ केन्द्रीय सहायता में भी कटौती की गई है। वे दावा करते हैं कि राज्यों ने योजना आवंटन को बढ़ा दिया है लेकिन मध्य प्रदेश राज्य में क्या हुआ, जहां कि आपकी सरकार है। योजना सहायता में कटौती की गई है। यह वर्ष 1993-94 में 20013 था और यह घट कर 18,000 रूपये हो गया। इसका मतलब इसमें 6.4 प्रतिशत कमी हुई।

नौकरियों के विषय में मैं कहना चाहता हूं कि चुनावी वादा किया गया था हर वर्ष 100 लाख नौकरियों प्रदान की जाएंगी यदि कांग्रेस सत्ता में आ गई तो। आप सत्ता में तो हैं ही, कोई संदेह नहीं है। हम आपको चुनौती भी दे सकते है। आपने काम चलाऊ, बहुमत हासिल कर लिया है और श्री पी. वी. नरसिंह राव आपके साथ हैं। सत्ता में कुछ समय के लिए होने की आप उम्मीद करते हैं ताकि लोग समझ सकें और सही तस्वीर देख सकें।

जहां तक रोजगार रजिस्टर में बेरोजगार लोगों की संरचना का संबंध है यह 3.63 करोड़ तक आता है। श्री मनमोहन सिंह ने यह कहते पाए गए हैं कि बेरोजगारी की समस्या कम हो गई है क्योंकि रजिस्टर में संख्याओं में कमी आई है। खैर, वह किसी उत्तर की अपेक्षा नहीं करते क्योंकि उन्हें सच्चाई का अनुभव

नहीं है। लेकिन अप्रैल-दिसम्बर, 1993 के दौरान क्या हुआ। रोजगार केन्द्र ने जैसा सलाह दिया था, उसके मुताबिक नामों की इसमें कुल संख्या 3.63 करोड़ है। 1.57 लाख लोगों को बहाल किया गया। रोजगार स्थिति में आगे और भी गिरावट आती जाएगी।

हमारे देश में 3 लाख से अधिक एककों में 30 लाख लोग काम कर हैं। एक अनुसंधान संस्था ने अनुमान लगाया था कि वर्ष 1992-93 के दौरान 40 लाख और वर्ष 1993-94 में 8 मिलियन अतिरिक्त बेरोजगारी ही गई थी यह सब नई आर्थिक नीति का परिणाम है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं रोजगार स्थिति के बारे में दो शब्द कहूंगा। यह दावा किया गया है कि रोजगार केन्द्र का रजिस्टर कमी दर्शाता है। मैं आर्थिक सर्वेक्षण को देखते हुए इस बात की चर्चा कर रहा हूं।

रोजगार केन्द्र के आंकड़े बताते हैं कि नवम्बर 1992 में यह 367.75 लाख था जबकि वर्ष 1993 में यह 362.52 लाख था। क्या यह ठीक था। यही कमी है। यह कमी पांच लाख की है कल्पना कीजिए। बहाली में 8,000 की वृद्धि हुई है। कोई तो इन आंकड़ों को स्पष्ट करे।

सभापति महोदय : श्री चटर्जी कृपया दूसरा भाषण शुरू मत कर दीजिए।

श्री चित्त बसु : धन्यवाद, महोदय मैंने आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत ही सीमित समय दिया गया है। लेकिन मैंने पढ़ा है और मैंने इसका अध्ययन किया है। अतः मैं कहता हूं कि बहली 230 प्रतिशत से भी कम हुई। एक व्यक्ति पर 250 लोगों के ऊपर एक व्यक्ति बहाल किया गया है।

अब आशंका व्यक्त की जा रही है कि सरकार गोस्वामी समिति की सिफारिशों को स्वीकार करेगी, नरसिंहम समिति का जहां तक बैंक का मामला है, मल्होत्रा समिति का, जहां तक बीमा का प्रश्न है। और ननजुदैईया समिति का जहां तक रेलवे का मामला है। रोजगार की स्थिति में और भी गिरावट आएगी और सदन सहमत होगा कि ये सब चीजें नए आर्थिक कार्यक्रम के परिणाम हैं और यह हमें बरबादी की ओर ले जाएगा।

और अंत में मैं यह कहूंगा कि इस बजट ने निर्गम नीति के खतरे की भविष्यवाणी की गई है। लेकिन बजट ने 1020 करोड़ का आवंटन इस नीति के कार्यन्वयन के लिए किया है। कुछ मामलों में यह पाया गया है कि कम से कम निर्गम नीति शीर्ष के अन्तर्गत बजटीय आवंटन फैक्ट्री चलाने के लिए बजटीय आवंटन से अधिक है। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण एन टी सी है। देश भर की राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के लिए 1000 करोड़ रूपये का बजट-आवंटन किया गया है और 84 करोड़ रूपये श्रमिकों को नौकरियों और रोजगार से वंचित करने के फलस्वरूप मुआवजे के लिए आवंटित किए गए हे। अतः हम निर्गम नीति से जो कुछ समझते हैं वह यह है कि एन टी सी के कर्मचारियों को भी अपने कटु अनुभव से समझना होगा और अन्य उद्योगों का अनुसरण करना होगा।

अंतिम मुद्दे पर आते हुए, जहां तक रियायतों की बात है, तो एक वाक्य ही पर्याप्त होगा। इन तीनों बजटों के दौरान यह मनमोहन सिंह द्वारा पेश किया हुआ चौथा बजट है - हमेशा, नई आर्थिक नीतियों को नाम पर अमीरों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और विदेशी निवेशकों को रियायते दी गई है। पिछले वर्ष, मैं याद करता हूं कि यह राशि 3,273 करोड़ रूपये थी जो समाज के धनी वर्गों को रियायतों के तौर पर दी गई है। इस वर्ष, यह राशि दुगुनी है। वर्ष 1994-95 के बजटीय प्रस्तावों में यह 6,373 करोड़ रूपए है और यही बजट का सही पक्ष है। बजट का सही पक्ष ही गंदा है। इस बजट के सही पक्ष को लोग पहचानें तथा समझें। बाहर के लोगों ने इसे पहचान लिया है। लेकिन इस सभा के बहुत से संसद सदस्य इसे समझ नहीं पाते हैं, जबकि लोग इसे समझ चुके हैं और वे इस नई आर्थिक नीति को कामयाब नहीं होने देंगे क्योंकि

यह ऐसी स्थिति को उत्पन्न कर रही है, जिससे लोगों की विपदाएं घनीभूत होती जा रही हैं। अत: मैं इन बजट प्रस्तावों का पुरजोर विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे (नागपुर) : आदरणीय सभापति महोदया, माननीय वित्त मंत्री ने वर्ष 1994-95 का जो बजट संसद में प्रस्तुत किया है, वह न केवल ऐतिहासिक है अपितु राष्ट्रहित के प्रति पूर्णत: समर्पित होने के साथ एक नई दिशा को अंकुरित करने वाला भी है। आधुनिक भारत के निर्माता देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जिस अर्थतंत्र का उच्चतम रूप सोचा था, उसकी यथार्थ की आवृति का नाम ही वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत यह बजट है। आम आदमी की आशा व उम्मीदों को सार्थकता प्रदान करने के साथ हर स्तर व वर्ग के लोगों को राहत व दिलासा दिलाने का महत् प्रयास इस बजट की विशेष उपलब्धि है। इसका समर्थन करते हुए मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने जब देश की बागडोर संभाली, उस समय व्यवस्था का आर्थिक ढांचा पूर्णत: जर्जर हो चुका है। विरासत के रूप में जो उन्हें मिला था, वह भी खाली तिजोरी, चरमराती व्यवस्था, लोक मन का क्षोभ, अन्तर्राष्ट्रीय मायनों में गिरती हुई साख व जन-मानस से उपजी घनघोर निराशावाद। इस परिपेक्ष्य में आज से तीन वर्ष पहले जो बीज धानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने तन्मयता के साथ बोये थे, आज यह उसी का अंकुरित रूप है। मैं यह कहने से गर्व महसूस करता हूं कि यह बजट -लोगों का, लोगों के लिए ओर लोगों के द्वारा मतलब है जिसमें कांग्रेस व उसकी सार्वजनिक नीतियों का मूर्तिमत स्वरूप दिखाई पड़ता है।

मैंने कल सभी विरोधी दल के नेताओं के भाषण सुनें। उन्होंने उदारवादी नीति की आलोचना की। उदारवादी नीति को लेकर विश्व में आर्थिक क्रांति होने जा रही है। अगर इस दृष्टि से इसमें कुछ सुझाव देते तो वे लाभदायक होते। उन्होंने अपने भाषण में आलोचना के सिवाय दूसरी कोई बात नही की। विरोधी दल के नेताओं ने कहा कि यह बजट गरीबों के हित को देखते हुए नहीं बनाया गया है। इससे बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलने वाला है और बड़े पूंजीपतियों को ही इससे फायदा पहुंचने वाला है। यह देश का बजट है, पार्टी का बजट नहीं है।

उदारवादी दृष्टिकोण से विश्व में जो आर्थिक परिवर्तन बड़े पैमाने पर होने जा रहे हैं, उनके बारे में अगर आप कोई सुझाव देते तो हमारे वित्त राज्य मंत्री उनको नोट करते। यहां कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों के लिये कुछ नहीं किया गया, बेरोजगारों के लिये कुछ नहीं हुआ। मैं जानकारी के लिये उन्हें बताना चाहता हूं कि जवाहर रोजगार योजना पर पहली दफा 145 करोड़ रूपए रखे गये हैं। इतनी बड़ी राशि आज तक ग्रामीण लोगों के लिये कभी नहीं रखी गई थी।

महाराष्ट्र में रोजगार गांरटी योजना के तहत गांव में लोगों को काम मिलता है। सरकार ने इस कार्यक्रम के लिये बहुत धन आवंटित किया। प्रधानमंत्री जी ने सारे देश में इसको लागू करके जो ऐतिहासिक कदम उठाया, उसकी आज हर कोई प्रशंसा कर रहा है। आत गांव में रहने वाले लोग काम करना चाहते हैं। उनको काम देने की गांरटी नरसिंहराव जी ने दी। बहुत बड़ा काम इस कार्यक्रम के माध्यम से हुआ है। ग्रामीण इलाकों में जल आपूर्ति के लिये 800 करोड़ रूपये रखे गये हैं। सहकारिता और सिंचाई के काम में कोई कटौती नहीं की गई है। प्रधानमंत्री जी ने हर दृष्टि से गरीबों का ख्याल रखा है। बड़े उद्योग आयेंगे तो उनके लिए बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे पास आज इतना पैसा नहीं है कि हम खुद बिजली का उत्पादन कर सके। चाहे आप सत्ता में रहे या हम रहे, बिजली का तो उतपादन करना ही है। इस काम पर करोड़ो रूपए खर्च करने पड़ते हैं। और यह जो उदार नीति है, यह बाहर के लोगों का पैसा लायेगी और यहां वह पैसा खर्च होगा। जो पैसा हम 10-15 साल तक नहीं देते, वह अब यहां देने वाले हैं और इससे

रोजगार बढ़ेगा, लोगों को काम मिलेगा। किसी भी जगह जब बड़ी इण्डस्ट्रीज आती हैं तो उससे वहां छोटी-छोटी इण्डस्ट्रीज भी बढ़ती हैं। यह भी एक बड़ा काम इस वर्ष इस बजट में हुआ है। हम कहते है कि इस बजट के अन्दर लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा, यह ठीक है लेकिन छोटे उद्योग-धन्धे वाले जो लोग हैं, उन पर जो टैक्सीकरण की बात है, उस पर भी हमारे वित्त मंत्री जी जरूर ध्यान देंगे।

जैसा कि स्वयं वित्त मंत्री जी ने कहा है कि यह बजट 6 मूलभूत पहलुओं को मंद्देनजर रखकर बनाया गया है, कर प्रणाली में सुधार, आधुनिकीकरण की तेज गति, राजकोषीय घाटे की बढ़ोत्तरी को सुधारने का प्रयास, निर्यात पर बल, औद्योगिक सुधार, बैंकिंग प्रणाली में सुधार व जनहित हेतु विकासोन्मुख योजनाओं का कार्यान्वयन। इस सन्दर्भ में हमारे विदेशी मुद्रा के आरक्षित भण्डार में लक्षणीय वृद्धि हुई है। जून, 1991 में जो एक बिलियन डालर थी, अब 13 बिलियन डालर हो गई है। इसके लिये वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। हमारा सोना, जो विदेशों में गिरवी रख दिया गया था, उसका हमारे पास वापस आ जाना, कम बड़ी उपलब्धि नहीं है।.......(**व्यवधान**)....... ठीक है, लेकिन जो गलत हुआ है, उसको दुरूस्त करने का काम हमारे वित्त मंत्री जी ने बहुत कम टाइम में किया है। वह यह काम नहीं करते तो आज देश की हालत क्या होती, यह तुम और हम अच्छी तरह से समझ सकते है।

निर्यात में वर्ष 1993-94 के प्रथम 10 महीनों में डालर के रूप में 21 प्रतिशत की वृद्धि हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती का प्रमाण है। उन सभी मथों के बावजूद कि उदारीकरण से आयातों में भारी वृद्धि हो जायेगी, अप्रैल से जनवरी, 1993-94 की समतुल्य अवधि के दौरान किये गये आयातों से एक प्रतिशत कम हो जाना, रूपये की विनिमय दर का एकीकरण व व्यापार नियंत्रण के हटाये जाने के बावजूद स्थिर रहना व विदेशी पोर्टफोलियों निवेश में वर्ष 1992-93 के 150 मिलियन डालर से 1993-94 में 3 बिलियन डालर की वृद्धि हमारी आर्थिक नीतियों के कारण बढ़ते हुए अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास का प्रतीक है।

घरेलू अर्थव्यवस्था की प्रगति के साथ-साथ कृषि उत्पादन की रिकार्ड बढ़ोत्तरी भी एक दूरगामी उपलब्धि है आर्थिक उदार धोरन के अवलम्ब के समय विरोधियों की यह आशंका कि इससे बेरोजगारी में वृद्धि होगी, यह निराधर साबित हुई है। क्योंकि, रोजगार कार्यालियों में पंजीकृत और रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों के अद्यतन आंकड़े नवम्बर, 1992 की तुलना में नवम्बर, 1993 में 1/4 प्रतिशत की कमी दर्शाते हैं। इन वस्तुस्थितियों के तहत कीमतों में अंकुश की सम्भावना को बल मिलता है।

इस बजट के प्रमुख दो लक्ष्य दीख पड़ते है। पहला लक्ष्य घाटे की अर्थव्यवस्था समाप्त कर वित्तीय स्थायित्व प्रदान करना व दूसरा देश के आर्थिक ढांचे में बदलाव लाना है। इन लक्ष्यों के अनुरूप उद्योग आयात-निर्यात, विदेशी निवेश व मुद्रा नीति में बदलाव मील के पत्थर कहे जा सकते हैं। इसी के साथ-साथ सरकारी सब्सिडियों को घटाने के साथ-साथ सरकारी खर्च पर अकुंश रखने का अभिवचन भी नये आशावाद का निर्माण करता है। वे सार्वजनिक इकाइयां, जिनको बजटीय सहायता देनी पड़ती है, जिसका राजकोष पर सीधा बोझ पड़ता है, उन्हें अपने खाते दुरूस्त करने के निर्देश भी एक औचित्यपूर्ण कदम है।

4.54 म.प.

(माननीय उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

राजकोषीय अनुशासन को सुदृढ़ करने के स्पष्ट दिशानिर्देश, वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण देने की अपनी न्यूनतम दर, बयाज दर के अतिरिक्त एक प्रतिशतांक की कमी, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिये गये ऋण की समय पर आदायगी, चालू लेखे में परिवर्तनीयता, कम्पनी अधिनियमों में सामयिक संशोधन, ग्रामीण ऋण प्रणाली को मजबूती प्रदान करने के साथ-साथ ग्रामीण विकास के लिए प्रावधान में वांछनीय वृद्धि, एक कुशल व प्रतिस्पर्धी पूंजी बाजार की रचना इस बजट की प्रमुख उपलब्धियां हैं।

आयकर के ढांचे में बुनियादी परिवर्तन भी लोक आकांक्षा के अनुरूप है। कड़े नियंत्रण और अनुपालन के जरिये भारत के अब तक के संकीर्ण कर आधार को व्यापक बनाने के लिए वर्तमान घोषित कर ढांचा आम आदमी की आवश्यकता के अनुरूप होने के कारण ही उसका व्यापक स्वागत है व हो रहा है। इसी के साथ नियमित आयकर पर लगने वाले अधिभार की समाप्ति भी सामान्य कर दाताओं को आवश्यक दिलासा देने में सक्षम साबित हुई है। मेरा कहना यह है कि जो सैलेरीड पीपल हैं उनके लिए आप थोड़ी और छूट दे दें तो अच्छा रहेगा।

महोदय, 65 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली आयकर छूट सीमा की वृद्धि भी एक योग्य कदम है। इसके साथ ही गरीब परिवार के विद्यार्थियों को सहायता के लिए कर ढांचे में विशेष प्रावधान सार्वजनिक व जरूरतमंदों की आवश्यकता की पूर्ति के प्रति सरकार की प्रतिबधता का परिचायक है। इसमें चिंता का पहलू है घाटा कम करने के पिछले बजट लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाता। राजकोषीय घाटा जिसे 36959 करोड़ तक सीमित रखने का लक्ष्य था वह बढ़ कर 58551 करोड़ हो गया। उसी तरह बजट घाटा 4314 करोड़ से बढ़ कर 9060 करोड़ हो गया। इस वस्तुस्थिति से मंहगाई बढ़ने की संभावना है। यही कारण हैं कि इस दिशा में अत्यधिक जागरूकता की आवश्यकता है। सरकार को बाजार पर लगातार ध्यान देना होगा ताकि बजट की रियायतों व राहतों का लाभ प्रत्यक्षत: जनता तक पहुंचे।

महोदय, मैं उदारीकरण की बात करता हूं। इसमें मैं एक ही बात कहूंगा कि उच्च शिक्षा व व्यवसायिक शिक्षा हेतु वित्तीय प्रावधान बढ़ाया जाना चाहिए। विशेष अनुदान हेतु राशि का आवंटन आवश्यक है व उसी के साथ इस दिशा में कार्यरत शैक्षणिक संस्थाएं जो शासकीय वित्तीय अनुदान प्राप्त नहीं करती उन्हें ब्याज रहित ऋण या न्यूनतम दरों पर ऋण देने का तात्कालिक प्रावधान आवश्यक है जिससे उच्च शिक्षा के प्रचार व प्रसार को बल मिलेगा।.....**(व्यवधान)**..........मेरा कहना यह है कि जो अच्छे प्राइवेट कॉलेज चलाते है वहां अच्छी एजुकेशन दी जाती है वहां आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी अच्छा हुआ है।............**(व्यवधान)**............ हम 50 परसेंट बच्चों को इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते है।......**(व्यवधान)**....... मेरा कहना यह है कि जिनका एक परसेंट कम मार्क होता है उसको हम एक-डेढ़ लाख की बात जब मेडिकल के लिए करेंगे तो वह भी ठीक नहीं है। इस दृष्टि से पार्लियामेंट के अंदर जो उच्च शिक्षा की बात है, जो अच्छी शिक्षा देने वाला प्रस्ताव है उनको जो ऋण देने की बात है, जो अच्छी संस्थाएं है वे लोग जो भी काम कर रहे हैं वे संस्थाएं ठीक ढंग से चले इस और ध्यान देने की जरूरत है।

महोदय, मैं नागपुर से आता हूं और यह पूरे देश का सेंट्रल प्लेस है। वहां 20 लाख की बस्ती है और वहां कोई टेलीफोन की सुविधा नहीं है। मेरा कहना यह भी है कि वहां रेलवे की सुविधा जरूर होनी चाहिए।...**(व्यवधान)**......वहां बाहर के बड़े-बड़े पूंजीपति लोग आ रहे है। हमारे यहां हजारों करोड़ो रूपया लगाकर सबसे बड़ा उद्योग का क्षेत्र बन रहा है। वहां करोड़ो रूपया खर्च करके औद्योगिकरण होने जा रहा है। वहां प्रधान मंत्री जी का भी बहुत सहयोग मिला है।.....**(व्यवधान)**......वहां जो काम हो रहा है उससे बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा।

महोदय, यह जो बजट है इसका पूरे देश के लोगों ने स्वागत किया है लेकिन जो हमारी विरोधी पार्टी के लोग हैं वे पता नहीं इसका क्यों विरोध कर रहे है।

5.00 म.प.

विरोधी दल के लोगों को विरोध करना चाहिए, लेकिन जो सही चीजें हैं, उनकी चर्चा भी अवश्य करनी चाहिए। आज हमारी सरकार नई नीति के तहत विश्व बाजार में भारत को ले जाने का काम कर रही है, गरीबों की भलाई के लिये काम कर रही है, गरीबों के लिए काम के स्कोप को बढ़ाने का काम कर रही

है, लेकिन बीजेपी के सभी व्यक्तियों के भाषणों में मैंने एक शब्द भी नई नीति के समर्थन में नहीं सुना। विरोधी दलों को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि नरसिंह राव सरकार इस देश को अच्छी आर्थिक नीति दे कर सर्व-साधारण की भलाई का काम कर रही है।

इन्ही शब्दों के साथ इस बजट का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा (चतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट पर विचार करते समय सबसे पहले इसके आर्थिक रूझान की तरफ ध्यान जाता है, देश की अर्थ व्यवस्था की दिशा की ओर जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बजट इस देश को विश्व बाजार में छलांग मार कर ले जाने का काम करेगा और विश्व व्यापार में भारत का प्रतियोगिता के आधार पर ले जाने का प्रयास किया जाएगा। जब हम भारत को विश्व बाजार में, विश्व व्यापार में छलांग मारकर ले जाना चाहते है तो हमको यह भी देखना होगा कि विकसित देश किस तरह से काम कर रहे है और हमको भी वैसे ही काम करना होगा। अमेरिका जो उद्योग प्रधान देश है, वहां पर प्रति व्यक्ति जितनी पूंजी उद्योग में लगाई जाती है, उससे अधिक प्रति व्यक्ति पूंजी कृषि में लगाई जाती है। जब हम विश्व प्रतियोगिता की बात करते है तो हमको यह व्यवस्था भी अपने बजट में करनी होगी और ज्यादा से ज्यादा कृषि में इनवेस्टमेंट करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत और दूसरे विकसित देशों में फर्क है। अमरीका का क्षेत्रफल 94 लाख वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 25 करोड़ है, जबकि भारत का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलो मींटर है और जनसंख्या 87 करोड़ है। अमरीका में जमीन अधिक है और आदमी कम हैं और हमारे यहां आदमी अधिक है और जमीन कम है। विकसित देशों में मशीन सस्ती है और हाथ महंगा है, लेकिन हमारे यहां मशीन मंहगी है और हाथ सस्ता है। हम अपने बजट में इस बात को खोजते है तो कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। हमें जापान, ताईवान, कोरिया, चीन आदि देशों से सबक लेना चाहिए, जहां श्रम-शक्ति अधिक थी, जिसको उन्होंने विकास के काम में लगा दिया और तेजी से आगे बढ़ गये। इन देशों ने कर्जा नहीं लिया और लिया भी तो नाममात्र का लिया। लेकिन हमारे यहां उल्टा काम हो रहा है। हमारे यहां उपलब्ध अपार श्रमशक्ति को तो बेकार किया जा रहा है, उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है और हम समझ रहे है कि विदेशों से कर्जा ले कर इस मुल्क के उत्पादन को विदेशी बाजार में पहुंचा देंगे।

विश्व व्यापार के पिछले इतिहास को देखें तो पता चलेगा कि 1950 में विश्व व्यापार में भारत का दो प्रतिशत हिस्सा था, बीस वर्षों के बाद 1970 में 0.6 परसेंट था और फिर बीस वर्षों के बाद 1990 में 0.5 परसेंट पर था और आज भी 0.5 परसेंट है। 1950 में जब दो प्रतिशत हिस्सा था तब हमारे ऊपर विदेशी कर्जा नहीं था, वह शैतान की आंत की तरह बढ़ता चला गया जैसे- 1952 में 32 करोड़ रूपए और 31 मार्च 1953 में 2 लाख 76 हजार 662 करोड़ रूपयों पर पहुंच गया जिसका सूद हमें इस साल 46 हजार करोड़ रूपए देना पड़ रहा है। जैसे-जैसे विदेशी कर्जा बढ़ता चला गया वैसे-वैसे विश्व व्यापार से हमारा हिस्सा कम होता चला गया, ये सरकारी आंकड़े हैं। जो बजट हमारे सामने है तो क्या हम इससे तरक्की कर सकेगें। अंधाधुंध जो कर्जा आ रहा है उसको कहां लगाया जाए, यह भी दिमाग में नहीं है। साठ हजार करोड़ रूपया जो विदेशों से ऋण के रूप में आया हुआ है वह बेकार पड़ा हुआ है जिसका इस्तेमाल आज तक नहीं हो सका है। उस रूपए को इस्तेमाल नहीं करने पर प्रतिबद्धता शुल्क कमिटमेंट चार्जेस देने पड़ते है। यह कैसा बजट है कि अंधाधुंध कर्जा लिया जा रहा है और जिसका इस्तेमाल आज तक नहीं हो पा रहा है। उसके कुपरिणाम देश को भोगने पड़ रहे है और इस देश की संस्कृति और सम्पदा दूसरी ओर जा रही है और पंचतारा होटलों की संस्कृति हमारे देश में कायम हो रही है जिसे देश को भुगतना पड़ रहा है। जब आप प्रतियोगिता की बात करते है तो सोच लें किससे प्रतियोगिता करनी है? गांव का आदमी जब शहर में नौकरी

करने जाता है और जब वह दस या बीस हजार रूपया पोस्ट आफिस में जमा कर लेता है तो वह भी एक सेठ की तरह मकान बनाने की सोचता है और पूरा पैसा लगा देता है। नींव पड़ने के बाद उसके पास पैसा नहीं होता है तो वह नींव ज्यों की त्यों रह जाती है। ऐसा न हो कि "पड़ जाए सब मनोरथ सभी सुना-धोखे में दही के न खा लेना कहीं चूना"। हमारी हालत खराब हो रही है तो इस विश्व प्रतियोगिता में क्या होगा? बाजार में विदेशी सामान आने लगा है। मैथिलिशरण गुप्त की वह पंक्ति याद आ रही है जिसमें उन्होंने कहा है "सब वस्तुएं हैं मेड इन इंग्लैण्ड, इटली, जर्मनी, चीन, अमरीका व अन्य देशों की बनी।" है। पचास करोड़ का कागज गोदाम में बनकर तैयार है लेकिन वह नहीं बिक रहा है। विदेशी कागज आ रहा है और सस्ता पड़ रहा है। यह विदेशी कागज, विदेशी सामान उस समय तक सस्ता रहेगा जब तक हमारे कारखाने बंद नहीं हो जायेंगे। जिस दिन हमारे कारखाने बंद हो जायेंगे उसी दिन हम देखेंगे कि विदेशी सामान की कीमतें बढ़ गई है। हमारे उद्योग धंधें पर यह खतरा है। मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक छोटे-छोटे उद्योग धंधों का सवाल है उस पर काफी चर्चा हो चुकी है। मैं वित्त मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि इस बजट से पहले स्माल स्केल इंडस्ट्रीज पर उत्पाद कर नहीं लगता था, अब आपने लगाने का प्रस्ताव किया है तो उससे बहुत नुकसान होगा। इसको आप कृपया वापस ले लें। क्योंकि जितनी औद्योगिक चीजें बनती है। उनका 60 प्रतिशत कुटीर उद्योगों में पैदा होता है। तीन करोड़ लोग इसमें काम पा रहे हैं। वित्त मंत्री से मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अमरीका की तरह हिन्दुस्तान में भी कृषि क्षेत्र में उद्योगो में ज्यादा पूंजी लगायें। आपने टैक्स होलीडे की योजना बनाई है किन्तु बिहार को इससे वंचित रखा है। कृपया बिहार जैसे गरीब राज्य को भी उसमें शामिल करे।

इस देश में करीब ढाई करोड़ आदमी बेरोजगार है। जिसमें शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 70 लाख है और 60 लाख के करीब ऐसे हैं जिनको थोड़ा काम मिलता है। बहुत से लोगों के नाम रोजगार कार्यालयो में दर्ज नहीं है। इस बेरोजगारी की समस्या को आप सामने रखकर सोचे कि क्या हम बेरोजगारों की संख्या में और बढ़ोत्तरी करने वाले है या घटाने वाले है। वह बजट किस काम का है जिस बजट से मुल्क में मंहगाई बढ़े, जिस बजट से मुल्क में बेरोजगारी बढ़े। जिस बजट से मुल्क में विदेशी कर्जा बढ़े और विषमता बढ़े, वह बजट किस काम का है। बजट कभी भी स्वीकार करने लायक नहीं हो सकता।

सरकार कहती है शिक्षा पर हम पिछले साल से ज्यादा खर्च करेंगे। पिछले साल 952 करोड़ रूपये का प्रावधान था और इस साल सरकार 1310 करोड़ रूपये खर्च करने जा रही है। इसका भी ब्यौरा देखिये। यह पैसा कहां जा रहा है गांव में तो नहीं जा रहा है। आपने दो प्रकार की शिक्षा व्यवस्था कायम की है। छोटे-छोटे बच्चों के बीच मे विषमता पैदा की है। जो अमीर के बेटे है, अफसरों के बेटे हैं, विधायकों और सांसदो के तथा मंत्रियों के बेटे है, साहूकारों के बेटे हैं उनके लिए केन्द्रीय विद्यालय खोल रखे है, बम्बई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में, जो इस बजट का ज्यादा पैसा खा जाते हैं। नवोदय विद्यालय खोल रखे है, जो इस बजट का ज्यादा पैसा खा जाते है। गांवो में पाठशालाओ को देखिए, किसी की दीवार नहीं है, किसी पर छप्पर नहीं है, कहीं पर मास्टर नहीं है तो कहीं पढ़ने-पढ़ाने का सामान नहीं है। वित्त मंत्री कब तक इस देश को इस प्रकार रखेंगे। यदि आप चाहते हैं कि इस देश में देशभक्ति पनपे, सबको बराबरी का दर्जा मिले, लोगों में स्वाभिमान जगे तो आप इस तरह की भिन्न-भिन्न व्यवस्था का अंत करें। समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे, नहीं तो जो व्यवस्था चल रही है यह बेईमानी होगी और गरीबों के बच्चों के साथ अन्याय और ज्यादती होगी। आपने अपने आंकड़ो में कहा है कि गांव वालो को आपने बहुत कुछ दिया है। मैं जिस इलाके से आता हूं वह देश का बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। पलामू चतरा और गया, जहां गांव में जाने पर गांव वाले कहते है कि हमारे यहां एक दाना भी खाने को नहीं है। हमारे पास एक दाना अन्न का नहीं है जो खिला सके। हां टमाटर मुर्गा खिला सकते हैं जबकि चावल और गेहूं

नहीं। जब मैं वहां देखता हूं तो पाता हूं कि उनके पास पहनने के लिये कपड़ा तक नहीं है। हमारे इलाके के लिये इस बजट से भी कुछ नहीं मिलने वाला है। इसको देखकर निराशा होती है। वहां पर न कोई नया कारखाना खुलने वाला है, न कोई सिंचाई की नयी व्यवस्था होने वाली है और न ही वहां कोई नया स्कूल खुलने वाला है। आज इस मुल्क में 5 करोड़ बच्चे-बच्चियां स्कूल का मुँह नहीं देख पाती। देखते हैं। इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वह ग्रामीण गरीबों के लिये कितना फण्ड देती है। सरकार ने पिछले साल 5606 करोड़ रूपया दिया जो इस वर्ष 7010 करोड़ रूपया किया है। इस प्रकार गत वर्ष की 25 रूपये सालाना की अपेक्षा इस वर्ष 29 रूपये प्रति व्यक्ति को पड़ता है। इसमें केवल 4 रूपये की वृद्धि होना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि अनाज की कीमत तो इससे कई गुना अधिक बढ़ी है। इसलिये मैं यह कह रहा हूं कि जहां जहां इस बजट में गड़बड़ी हुई है, उससे देश में बेचैनी फैली हुई है, उसे वापस लें।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बजट प्रस्ताव का सवाल है, इसका कुछ हिस्सा मीठा और कुछ खट्टा होता है। यह बजट केवल 2 करोड़ लोगों के लिये मीठा साबित हो रहा है जबकि 85 करोड़ जनता के लिये खट्टा है। इसलिये मेरा वित्त मंत्री से निवेदन है कि जरा खट्टेपन की मात्रा कम करके उसमें मिठास बढ़ायें ताकि ग्रामीण जनता को भी उसका स्वाद अच्छा लग सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : हमारे क्षेत्र में पढ़ रहे बच्चों में से तीस प्रतिशत बच्चे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बंधित हैं तथा वे शतप्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। यही एक मात्र ऐसा स्कूल है जिससे कि ग्रामीण निर्धन बच्चे शिक्षा पाने का लाभ उठा रहे हैं। वास्तव में यह दुःख की बात है कि नवोदय विद्यालय पर इस प्रकार से हमला किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच-पड़ताल करूंगा तथा यदि उपयुक्त होगा तो ऐसी समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा। अब श्री मनोरंजन भक्त जी बोलेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मनोरंजन भक्त का नाम बोलने वाले सदस्यों की सूची में नौवां है।

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : कुछ अन्य व्यक्तियों का नाम बोलने वाले सदस्यों की सूची में शामिल कर लिया गया है। पंजाब राज्य के किसी सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री मनोरंजन भक्त जी बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो वर्ष 1994-95 से संबंधित बजट प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करते हुए अपने विचार रखने के लिये खड़ा हुआ हूं। शुरू से जितने सम्मानीय सदस्यगण इस पर बोले है, चाहें वे विरोधी पक्ष के रहे हैं या सत्ता पक्ष के, मैंने उनको गौर से सुना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी देश की वित्तीय व्यवस्था और उस देश का बजट, उस देश की राजनैतिक स्थिरता पर आधारित होता है। यदि किसी देश में राजनैतिक स्थिरता नहीं होगी तो उस देश में आर्थिक विकास और आर्थिक स्थिरता भी नहीं रह सकती है। इसी कारण मुझे यहां उस बात को दोहराना पड़ता है और हमारे विरोधी दल के लोग इस बात को समझते है कि क्यों

मैं यहां 1990-91 की बातों को दोहराता हूं क्योंकि जब देश में कांग्रेस सरकार सत्ता में आयी, नरसिंह राव जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उस समय देश की राजनैतिक स्थिरता ऐसी थी कि देश के लोगों को लगता था कि इस देश में अब हर साल एक प्रधानमंत्री बनेगा, देश में विकास का कोई काम चल ही नहीं पायेगा और देश में जाति-पाति और धर्म का नाम लेकर जिस तरह से राजनीति चली, उससे स्पष्ट नहीं लगता था कि सारा भारत टुकड़े-टुकड़े हो जायेगा या एक रहेगा। लेकिन जैसे ही नरसिंह राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां बनी, उसने देश को राजनैतिक स्थिरता प्रदान की और इसके साथ ही उदारीकरण की नीति को देश में आरम्भ किया।

यह बात ठीक है कि हम आजादी के बाद इतने दिनों तक जिस दिशा में लगातार बढ़ते आये, पब्लिक सैक्टर और प्राईवेट सैक्टर की मिश्रित अर्थ नीति को हम चलाते आये, इतने साल उस नीति पर चलकर जब हमने सिहावलोकन किया कि हमें क्या मिला, क्या नहीं मिला, तो इस देश की जरूरतों को देखने के बाद हमने निर्णय किया कि हमें अपनी बुनियादी नीति में थोड़ा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। इसीलिए हमने उसमें जहां आवश्यकता थी, कुछ संशोधन किया।

यहां अभी एक माननीय सदस्य ने बोलते हुये देश में बेरोजगार लोगो की संख्या बताई, आंकड़े दिये। खाली बेरोजगार लोगों के आंकड़े देने से ही काम नहीं चलता। यदि हम बेरोजगारी दूर करने के लिये कदम न उठाये, रोजगार के अवसर पैदा न करे, उस समय तक हमारे बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पायेगा। बेरोजगारों को तभी रोजगार मिल पायेगा जब हमारे देश में पूंजी लगेगी, जब देश में रोजगार के नये अवसर पैदा किये जायेंगे। एक बात उधर से कही गयी कि हमने शुरू से जिस आर्थिक नीति को देश में लागू किया, अपनाया था, जो दिशा हमनें पकड़ी थी और हम समझते थे कि इस नीति पर चलकर हम देश का विकास कर सकते है, साथ ही साथ देश के उत्पादन में वृद्धि भी कर सकते है, देश में रोजगार के साधन भी पैदा कर सकते हैं और दुनिया में जिस तरह से परिवर्तन हो रहे हैं, जो परिवर्तन की लहर हमें सारी दुनिया में दिखाई पड़ रही है, हमने देखा कि 40-50-60 साल तक एक नीति पर चलते हुए आज मुल्क में अपेक्षित उन्नति नहीं हो पायी है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही वर्तमान बजट को वित्त मंत्री जी ने यहां प्रस्तुत किया है।

इसलिए मैं समझता हूं कि हमारे जो भी विरोधी पक्ष के लोग हैं उनको हक है कि सरकार पर लांछन लगाएं और कटुतापूर्ण बाते करें। मैं उसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मैं यह समझता हूं कि भारत एक ऐसा देश है जिसके सामने कुछ मुद्दे है, कठिनाइयां है उनसे देश को बचाने के लिए, हम सब लोगों को एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से कुछ सुझाव देने चाहिए।

5.25 म.प.

(श्री तारासिंह पीठासीन हुए)

इसमें भारत का आर्थिक विकास और ढांचा मजबूत हो सके और इस देश के रहन-सहन में खुशहाली आ सके, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम सिर्फ डंकल और आई.एम.एफ. को देखते है और प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री के ऊपर लांछन लगाकर के हम सोचते है कि इससे शायद कुछ लाभ होगा, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम परिवर्तन के चौराहे पर खड़े है। इस बात को हम सबको बहुत अच्छे ढंग से सोचना पड़ेगा। हम जो कदम उठा रहे है इस कदम से देश के लोगों को किस तरह से लाभ पहुंचा सकते है, इस बात की ओर हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

आज हमारी ज्यादा से ज्यादा आलोचना वित्तीय घाटे के बढ़ने को लेकर हुई है। यह बात सही है कि वित्तीय घाटा बढ़ा है, यह बात भी सही है कि सबसिडी में 4 हजार करोड़ रूपए बढ़े है, यह बात भी सही

है कि डिफेंस में ढाई हजार करोड़ रूपए बढ़े है और कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देने के लिए ज्यादा रकम की व्यवस्था की गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज हमको एक बात को सामने रखना पड़ेगा कि भारतीय वित्तीय व्यवस्था को अगर सही करना है तो हम इस बात को भी ध्यान में रखें कि हमारे देश में दो प्रकार की व्यवस्था चल रही है- राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार और जब तक दोनों में सामंजस्य नहीं होगा तब तक कोई भी व्यवस्था अच्छी तरह से चल नही सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि केन्द्र सरकार का समर्थन राज्य सरकारें करें। आज स्थिति यह है कि किसी राज्य में किसी पार्टी की सरकार है किसी में किसी दूसरी पार्टी की तथा केन्द्र में भी अलग पार्टी की सरकार है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि एक नेशनल एजेंडा ऐसा बनाया जाए जिस पर हर पार्टी की सरकार काम करे और कोई मतभेद नहीं हो और उस नेशनल एजेंडे के ऊपर जब तक हम मिलकर कार्य नहीं करेंगे, तब तक व्यवस्था अच्छी नहीं हो सकती है। हमें मिल बैठकर हर पार्टी से उस नैशनल एजेंडे को अपना सकते है और एक राष्ट्रीय व्यवस्था को बना सकते है जिसमें आने वाले समय में सभी पक्षों के लोग उसको पूरा करने के लिए एक साथ सहमत होकर काम करना आरंभ करे तभी इससे लाभ उठा सकते है।

मुझे एक बात का अफसोस है कि कुछ राज्य सरकारे केन्द्रीय सरकार की बजट के ऊपर आलोचना करती हैं, लेकिन जब अपने राज्यों में विदेशी पूंजीपतियों को बुलाकर उनसे अपने प्रदेश में पूंजी लगवा कर उनके साथ कल-कारखाने लगा कर शाबाशी लेना चाहती है, तो यह डबल स्टैंडर्ड वाली बात नहीं होनी चाहिए। इस मामले में एक राष्ट्रीय व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सभी मिलकर इस पर काम कर सकें। वस्तुओं के दामों में वृद्धि हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि कहा जाए कि दाम नही बढ़े है तो यह गलत होगा। लेकिन आप यह सोचिए कि यदि कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए हम किसान को रैमुनरेटिव प्राइस नहीं देगे तो कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ेगा। भारत कृषि प्रधान देश है, उसकी अर्थव्यवस्था कृषि उत्पादन पर निर्भर करती है। आज भी हमारा उत्पादन दुनिया के ऐवरेज उत्पादन से बहुत कम है। हम उसमें वृद्धि कर सकते है लेकिन उसके लिए किसानों को रैमुनरेटिव प्राइस देना पड़ेगा। चावल, गेंहू, चीनी को खरीदने के लिए थोड़ा ज्यादा दाम देना पड़ेगा। विकासशील देश में आज भी उत्पादन बढ़ाने के लिए इनसैनटिव देने की जरूरत है।

कुछ लोग कहते है कि सरकारी खर्च कम होना चाहिए। मैं भी इस बात को मानता हूं कि नॉन-प्लान में सरकारी खर्च कम होना अच्छा है। लेकिन वह कैसे होगा। आप प्लान में जो भी खर्च करते हैं, डयूरेबल ऐसैट बनाते है, उसके साथ ही जो स्टाफ ऐप्वायंट करते हैं वह ट्रांसफर होकर नॉन-प्लान में चला जाता है। उसका को मेनटेनैंस वगैरह होगा वह भी देना पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि यदि प्लान का खर्चा कम होगा, तो विकास कम होगा विकास कम होगा तो जरूरी चीजें उपलब्ध नहीं होगी और लोगों को परेशानी होगी।

वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने पिछली उपलब्धियों को कनसीलिडेट करने की कोशिश की है। उनकी दिशा बिलकुल सही है कि रूरल डैवलपमैंट के लिए ज्यादा रूपया होना चाहिए और यह कांग्रेस पार्टी की नीति में है।

श्री शरद यादव नहीं है। उन्होंने गांधी जी की बात की। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ग्रामीण स्वराज के विकास के लिए वचनबद्ध है और सरकार ने उस दिशा में बजट पेश किया है। ज्यादा रूपया होता तो और अच्छा होता, यह हम सब मानते हैं। लेकिन हमारे पास उतनी रकम नहीं है, इतने रूपये में जितना दे सकते थे, दिया है।

ग्रामीण विकास के लिए जो रकम दी गई है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर-

बेस्ड, एग्रो-बेस्ड और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पर अधिक ध्यान देना चाहिए। मुझे श्री देवगौड़ा की बात सुनने का मौका मिला था। उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया। इस पर ज्यादा धनराशि आवंटित होनी चाहिए। इससे ज्यादा रोजगार पैदा होंगे, कृषि उत्पादन बढ़ेगा, हम इनका निर्यात करने की स्थिति में होंगे और विदेशी बाजार की प्रतियोगिता में खड़े हो सकेंगे।

आज चटर्जी साहब ने बहुत से आंकड़े देकर अपनी बात कही। मैं उनको बहुत मानता हूं। वह बहुत जानकारी रखते है। कभी-कभी उनसे जरूरत पड़ने पर जानकारी भी लेता हूं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब हम आजाद हुए थे तो हमारी आबादी लगभग 30 करोड़ थी और आज हमारी आबादी 89 करोड़ से अधिक तक पहुंच गई है। आबादी को कम करने के लिये हम प्रयत्न कर रहे है। चीन ने तो अपनी आबादी पर काबू पा लिया है। हमें इस तरफ और अधिक ध्यान देना चाहिए और लोगों की जरूरतों को पूरा करना चाहिये।

मैं विरोधी दल वालो से कहना चाहता हूं कि वह केवल बजट का विरोध ही न करे बल्कि इसमें जो अच्छे प्रावधान किये गये है, उनका भी स्वागत करें। हमें पार्टी लाइन से ऊपर उठकर अपनी बात कहनी चाहिए। राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के बीच में अच्छी मेल-मिलाप होना चाहिये। अगर यह नहीं होगा तो योजनाओं को ठीक ढंग से लागू नहीं कर पायेंगे।

स्माल सेविंस के लिये इंसेटिव देना बहुत जरूरी है। इसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। स्टील सैक्टर में एनॉमली को दूर करना चाहिए। अगर हम इस सेक्टर की तरफ ध्यान देंगे तो आने वाले समय में इसका अच्छा निर्यात कर सकेंगे। स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को सुविधाये और प्रोटैक्शन देना चाहिये। कस्टम ड्यूटी कम करने या समाप्त करने से हमारे देश के बने सामान मंहगें हो जायेंगे और बाहर के कम हो जायेंगे। यह देखने की आवश्यकता है।

आज सरकारी विभागों में जैसा काम चल रहा है, उसका देखतर बहुत दुख होता है। आज लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय में बहुत एफिशेसी है। अगर इसकी 25 परसेंट एफिशेसी दूसरे सरकारी विभागों में आ जाये तो भारत में सोना ही सोना हो जाये। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप यहां के कर्मचारियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करत हैं, यह भी देखने की आवश्यकता है। पांचवें पे कमिशन के बारे म. आपने निर्णय ले लिया है लेकिन आज तक उसका गठन नहीं हुआ है। वित्त मंत्री जी का जवाब तो अप्रैल में होगा। इसके पहले ही पे कमीशन के गठन की घोषणा होनी चाहिए।

छोटे-छोटे केन्द्र शासित इलाकों का इस बजट में कोई उल्लेख नहीं है। मेरा चुनाव क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह है। वहां के लोगों की यह मांग है कि इसे फ्री पोर्ट बनाया जाये। समुद्र का अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग यही से जाता है। अत: इसे फ्री पोर्ट बनाया जाये। इससे एक्सचैंकर में काफी सहायता मिल सकती है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां जो एक पैसेंजर जहाज था, उसको वहां से हटाकर हज के पैसेंजर्स को ले जाने के लिए लगा लिया। हज के पैसेंजर्स के लिए सुविधा देना भी जरूरी है, यह भी राष्ट्र का काम है, उसमें हमें एतराज नहीं है। लेकिन अंडमान निकोबार आइसलैंड की जनता समुद्र के बीच में रहती है और वह मेनलैंड से 800 नोटिकल माइल्स की दूरी पर है और यह सुविधा नहीं रहने से उनके आने जाने और खाने पीने के सामान को पहुंचाने की बहुत दिक्कत हो गई है। उनके लिए कौन सी व्यवस्था है, उसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा।

आज सारे केन्द्र शासित प्रदेशों की जनता को डैमोक्रेटिक राइट देने के बारे में भी हमें विचार करना पड़ेगा वहां भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए। अंडमान निकोबार द्वीप में हम असेम्बली की डिमांड करते है। विधानसभा वहां होनी चाहिए। वहां के लोगो के हाथ में वहां ताकत देनी चाहिए। आज आप हर जगह

देश में लोगों के हाथों में पंचायत लेविल तक ताकत देना चाहते है और दी भी है। किसी भी इलाके की जनसंख्या के आधार पर उनका लोकतांत्रिक अधिकार होना चाहिए, उनको उससे वंचित नहीं करना चाहिए।

इसी के साथ मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां प्लान में जो कुछ भी पोस्टे क्रिएट होगी, वह पोस्टे फाइनैंस मिनिस्ट्री की इजाजत से फिल-अप होगी। इससे क्या हो गया है कि आज 1000 से ज्यादा पोस्टे फिल-अप नहीं हो सकी। एक साल के अन्दर वह बैन में आ गई। बैन में आ जाने से आज हमारे बहुत सारे विभागों में काम नहीं हो सकता है। इससे एफीसिऐसी नहीं बढ़ सकती है और बजट का पैसा खर्च नहीं हो सकता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी पोस्टे बैन हो गई है, वह सारी पोस्टे एक बार एग्जम्पशन देकर भर दीजिए, जिससे कि वहां के लोग यह महसूस कर सके कि हम भी इस महान देश का एक हिस्सा है।

आज हम देखते हैं कि भारत का मैप निकलता है तो उसमें अंडमान निकोबार नहीं है तो यह नहीं होना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

प्रो० मुमताज अन्सारी (कोडरमा) : सभापति महोदय, हमारे कांग्रेस के मित्र श्री मनोरंजन भक्त द्वारा एक भाषण दिया गया है। वह प्राक्कलन समिति के सभापति रहे है और इसलिए उन्होंने बहुत सी वस्तुओं का आकलन किया है **(व्यवधान)** मुझे सब कुछ याद है, आप उस बारे में चिन्ता न करें।

महोदय, श्री भक्त ने अभी बताया है कि विपक्ष के माननीय सदस्य डा. मनमोहन सिंह की आलोचना कर रहे हैं, उनकी भर्त्सना भी कर रहे है और उन पर आरोप लगा रहे है। यह बिल्कुल बेबुनियाद तथा निराधार है। विपक्षी पीठ का चाहे कोई भी सदस्य हो वह डा. मनमोहन सिंह के विरूद्ध किसी तरह का व्यक्तिगत आरोप लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता तथा वह विपक्षी पार्टियों के सभी सदस्यों द्वारा सम्मानीय है। लेकिन वह जो भी सिद्धांत लाये है या उनके द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत मनमोहनो मिक्स हैं। नि:संदेह विपक्षी पार्टियों के सदस्य इसका विरोध करने के लिए मजबूर है क्योंकि यह गरीब व्यक्तियों के विरूद्ध जाता है, यह देश के किसानों के विरूद्ध है यह देश के युवाओं के विरूद्ध है। अत: स्वाभाविक ही विपक्षी दलों के सदस्य ऐसे मामलों का विरोध करेगें।

मैं मनोरंजन सिद्धांत को समझने में असमर्थ हूं या जो कुछ सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया है वह स्वत: ही एक गैर-योजनागत व्यय होगा। यह अर्थशास्त्र का एक स्थायी सिद्धांत है कि यदि एक बार योजना व्यय में वृद्धि होती है तो स्वाभाविक तौर पर कुछ परिसम्पतियों का सृजन होगा, देश का विकास होगा लोगों को रोजगार मिलेगा, सब का विकास होगा प्रत्येक क्षेत्र के लोगों को इस विकास के लाभ होंगे। लेकिन मैं अपने वरिष्ठ मित्र श्री मनोरंजन भक्त को समझने में समर्थ हूं जब उन्होंने अलग बात बताई। यहां भी, हम डा. मनमोहन सिंह के विचारों का तथा डा. मनमोहन सिंह द्वारा तैयार किए गए बजट का विरोध करते हैं।

प्रथमत: इसकी सारी बजटीय पवित्रता खो चुकी है। आप जरा इसे देखिये। संसद में बजट प्रस्तुत करने से पहले, उन्होंने बहुत सी आवश्यक वस्तुओं जैसे चावल, गेंहू, चीनी, पैट्रोल, डीजल आदि के मूल्यों में वृद्धि कर दी है, यह सब आवश्यक वस्तुएं है। यह एक स्थायी सिद्धांत है। यह बजट सत्र इस मूल कारण से बुलाया जाता है क्योंकि संसद में आय-व्यय का ब्यौरा या आकलन प्रस्तुत किया जाता है। देश का प्रत्येक व्यक्ति रेडियो, टेलीविजन तथा अखबार को ध्यान से पढ़ते व सुनते हैं तथा वे देश को वित्त मंत्री को या श्री मनमोहन

सिंह के भाषण की प्रत्येक पंक्ति ध्यान से देखना चाहते हैं कि उसमें क्या लिखा गया है और देश के लिए क्या किया गया है। अन्ततः वह अर्थव्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है या देश के अधिकांश लोगो पर इसका प्रतिकूल या अनुकूल प्रभाव पड़ता है।

संसद में इस बजट को प्रस्तुत करने से पूर्व, उन्होंने श्री मनोरंजन भक्त या इस सदन के किसी अन्य सदस्य की स्वीकृति लिये बिना आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि कर दी। यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है इससे बजट की पवित्रता का हनन हुआ है।

इसी तरह, आप देखिये उन्होंने लोक वित्त तथा पब्लिक अर्थशास्त्र के समूचे स्थायी सिद्धांतों में भी परिवर्तन कर दिया है। यह एक स्थायी सिद्धांत है कि जब कभी आप कर देते हैं तो आप को सभी विलासिता तथा आरामदायक वस्तुओं पर कर देना पड़ेगा। लेकिन यहां हम देखते हैं कि श्री मनमोहन सिंह ने अर्थशास्त्र का एक अलग रास्ता चुना है। उनका अर्थशास्त्र का एक अलग सिद्धांत है। उन्होंने जीवन की सभी आवश्यक वस्तुओं पर भारी कर लगाया है। उन्होंने विलासिता की वस्तुओं जैसे सौन्दर्य प्रसाधन, शैम्पू, लिपस्टिक, डिटर्जेंट, साबुन क्रीम तथा अन्य वस्तुओं को छोड़ दिया है। यह वस्तुएं इस देश के गरीब तथा आम लोगों द्वारा इस्तेमाल नहीं की जाती है। यह एक पश्चिमी स्टाइल है या जो भी स्टाइल कहा जाये यह उनका अपना स्टाइल हो सकता है। यह कांग्रेस का स्टाइल भी हो सकता है। अतः वे कांग्रेस स्टाइल में कार्य कर रहे हैं। अतः मैं अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र के समूचे सिद्धांत को समझने में असमर्थ हूं। सार्वजनिक वित्त के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है। कपड़े धोने की मशीन तथा इन सभी चीजों को छोड़ दिया गया है।

इस तरह यह एक गरीब विरोधी बजट है। गरीब व्यक्ति इन सब आवश्यक वस्तुओं जैसे चावल, गेंहू, पैट्रोल डीजल जैसी वस्तुओं का उपभोग करते हैं। इन सब का अधिकांश लोगों पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है उन पर भारी कर लगाया गया है। इन विलासिता तथा आरामदायक वस्तुओं को पूर्णतया छोड़ दिया गया है। अतः मैं वित्त मंत्री से या बैंकिग राज्य मंत्री में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या यह एक नया सिद्धांत है? क्या यह एक नई परिकल्पना है? आप इस देश के आम व्यक्ति से कैसे निपटना चाहते हो?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : आपको 'कांग्रेस संस्कृति' जैसे शब्दों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकालना होगा। वह लिपस्टिक की बात कर रहे हैं और अन्य ऐसी चीजों की बात कर रहे हैं। यह हमारी कांग्रेस संस्कृति नहीं है। अतः कृपया इन शब्दों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दीजिए। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया इस मुद्दे पर इतना ध्यान मत दीजिए। कृपया अपना भाषण जारी रखिए।

प्रो. मुमताज अन्सारी : मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं **(व्यवधान)** मैं यह अवश्य स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस की कोई संस्कृति नहीं है **(व्यवधान)** उनके पास कोई संस्कृति नहीं है। इसीलिए वह उस 'संस्कृति' का विरोध कर रही है। 'संस्कृति' कोई बुरी चीज नहीं है जो कुछ मैंने बताया है संस्कृति अच्छी हो सकती है। यह विभिन्न प्रकार की हो सकती है **(व्यवधान)** इसमें कांग्रेस संस्कृति हो सकती है।

सभापति महोदय : आप कृपया बजट के बारे में बात कीजिए।

प्रो. मुमताज अन्सारी : चावल, गेंहू, पैट्रोल तथा डीजल आदि वस्तुओं का गरीब व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है गरीब आदमी के लिए चीनी भी महंगी हो गई है। क्योंकि इस पर भारी कर लगाया गया है। इसी तरह, यह किसान विरोधी भी है। श्री मनोरंजन भक्त बता रहे थे कि कृषि क्षेत्र में भारी निवेश किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें कितना निवेश किया गया है? बजटीय प्रावधान के दौरान, केवल 87 करोड़ रूपये की धनराशि की वृद्धि की गई है। मेरे विचार से, वर्ष 1993-94 के दौरान यह 1950 करोड़ रूपये

थी। अब इसमें केवल सीमान्त वृद्धि की गई हे अर्थात् इस बढ़ाकर 2500 करोड़ रूपये किया गया है। कृषि के लिए यह बजटीय प्रावधान है। आप यह देखिए कि यह केवल कृषि के लिए भी नहीं है सिंचाई, पशुपालन के लिए भी इसमें काफी कटौती की गई है। यह बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। सिंचाई को कृषि का जीवन रक्त कहा जाता है। आप उसमें वृद्धि नहीं कर रहे हैं। बल्कि आप उसमें कटौती कर रहे हैं। अत: यह काफी खतरनाक है क्योंकि यह गरीब विरोधी किसान विरोधी तथा जनता विरोधी है। इसे राष्ट्र विरोधी भी कहा जा सकता है। इसमें संदेह नहीं है कि वित्त मंत्री हमारे देश के प्रति काफी वफादार निष्ठावान, समर्पित तथा ईमानदार है लेकिन जो बजटीय प्रावधान किए गए है उनसे वह राष्ट्र विरोधी लगते हैं। मैं इसे सिद्ध भी कर सकता हूं।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्र विरोधी से उनका क्या अभिप्राय है।

सभापति महोदय : मैं अपनी जिम्मेदारी जानता हूं कि कार्यवाही वृत्तांत से क्या निकाला जाना चाहिए और क्या नहीं आप व्यवधान मत डालिए।

प्रो. मुमताज अन्सारी : महोदय, मैं उन्हें एक व्यक्ति के रूप में कुछ नही बता रहा हूं। मैं बजटीय प्रावधानों की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं उनके बजटीय प्रावधान राष्ट्र विरोधी हैं।

श्री उमराव सिंह : महोदय, वह एक सदस्य के रूप में उनका जिक्र कर रहे है और बजट का नहीं।

सभापति महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

(व्यवधान)

प्रो. मुमताज अंसारी : महोदय, वह एक बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति है। **(व्यवधान)**

श्री उमराव सिंह : उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में एक व्यक्ति के बारे में कहा है। इसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : उन्होंने मंत्री के बारे में नहीं कहा है। मैं यह जानता हूं।

प्रो. मुमताज अंसारी : महोदय, मैं व्यक्ति के विरुद्ध कुछ कह रहा हूं। लेकिन यदि आप बजटीय प्रावधानों को देखें तो आप पायेंगे कि विदेशी शक्तियों जैसे डंकल या उरूग्वे टेबल कांन्फ्रेस या "गैट" समझौता या अन्य देश के बाहर बैठे शासकों के आदेश पर बजटीय प्रावधानों का निर्धारण किया गया है। उन्होंने आदेश दिये होंगे या किसी प्रकार के निर्देश दिए होंगे और उनके आदेश पर उन्होंने इस प्रकार के प्रावधान किये है। आप देख सकते हैं कि डा. मनमोहन सिंह केवल एक वाकपटु विवरण दे रहे थे कि कम राजस्व घाटा होना चाहिए। लेकिन मैंने पाया है कि एक दिन वह स्वीकार कर रहे हैं कि कहीं अधिक वित्तीय घाटा होना चाहिए।

यदि आप सभी प्रावधानों का अध्ययन करें, तो आपको पता चल सकता है कि वर्ष 1985 से 2.7 प्रतिशत राजस्व घाटा था, लेकिन, इस बजट के दौरान, यह घाटा 4.3% तक पहुंच गया है। इसलिए हमारी स्थिति क्या है। इसके पहले, आप बता रहे थे कि यह बहुत खतरनाक और संकटपूर्ण स्थिति थी और हम जिस भी मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं वह खतरनाक है। लेकिन एक दिन आप कहते हैं कि वित्तीय घाटा ही अच्छी चीज है। अर्थव्यवस्था के लिए जो कुछ भी पहले खतरनाक थी, अब वह अर्थव्यवस्था के हित में और देश के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण उपकरण साबित हो रहा है। आपने किस प्रकार का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। मैं समझता हूं कि यह सब इसलिए है कि यह चुनाव वर्ष है और आपने कई एजेंसियों और कई मदों

पर अनिवार्य खर्च आरंभ कर दिया है। यही कारण है कि आप घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा ला रहे हैं।

अब, आप कहते हैं कि घाटे की अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी है। अर्थशास्त्र का छात्र होने के नाते, मैं भी सहमत हूं कि आप घाटे की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से अस्वीकार अथवा समाप्त नहीं कर सकते है। लेकिन कुछ निवारक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है अब आप कह रहे हे कि परिस्थितियों में परिवर्तन हो चुका है। परिस्थितियों में किस तरह का परिवर्तन हुआ है। आप कहते है कि खाद्यानों का 23 मिलियन टन का विशाल भंडार है, विदेशी मुद्रा का 13 विलियन डालर का भंडार है और अन्य परिस्थितियां भी अनूकुल है। यही कारण है कि आपने घाटे की अर्थव्यवस्था का आश्रय लिया है। लेकिन, इसके साथ ही कुछ एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए। जैसा कि श्री मनोरंजन भक्त जी ने पहले ही उल्लेख किया है कि गैर योजना व्यय में काफी कटौती की जानी चाहिए मेरा भी दृढ़ विचार है कि जब तक इस वित्तीय घाटे के व्यय का उत्पादकतापूर्ण इस्तेमाल नहीं होता तब तक आपके प्रयास सफल नहीं होंगे और विकास का लाभ देश की सामान्य जनता तक नहीं पहुंच पाएगा।

आपने विभिन्न कार्यवाही शुरू की है। आपने एक ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित किया है जिससे आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको किंस के एक सुस्थापित सिद्धांत का स्मरण कराता हूं, जो प्रख्यात अर्थशास्त्री थे। उन्होंने प्रतिपादित किया था कि बाजार में मांग होनी चाहिए जिससे अधिक रोजगार उत्पन्न होगा और अधिक रोजगार से मांगे और भी बढ़ेगी और इसके माध्यम से राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। अब हम देखते हैं कि आप आपूर्ति के पक्ष को बढ़ावा दे रहे हैं। आप कहते हैं कि उत्पादन होना चाहिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने देश में आने दीजिए, विदेशी से पूंजी को आने दीजिए। विदेशों से ऋण भी आने दीजिए।

यह क्या है? आप मांग वाले पक्ष पर समान बल नहीं दे रहे हैं। आपको यह अवश्य स्मरण करना चाहिए कि इस तरह के सिद्धांत जिसे आप इस देश में अब प्रतिपादित कर रहे हैं, उस सिद्धांत पर अन्य देशों में पहले ही प्रयोग हो चुके है और इसे अस्वीकार किया जा चुका है। चाहे यह थैचर की सरकार हो या अमेरिकी अर्थव्यवस्था हो या ब्रिटिश अर्थव्यवस्था हो, इस पर प्रयोग पहले ही हो चुका है और इसे अस्वीकार किया जा चुका है। अब इस पर पुन: प्रयोग करने की क्या आवश्यकता है और वह भी हमारे देश में जो एक गरीब देश है और मुख्यत: कृषि प्रधान देश है। मैं इस तर्काधार को समझने में असफल हूं। यही कारण है कि मैं पुन: दोहराता हूं कि जिस सिद्धांत पर यह बजट निर्भर है वह तुच्छ और अर्थहीन है। इस तरह के सिद्धांत पर पहले ही प्रयोग हो चुके है और इसे कूड़े के ढेर में डाल दिया गया है।

इसी प्रकार ऋण स्थिति देखिए अब आप ऋण चुकाने के लिए ऋण ले रहे है। ब्याज के भुगतान के लिए ऋण ले रहे हैं। यह है क्या? आप ऋण के जाल में फंसते जा रहे हैं। आप कह सकते हैं कि अगर आप एक बार ऋण के भार से मुक्त हो जाते हैं, तो सब ठीक जो जायेगा। ऐसा नहीं हो सकता। अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। आप पहले से ही ऋण के जाल में फंस चुके हैं और जब तक आप वास्तव में इससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते व तब तक यह पूरा देश ऋण में डूबता चला जाएगा और हमें कोई बचा नहीं सकता। ऋण पर केवल ब्याज ही 470 बिलियन तक पहुंच गया है। वर्ष 1993-94 में सिर्फ ब्याज ही 376 विलियन था और अब भी इसमें वृद्धि होती ही जा रही है। इसके अतिरिक्त, आप अब भी ऋण ले रहे हैं। आप एक उज्जवल पहलू के बारे में प्रसन्न महसूस कर रहे हैं। आपने उल्लेख किया है कि आप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण का 1.7 विलियन डालर पहले ही भुगतान करने जा रहे हैं। लेकिन हमारे कुल ऋण को देखते हुए, यह बहुत की कम राशि है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय

मुद्रा कोष का और अन्य धनी देशों से हमने जितनी धनराशि ली है वह बहुत अधिक है। जब तक आप यह ऋण बंद नहीं करते तब तक आप ऋण के जाल से बच नहीं सकते।

मैं श्री शरद यादव जी द्वारा अपने भाषण में उठाए गए मुद्दे से सहमत हूं। जो सिद्धांत सरकार द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं और जिस मार्ग पर हम चल रहे है उसके लिए किसी भी सदस्य द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई। हमारी सरकार ने एक सिदांत प्रतिपादित किया कि हमें आत्म निर्भर बनने और अपने पांवों पर खड़े होने का प्रयास करना चाहिए। हमारी सरकार हमारे लोगों की आवश्यकताओं को अपने सीमित संसाधनों से ही पूरा करने की कोशिश करती रही है।

आपकी अनुमति से मैं वित्त राज्य मंत्री को स्मरण कराना चाहता हूं कि उन्हें भी पर्याप्त मौका मिला है। अब आपने सीमा शुल्क के सम्बन्ध में छूट दी है। इसके पीछे तर्क क्या है ? आप इस्पात, कम्प्यूटर, कोयला, पैट्रोल और चमड़ा की वस्तुओं के आयात हेतु छूट दे रहे हैं। इस तरह हमारे उद्योंगो की क्या स्थिति होगी। रांची में हमारे भारी इंजीनियरिंग कंपनी का क्या हो रहा है, उसी प्रकार, हजारों कंपनियां जो उपभोक्ता उत्पाद का उत्पादन न करके पूंजीगत उत्पाद का उत्पादन कर रही हैं बाजार के अभाव में विनक्षत होती जा रही है और समाप्त होती जा रही है। आप हमारे पूंजीगत उत्पाद वाले उद्योग को प्रोत्साहन देने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ आज जापान, अमेरिका, इंग्लैण्ड, जर्मनी आदि से सभी पूंजीगत उत्पाद आयात कर रहे हैं ? यह क्या है? आप इस दु:खद स्थिति का उपहास कर रहें है ?

मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोडरम में हिरोदी नामक स्थान पर एक कंपनी है जो विदेशों के लिए बड़ी संख्या में पाईपें बनाने का काम करती थी। अब यह कंपनी भी नष्ट हो रही है। आप अपने पूंजीगत उत्पाद उद्योग की और भी ध्यान नहीं दे रहे हैं लेकिन आप विश्वीकरण, उदारीकरण के नाम पर महिमा मंडित शब्दों के नाम पर आप आयात करना चाहते हैं। इन शब्दो को आपने अपने संतोष के लिए तथा विदेशी निर्यातकों के संतोष के लिए बनाया है। यदि एक बार आप चमड़ा उत्पाद, इस्पात कम्पयूटर आदि के नाम पर आयात के दरवाजे खोलना चाहते हैं तो कोई भी हमारे देश को बचा नही सकता। हमारे देश में कम्प्यूटीकरण की क्या आवश्यकता है जहां करोड़ो युवक सड़कों पर बेरोजगार मारे-मारे फिर रहे हैं और जो अपने नाम रोजगार कार्यालयों में भी दर्ज करा पाने में भी सक्षम नहीं है? और इस स्थिति में आप कम्प्यूटरीकरण की बात करते हैं। आप चमड़े उत्पाद के आयात का ही मामला लीजिए। चमड़े का उद्योग निर्याती-मुखी है और रोजगार के अवसर उत्पन्न करने वाला है। लेकिन आप हमारे उद्योग को नष्ट करना चाहते हैं और वह भी चमड़ा उत्पादों के आयात के लिए छूट के नाम पर।

सभापति महोदय : मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। क्या हम सदन की कार्यवाही 6 बजे शाम को स्थगित कर दें या 8 बजे तक जारी रखें

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : उनके भाषण के समाप्त होने पर सभा स्थगित कर दें।

सभापति : हम प्रो० अंसारी जी के भाषण के समाप्त होने तक सभा का समय बढ़ा देंगे। कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

प्रो० मुमताज अंसारी : मुझे सरकार को सुझाव देने है। कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए।

यह ऐसी स्थिति है जिसमें हमें रख दिया गया है। हम लोग कम से कम श्रेणी के लोग हैं। लेकिन हमारे कृषक समुदाय के विषय में गरीब किसानों, भूमिहीन मजदूरों, दैनिक मजदूरों के विषय में सोचें। आपने उनके लिए क्या किया है। मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि श्री मनमोहन सिंह के बजट ने समाज के धनाढ़्य वर्गों के लिए रंगीन तस्वीर पेश की है। यह कहा जाता है कि जो विदेश में भ्रमण करना चाहते

हैं उनके लिए विदेशी मुद्रा जारी कर दी जाएगी। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति के लिए इस प्रावधान का क्या औचित्य है तो देश में भी यात्रा करने का सपना नहीं देख सकता? यही तो आप उदारीकरण के नाम पर कर रहे हैं। आयकर छूट सीमा के प्रावधानों का भी यही मामला है। इस छूट से वैतनिक लोगों तथा गरीब लोगों को कभी सहायता नहीं मिली है।

6.00 म.प.

इनका पक्ष नहीं लिया गया है आपने आयकर की निजी छूट सीमा को बढ़ा कर 5,000 तक कर दिया है। यह कराधान की ऊपरी सीमा है और निगमित क्षेत्र को आपने अनेक छूटें दी हैं। इसलिए, आपने वैतनिक लोगों को छूट दी है और वह भी 5,000 रू तक की राशि तक ही। यह 5,000 की छूट मुद्रा स्फीति के बढ़ते दबाव में निष्फल साबित होगी। हमने अभी मुद्रा स्फीति की दर को 17 प्रतिशत से घटाकर 8.5 प्रतिशत तक किया है। लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं आपने अपने तरीके अपना स्तर प्रतिपादित कर दिए है। लेकिन इन सभा से मैं सम्बद्ध नहीं हूं। परन्तु जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जायेगें तो आपको गरीब लोगों की वास्तविक स्थिति देखने को मिलेगी। आप फुटकर बाजारों में जायें, तो आप देखेंगे कि इन सभी आवश्यक वस्तुओं की क्या स्थिति है। आप लोगों की समस्याओं को नहीं समझ सकते, क्योंकि आप सत्ता पक्ष में बैठे हैं और सभी लाभ उठा रहे हैं। अतः आप कभी भी यह दावा नहीं कर सकते अथवा अपनी शेखी नहीं बघार सकते कि आपने मुद्रा स्फीति की दर को 17 प्रतिशत से घटाकर 8.5 प्रतिशत कर दिया है। आपने यह सभी जानकारी, ये सभी आंकड़े थोक बाजार से एकत्रित किये हैं जिनकी संगणना आपके इशारे पर की गई थी। आपने वह जानकारी प्राप्त कर ली होगी तो आपके अपने ही अधिकारियों द्वारा तैयार की गई थी। परन्तु यह वास्तविक स्थिति नहीं है। मुद्रा स्फीति की सियति है। कीमतें अत्याधिक तेजी से बढ़ रही हैं। कीमतें गरीब लोगों और किसानों के जीवन स्तर पर अत्याधिक प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है।

इसी प्रकार से आपने निगमित क्षेत्र को रियायतें दी हैं। आपने निगमित क्षेत्र के लिए दर को कम करके 45 प्रतिशत कर दिया है। अतः आपने निगमित क्षेत्र को जो छूट दी है वह 2500 करोड़ रूपये के आसपास है। यह रियायत व्यक्तियों के लिए नहीं है। यह छोटे व्यापारों, व्यवसायों और कारोबार के लिए नहीं है। इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि यह गरीबों के विरूद्ध हैं, यह आम आदमी के विरूद्ध है ; यह मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के विरूद्ध है ; यह वेतन भोगी वर्ग के व्यक्तियों के विरूद्ध है ; और यह मंजूरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध है।

इसलिए, मैं कहना चाहता हूं कि आप यहां हैं और आपने इस प्रकार का बजट तैयार किया है, आपको यह सुनिश्चित करना है कि सरकार का खर्च केवल योजनाबद्ध खर्च हो और कि इसे उत्पादक कार्यो में प्रयोग किया जाए। तभी अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकता है।

इसी प्रकार, यदि आप अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार करना चाहते हैं, तो आपको उन सभी रियायतों को वापस लेना होगा जो आपने सीमा शुल्क, आयात शुल्क आदि के रूप में दे रखी हैं और जो 2300 करोड़ रूपये के बराबर हैं। आपने निगतिम क्षेत्र के लिए 2500 करोड़ रूपये तक की रियायतें दे रखी है। आप उन सभी रियायतों को वापस लें। आप रोजगार, शिक्षा, कल्याण- हरिजन और आदिवासी कल्याण जैसे विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों और रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों में धन खर्च करें। उस स्थिति में यह बजट काफी कारगर सिद्ध हो सकता है। अन्यथा यह बजट निश्चित रूप से असफल होगा। यह बजट आम व्यक्ति के लिए हताशा पैदा करने वाला होगा।

यह बजट निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में भी सभी प्रकार की अव्यवस्था

और भ्रम उत्पन्न करेगा। इसी कारण मैं इन सभी महत्वपूर्ण उपायों का सुझाव दे रहा हूं जिन्हें कार्यरूप दिया जाना चाहिए।

आप लाल किले के प्राचीर से 10 लाख युवकों को रोजगार देने जैसे जो बड़े-बड़े वायदे कर रहे हैं, वे सभी युवा विरोधी हैं। इसी कारण से मैंने ये सभी चीजें स्पष्ट की हैं। ये परियोजनाएं पूरी तरह से युवा पीढ़ी के विरूद्ध हैं। आपने कम से कम 10 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने का वायदा किया है ; आपने धन उपलब्ध कराने का वायदा किया है ; आपने वैकल्पिक तरीके आदि उपलब्ध कराने का वायदा किया है। परन्तु हो क्या रहा है ? आपने 10 लाख युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केवल 145 करोड़ रूपये की धनराशि उपलब्ध की हैं। आप गणना कीजिए कि प्रति व्यक्ति कितनी रकम उपलब्ध होगी। यह राशि प्रति युवक अथवा बेरोजगार स्नातक या बेरोजगार स्नातकोत्तर व्यक्ति के लिए 1450 रूपये होगी। अतः यह अत्याधिक कम राशि है। इस समिति धनराशि से किस प्रकार की परियोजनाओं का निर्माण या स्थापना की जायेगी आकर युवकों को किस प्रकार का व्यवसाय और रोजगार प्राप्त होगा ? व्यक्ति कैसे अपना जीवन यापन करेंगे ? अतः ये चीजें है जिनके लिए आपने वायदा किया है।...........**(व्यवधान)**.........

श्री उमराव सिंह : वे यहां जो कुछ कह रहे हैं उसे दस्तावेजों के साथ प्रमाणित करें। उन्होंने एक भी दस्तावेज नहीं पढ़ा है।

[हिन्दी]

श्री राजेश कुमार (गया) : चेयरमैन साहब, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय सदस्य बोलते है तो वे बार-बार टोक रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनको माननीय सदस्य की बात समझ में नहीं आ रही हैं।

सभापति महोदय : दरअसल, यह तो श्री नीतीश कुमार ने बता दिया कि टोका-टोकी होनी चाहियें। मैं तो कल इस बात के हक में नहीं था।

[अनुवाद]

श्री मुमताज अंसारी : इसी प्रकार, इन सभी उद्योगों और कुटीर उद्योगों की भी पूरी तरह से उपेक्षा की गई है। आपने इन सभी लघु उद्योगों पर उत्पाद शुल्क लगा दिया है। उसके पीछे क्या तर्क है? अभी तक ये सभी लघु उद्योग इन सभी उत्पाद शुल्कों से मुक्त थे, अब आप उत्पाद शुल्क लगाने के नाम पर पुन इंस्पैक्टर राज लादने का प्रयास कर रहे हैं। आप पुनः इन सभी निरीक्षकों को नियुक्त करने जा रहे हैं और वे लघु उद्योगों के दरवाजे खटखटायेंगे। वे विभिन्न चीजों की गणना अथवा अनुचित गणना करेंगे और ये सभी छोटे तथा बेरोजगार व्यक्ति काफी परेशानी में पड़ जायेंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय जी को स्मरण कराना चाहता हूं कि यह लघु क्षेत्र कीमत की दृष्टि से कुल औद्योगिक उत्पादन का 35 प्रतिशत उत्पादन करता हैं। इसीं प्रकार से यह देश के कुल निर्यात का 30 प्रतिशत तक निर्यात करते हैं।

इसी प्रकार, यह देश के कुल औद्योगिक विकास का 5.8 प्रतिशत है जबकि इसे यहां औद्योगिक विकास का 1.8 प्रतिशत बताया गया है। इसलिए, यह सभी सांख्यिकीय जानकारी है; आपके सामने यह स्थिति है उसके बावजूद आप ऐसे लघु उद्योग क्षेत्र पर उत्पाद शुल्क लगा रहे हैं जो कि अत्यधिक रोजगारोन्मुख क्षेत्र है। इसी प्रकार से, कुटीर उद्योग और विद्युत करघा तथा हथकरघा क्षेत्रों, जिनमें वृहत रोजगार के अवसर हैं, पर बुरी तरह कर लगाये गये हैं। इसलिए, उस क्षेत्र के बारे में नहीं सोचते जो रोजगार प्रदान करता है; आप विद्युत क्षेत्र, रोजगारोन्मुख क्षेत्र और कुटीर उद्योग पर सभी प्रकार के बंधन लगाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वभाविक रूप से यह बजट लघु क्षेत्र विरोधी, जन विरोधी और रोजगार कार्यक्रम विरोधी हैं।

यदि आप अर्थव्यवस्था की बेहतर स्थिति करना चाहते हैं तो आपको उन सभी उपायों को कार्यान्वित करना होगा जो लघु क्षेत्र की स्थिति का सुधार करेंगे और यह घोषणा करनी होगी कि सरकार सभी उत्पाद शुल्क वापस ले रही है जो लघु क्षेत्र पर लगाया गया है क्योंकि अनेक प्रतिनिधि मंडल, व्यक्तियों के अनेक वर्ग, लघु क्षेत्र के अनेक वर्ग संसद सदस्यों के समक्ष निवेदन कर रहे हैं कि यह अत्यधिक भ्रमपूर्ण स्थिति है जो इस देश की सरकार द्वारा उत्पन्न की गई है। इससे पूर्व यह आशा नहीं थी कि यह सरकार इस हद तक समाज के छोटे वर्ग का शोषण करेगी।

देश के सभी किसानों की ओर से देश के गरीब लोगों की ओर से, देश के श्रमजीवी वर्ग की ओर से, देश के किसानों और कृषि श्रमिकों की ओर से तथा अपने देश वासियों की और से मैं इस बजट का पूर्ण शक्ति से पुरजोर विरोध करता हूं। यदि हम यहां सफल नहीं होते हैं तो हम जनता के समक्ष जायेंगे और उन्हें इस बजट के प्रावधानों के विरूद्ध प्रेरित करेंगे।

[हिन्दी]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): सभापति जी, बिजिनैस एडवाइजरी कमेटी ने प्रतिदिन 8.00 बजे तक बैठने का फैसला किया है इसलिए 8.00 बजे तक हाउस को चलाया जाये ताकि कुछ और माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिल सके।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : चूंकि आज मंत्री महोदय की और से कोई उत्तर नहीं दिया जायेगा अत: देर तक बैठने का कोई औचित्य नहीं है।

सभापति महोदय : मुझे उपाध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया था कि मैं देर तक बैठने के बारे में सभा की सहमति प्राप्त करूं। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि सभा 8 म.प. तक बैठे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम सभा को स्थगित करते हैं।

सभापति महोदय : सभा मंगलवार, 29 मार्च, 1994 को 11 म.पू. पर पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.13 म.प.

तत्पश्चात् सभा मंगलवार, 29 मार्च, 1994/8 चैत्र,

1916 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी० एल० एस०—48/29/17/94 (एन०)

250

© 1994 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य सचालन नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक, सनलाईट प्रिंटर्स, 2265 डा० सेन मार्ग, दिल्ली-11006 द्वारा मुद्रित ।